सत्यमेव जयते

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

सत्यमेव जयते

पर्यटन मंत्रालय

भारत सरकार

जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा

अनुक्रमणिका

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

01	पर्यटन-एक सिंहावलोकन	7
02	पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और उसके कार्य	15
03	गंतव्य विकास	25
04	कार्यनीति एवं उत्पाद विकास	71
05	विपणन एवं संवर्धन	79
06	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	93
07	अनुसंधान एवं विश्लेषिकी	107
08	सुविधा एवं मानक	115
09	कौशल एवं क्षमता निर्माण	129
10	प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग	139

ताजमहल, आगरा

01 पर्यटन – सिंहावलोकन

1.1 आर्थिक पावरहाउस के रूप में पर्यटन क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव और विकास के साधन के रूप में इसकी क्षमता अकाट्य है। पर्यटन क्षेत्र न सिर्फ विकास की अगुवाई करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित करने की अपनी क्षमता के साथ लोगों के जीवन में भी सुधार लाता है। यह पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करता है, विविध सांस्कृतिक विरासत की हिमायत करता है और दुनिया में शांति को सुदृढ़ बनाता है।

1.2 पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को मजबूत बनाना और सुगमता प्रदान करना है। भारत में पर्यटन को बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में वृद्धि करना, वीजा व्यवस्था को सरल बनाना, पर्यटन सेवाप्रदाताओं की सेवाओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना, पूरे वर्ष के अनुकूल पर्यटक गंतव्य के रूप में देश को प्रदर्शित करना, स्थायी पर्यटन का संवर्धन आदि कुछ ऐसे नीतिगत क्षेत्र हैं, जिन पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ाया और सुगम बनाया जा सके ।

1.3 घरेलू पर्यटन के साथ-साथ आगमन (इनबाउंड) पर्यटन आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक तत्व बनकर उभरा है। वर्ष 2025 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफ़टीए) की संख्या 9.02 मिलियन (अनंतिम) दर्ज की गई, जिससे विदेशी मुद्रा आय (एफ़ईई) के रूप वर्ष 2025 में 2,73,638 करोड़ रुपये (अनंतिम अनुमान) दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों तथा पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य सूचनाओं के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान देश भर में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) की संख्या 4132.8 मिलियन (अनंतिम अनुमान) रही।

1.4 रोजगार पर उल्लेखनीय प्रभाव के साथ पर्यटन क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाले आर्थिक क्षेत्रों में से एक है और यह संबंधित क्षेत्रों के कार्यकलापों पर गुणक प्रभाव के साथ क्षेत्रीय विकास को गति देता है। आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों में घरेलू पर्यटन, पर्यटन के विकास का बड़ा कारक बन गया है। यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संसाधन जुटा सकता है और इसमें सतत विकास के लक्ष्यों में सकारात्मक योगदान देने की बड़ी क्षमता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन, तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) के अनुसार, 2023-24 के दौरान भारत में पर्यटन से जुड़ी नौकरियों का अनुमानित हिस्सा 13.34 प्रतिशत है। पर्यटन क्षेत्र भारत की जीडीपी में 5.22 प्रतिशत का योगदान देता है, जो देश के आर्थिक विकास में इसके महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

1.5 पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में पर्यटन सुविधाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में सहायता के लिए वर्ष 2014-15 में 'स्वदेश दर्शन नामक फ्लैगशिप योजना की शुरूआत की थी और अब तक 76 परियोजनाओं के लिए 5290.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 75 परियोजनाओं के भौतिक रूप से पूरा होने की सूचना है।

1.6 राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 29 परियोजनाओं और 2024-25 के दौरान 19 परियोजनाओं तथा 2025-26 में 5 और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

1.7 पर्यटन मंत्रालय ने ऐतिहासिक स्थलों और विरासत शहरों सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए प्रशाद याजना – तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान की शुरूआत की थी। योजना के तहत, मंत्रालय ने कुल 1726.74 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और 31 दिसंबर, 2025 तक 1200.47 करोड़ रुपये संचयी रूप से जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रशाद योजना के तहत विकास के लिए 12 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करते हुए 16 नए स्थल भी चिह्नित किए गए हैं।

1.8 पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन की पहल मौसम के प्रभाव से निपटने तथा भारत को पूरे वर्ष के अनुकूल रहने वाले गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और उन अनोखे उत्पादों, जिनमें भारत को तुलनात्मक बढ़त प्राप्त है, के लिए पर्यटकों का बार-बार आगमन सुनिश्चित करने के लिए है। विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित किया गया है: साहसिक पर्यटन, बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई), सतत पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, चिकित्सा और निरोगता पर्यटन, इको पर्यटन, गोल्फ और क्रूज पर्यटन।

1.9 पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी: पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की। इस पहल के लिए कुल 7 पर्यटन स्थलों को चिह्नित किया गया, जिसमे - ओरछा (मध्य प्रदेश), गांडीकोटा (आंध्र प्रदेश) बोधगया (बिहार), आइजोल (मिजोरम), जोधपुर (राजस्थान), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और श्री विजय पुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) शामिल हैं।

1.10 अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल एक पर्यटन-केंद्रित, एक-स्टॉप डिजिटल समाधान है, जिसे भारत आने वाले यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह नवीकृत पोर्टल यात्रियों को खोज और अनुसंधान से लेकर नियोजन, बुकिंग, यात्रा और वापसी तक की उनकी यात्रा के हर चरण में आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है। यह नया पोर्टल वीडियो, चित्र और डिजिटल मानचित्र जैसी मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करते हुए, गंतव्यों, आकर्षणों, शिल्पकला, त्यौहारों, यात्रा डायरियों, यात्रा कार्यक्रमों आदि के बारे में भरपूर जानकारी प्रदान करता है।

1.11 पर्यटन संवर्धन: प्रमुख कार्यक्रम और पहल मंत्रालय - पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन विविधता को प्रदर्शित करने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और प्रचार संबंधी पहलों की शुरुआत की।

1.12 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित महाकुंभ 2025 का एक अतुल्य भारत मंडप की स्थापना, भारतीय मिशनों और भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से संवर्धनात्मक क्रिएटिव का प्रचार-प्रसार, एक बहुभाषी कुंभ पर्यटक

इन्फोलाइन का संचालन, ट्रैवल इंफ्लुएंसर के साथ सहयोग, आईटीडीसी द्वारा विकसित लक्जरी टेंट सुविधाओं सहित विशेष टूर पैकेजों और आवास विकल्पों के डिजिटल प्रचार-प्रसार के माध्यम से एक प्रमुख पर्यटन मंच के रूप में लाभ उठाया गया।

1.13 गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 26 से 31 जनवरी 2025 तक भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन, गणतंत्र दिवस परेड झांकी, 26 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी, देखो अपना देश अनुभवात्मक क्षेत्र और क्षेत्रीय व्यंजनों और शिल्पों की व्यापक प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया और इसमें लगभग 4.22 लाख आगंतुकों ने भाग लिया।

1.14 भारत को एक बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फिक्की के सहयोग से जयपुर में 14वें ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाज़ार (जीआईटीबी) 2025 के मौके पर भारत में मीट इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें एमआईसीई क्षेत्र में अवसरों, तैयारियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

1.15 सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस – भारत पर्व 2025 का आयोजन 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया गया। भारत पर्व की तर्ज पर और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक अतुल्य भारत थीम मंडप, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन मंडप और अखिल भारतीय खाद्य प्रदर्शन शामिल थे।

1.16 13वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) 2025, जो 13 से 16 नवंबर 2025 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई थी, ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर किया। लगभग 19 देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों और खरीदारों सहित 500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, इस कार्यक्रम ने बी2बी इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान की और रिवर क्रूज, वन्यजीवन, संस्कृति, होमस्टेज, स्थिरता और साहसिक पर्यटन जैसे विषयों में सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित किया।

1.17 विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की पुष्टि के लिए यह मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, होटलों को रेटिंग प्रदान की जाती है जैसे वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या उसके बिना फोर स्टार और फाइव स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग के एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस की स्थापना की है जो प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण को सुगम बनाना और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है और अधिक समावेशी बनाने के लिए इस पहल को निधि+ के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाइयों (एयर कैटरिंग और स्टैंडअलोन रेस्तरां), ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स और कन्वेंशन सेंटर को भी इसमें शामिल किया जा सके।

1.18 इनबाउंड पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा व्यवस्था पहली आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पहल करता है। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-वीज़ा सुविधा 172 देशों के नागरिकों को 33 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 16 प्रमुख भारतीय समुद्री पत्तनों और 2 भू- पत्तनों के माध्यम से प्रवेश के लिए प्रदान की गई है।

1.19 उप श्रेणियों यानी ई-पर्यटक वीजा (30 दिन /1 वर्ष /5 वर्ष के लिए), ई-व्यवसाय वीजा, ई-चिकित्सा वीजा, ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा, ई-सम्मेलन वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष सहयोगी वीजा, ई-स्टूडेंट वीज़ा और ई- स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा, ई-ट्रांजिट वीजा, ई-पर्वतारोहण वीजा, ई-फिल्म वीजा, ई-एंट्री वीजा और ई-प्रोडक्शन निवेश वीजा की सुविधा प्रदान की गई है।

1.20 ई-वीजा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। एक विदेशी नागरिक कहीं से भी ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकता है। ई-वीजा शुरू करने से पर्यटन, व्यवसाय और चिकित्सा उद्देश्यों आदि जैसे वैध उद्देश्यों के लिए भारत में विदेशियों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करने में मदद मिली है।

1.21 पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 8 फरवरी, 2016 को हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी टोल फ्री पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की है। पर्यटक हेल्पलाइन द्वारा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगीज, रसियन और स्पेनिश में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवा टॉल फ्री नम्बर 1800-11-1363 अथवा लघु कोड 1363 पर उपलब्ध है और निर्दिष्ट भाषाओं में ''बहु-भाषी हेल्प-डेस्क'' के रूप में वर्ष में 24x7 (सभी दिन) प्रचालनरत है।

1.22 पर्यटन मंत्रालय ने बेहतर योजना और शंकाओं के त्वरित समाधान के साथ पर्यटकों की सहायता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.incredibleindia.org) पर 24x7 लाइव चैट सेवा इंटरफेस शुरू किया है। लाइव चैट सेवा उनकी शंकाओं को दूर करने और यात्रा योजना बनाने में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों को सहायता प्रदान करती है।

1.23 पर्यटक सुविधा और सूचना काउंटर अंग्रेजी न बोलने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह पर्यटन मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन नंबर- '1363' से भी जुड़ा है जहां पर्यटक फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, पुर्तगाली, रूसी, जापानी, कोरियाई, चीनी और अरबी में विदेशी भाषा के एजेंटों से सीधे बात कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे काउंटर 9 हवाईअड्डों यानी नई दिल्ली, वाराणसी, बोधगया, बेंगलूरू, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद में उपलब्ध हैं।

1.24 हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुगम बनाने/प्रेरित करने के मुख्य उद्देश्य से आरसीएस – उड़ान की शुरूआत की गई है। यह एयरलाइन के प्रचालन की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा रियायतों और ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालन की लागत तथा प्रत्याशित राजस्व के बीच के अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। आरसीएस उड़ान के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय से सहयोग किया है और प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 53 पर्यटन मार्गों को चालू करवाया है।

1.25 पर्यटन मंत्रालय देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों को बेहतर एवं सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने अंडमान एवं

निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में चिह्नित द्वीपों के लिए 31 दिसम्बर, 2022 के बाद अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2027 तक पीएपी/आरएपी में छूट प्रदान की है। मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों में 31 दिसंबर, 2022 के बाद और 5 वर्ष की अवधि के लिए पीएपी/आरएपी संबंधी छूट को गृह मंत्रालय ने पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

1.26 सरकार ने निर्भया निधि नामक एक समर्पित अचल संचयी निधि की स्थापना की है, जिसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उपयोग महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, जिसके पास प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन/सिफारिश करने, संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने की जिम्मेदारी है। निर्भया निधि के तहत भारत सरकार के कुल 16.79 करोड़ रुपये (लगभग) के केंद्रीय वित्तीय हिस्से में से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पक्ष में 11.51 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किए गए हैं। 'निर्भया निधि' के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 27.99 करोड़ रुपये (लगभग) है।

1.27 कोविड-19 के बाद बहाली की तैयारी के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने व्यवसायों की अबाध एवं सुरक्षित बहाली को सुगम बनाने के लिए यात्रा क्षेत्र के पर्यटन सेवाप्रदाताओं के विभिन्न सेगमेंट के लिए प्रचालनात्मक सिफारिशें तैयार की। इस तरह की सिफारिशें ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपेटरर्स, टूरिस्ट गाइड एवं सुविधाप्रदाताओं को जारी की गई हैं। इन्हें राज्य सरकारों एवं पर्यटन/आतिथ्य हितधारकों के परामर्श से तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए समग्र दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।

1.28 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवाप्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 08 दिसंबर, 2020 को जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से लागू है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्टअप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। यह स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर एवं पिछले अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रावधान भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के अनुरूप हैं। प्रदत्त पूंजी एवं कर्मचारियों की संख्या संबंधी आवश्यकता भी अन्य श्रेणियों की तुलना में कम होगी।

1.29 आवश्यक अवसंरचना सहायता के साथ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करना पर्यटन मंत्रालय का प्रयास रहा है जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों दृष्टि से पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने में सक्षम हो। अब तक की स्थिति के अनुसार 56 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) (जिसमें 21 केंद्रीय आईएचएम और 33 राज्य आईएचएम और पीपीपी मोड में चल रहे 2 राज्य आईएचएम शामिल हैं) और 13 फूड क्राफ्ट संस्थान (एफसीआई) हैं जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं। जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में एक (1) केंद्रीय आईएचएम निर्माणाधीन है।

1.30 भारत को आतिथ्य उद्योग में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने और होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) की पुनः ब्रांडिंग करने के हिस्से के रूप में, यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय आईएचएम छात्रों को उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क में लाने और आतिथ्य, सेवा और देखभाल के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए अग्रणी होटल श्रृंखलाओं के साथ सहयोग करेंगे। इस पहल के पहले चरण के दौरान, विश्व पर्यटन दिवस, 2024 के अवसर पर सभी 21 केंद्रीय

आईएचएम ने 8 अग्रणी होटल श्रृंखलाओं, अर्थात आईएचसीएल (ताज), आईएचजी होटल एंड रिसॉर्ट्स, मैरियट इंटरनेशनल, ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल, रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स और लेमन ट्री होटल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जबकि, दूसरे चरण के दौरान दो और होटल श्रृंखलाएं अर्थात हिल्टन फॉर द स्टे और रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड ने भी आईएचएमएस के साथ 18 नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन अग्रणी होटल श्रृंखलाओं और केंद्रीय आईएचएम के बीच कुल 70 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत समन्वय वाले क्षेत्र छात्रों को रोजगार देना, संकाय विकास, अल्पकालिक पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल एवं शिक्षण और संस्थागत एवं अवसंरचनात्मक विकास शामिल हैं।

1.31 पर्यटन मंत्रालय केंद्रीकृत अखिल भारतीय ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करने के उद्देश्य से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम चला रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से और भारतीय पर्यटन को विशिष्ट रूप से लाभ होगा क्योंकि इससे सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का समूह तैयार करना और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन संभव हो सकेगा।

1.32 इसके अतिरिक्त, मौजूदा क्षेत्र स्तरीय गाइड (आरएलजी) का नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कर दिया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में प्रावधान के अनुसार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर उनका नाम बदला जाएगा, और उनके प्रचालन क्षेत्र को एक निर्दिष्ट क्षेत्र से बढ़ाकर संपूर्ण भारत किया गया है।

1.33 पर्यटन मंत्रालय ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से 08 मार्च, 2022 को आईआईटीएफ/आईआईटीजी के लिए डिजिटल पर्यटन समाधान के हिस्से के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-मार्केटप्लेस) की अवधारणा की शुरूआत की ताकि पर्यटकों और प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/पर्यटक गाइडों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरेक्शन मकैनिज्म प्रदान किया जा सके। इसे दिनांक 12 अगस्त, 2022 से ऑनलाइन (बीटा संस्करण) किया गया है। पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिए आईआईटीएफ और आईआईटीजी अपना प्रोफाइल, अनुभव, प्रदान की जाने वाली सेवाओं, योग्यताओं, विशेषज्ञता क्षेत्र, टैरिफ, उपलब्ध तारीखों आदि को अपडेट कर सकते हैं, जबकि पर्यटक अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की तलाश कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। पर्यटक अपने ही स्थान से किसी भी गंतव्य के लिए सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की तलाश कर सकते हैं और देश की अपनी आगामी यात्राओं के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यह वेब आधारित समाधान (ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म) सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का प्रोफाइल, बुकिंग, सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की रेटिंग देखने, उपयोगकर्ताओं के फीडबैक (सकारात्मक और नकारात्मक), ज्ञात भाषाओं और सामग्री का प्रबंधन करने के लिए है। यह अपनी सेवाओं में सुधार करने और बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए पर्यटक गाइडों और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को प्रोत्साहित करेगा।

1.34 माननीय सचिव (पर्यटन) की उपस्थिति में स्वच्छता ही सेवा, प्रमुख सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए एक मेगा इवेंट के पखवाड़े के समापन पर, दिनांक 25 सितंबर, 2025 को आईएचएम पूसा, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस मेगा इवेंट में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। सफाई कर्मचारियों/सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, दिनांक 19 सितंबर 2025

को मीडिया सेंटर, परिवहन भवन, नई दिल्ली में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, सफाई मित्रों को पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छता प्रहरी, अंगवस्त्र के गरिमामय बैज और फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने 02 से 31 अक्टूबर, 2025 तक एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों ने स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। अभियान के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय के एसबीएम प्रभाग ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में परिवहन भवन और उसके आसपास स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान चलाया। मीडिया सेंटर, परिवहन भवन, नई दिल्ली में 03 नवंबर, 2025 को एक स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार समारोह 2025 भी आयोजित किया गया।

1.35 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान कुल 658 आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए और इनके ऊपर समयबद्ध तरीके से समुचित कार्यवाई की गई।

****

ऋषिकेश, उत्तराखंड

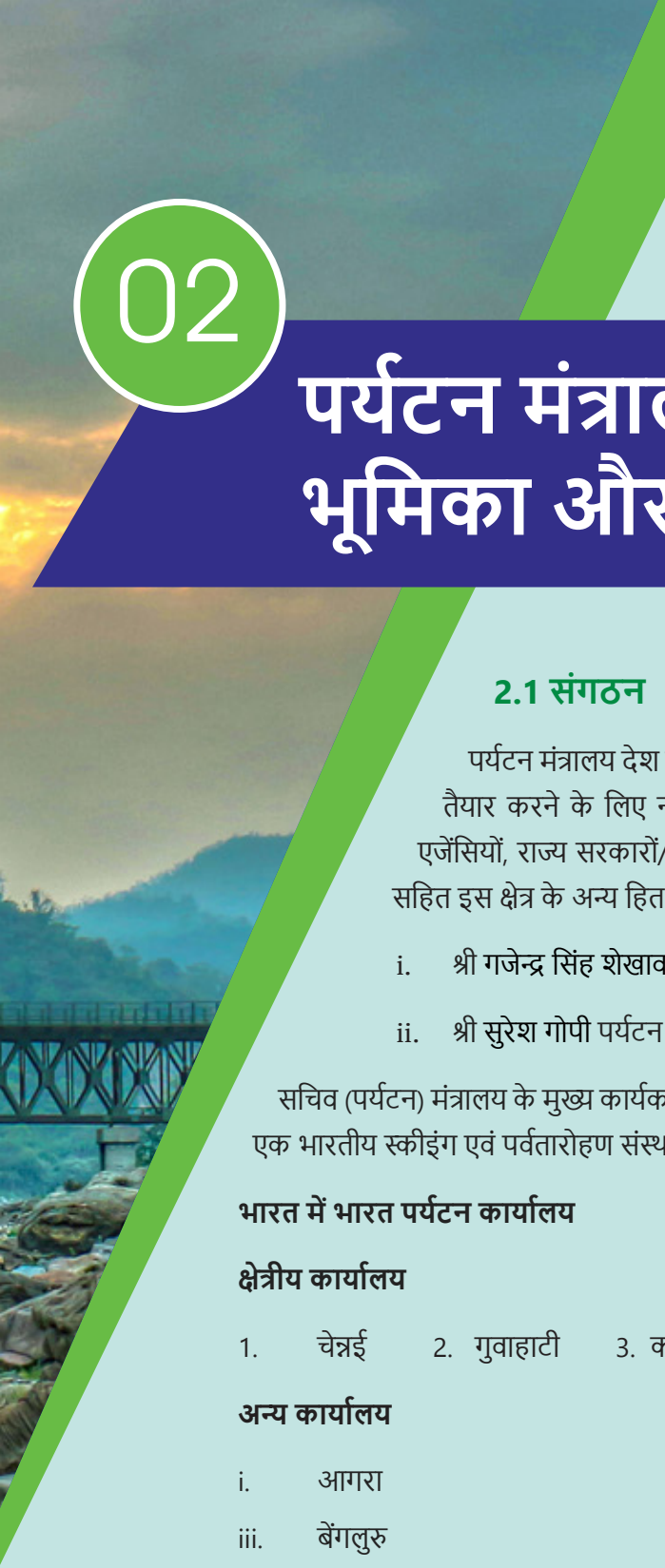

02 पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और उसके कार्य

2.1 संगठन

पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है । मंत्रालय इस प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, उद्योग संघों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श और सहयोग करता है ।

i. श्री **गजेन्द्र सिंह शेखावत** पर्यटन मंत्री हैं ।

ii. श्री **सुरेश गोपी** पर्यटन राज्य मंत्री हैं ।

सचिव (पर्यटन) मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी हैं। देश में पर्यटन महानिदेशालय के 20 घरेलू क्षेत्रीय कार्यालय और एक भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान है।

भारत में भारत पर्यटन कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय

1. चेन्नई 2. गुवाहाटी 3. कोलकाता 4. मुंबई 5. नई दिल्ली

अन्य कार्यालय

i. आगरा
ii. औरंगाबाद
iii. बेंगलुरु
iv. भुवनेश्वर
v. गोवा
vi. हैदराबाद
vii. इम्फाल
viii. इंदौर
ix. जयपुर
x. कोच्चि
xi. नाहरलगुन (ईटानगर)
xii. पटना
xiii. पोर्ट ब्लेयर
xiv. शिलॉन्ग
xv. वाराणसी

पर्यटन मंत्रालय के घरेलू फील्ड कार्यालय देश में पर्यटन क्षेत्र के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी तक फैली हुई है। ये कार्यालय देश भर में पूर्यटन विकास और संवर्धन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के निपटान के लिए एक सहयोगी परिवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ निरंतर सक्रिय संवाद और समन्वय करते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

मंत्रालय के निम्नलिखित स्वायत्त संस्थान भी हैं:

i. भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)।

ii. राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी); और होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)।

iii. भारतीय कलीनरी संस्थान (आईसीआई)। (आईआईटीटीएम और आईएचएम से संबंधित विवरण अध्याय संख्या 9 कौशल एवं क्षमता निर्माण में देखा जा सकता है।)

2.2 पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और कार्य

पर्यटन मंत्रालय रोजगार को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए भारत में इनबाउंड और घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन पर ध्यान केंदित कर रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में देश को पूरे वर्ष अनुकूल रहने वाले पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने, स्थायी रूप से पर्यटन का संवर्धन करने, पर्यटन सेवाप्रदाताओं के बीच गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और पर्यटन अवसरंचना के एकीकृत विकास आदि को बढ़ावा देना शामिल हैं। सरकार पर्यटन अवसरंचना के एकीकृत विकास को बढ़ावा देती है । पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका विनियामक से बदल कर उत्प्रेरक की हो गई है और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहक्रिया और अभिसरण आवश्यक है। इसके कारण यह कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हो गया है परन्तु यह सेक्टर के संवर्द्धन के लिए आवश्यक है।

मंत्रालय के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:-

I. नीतिगत मामले

पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन संवर्धन और विपणन, पर्यटन के लिए विकास कार्यनीतियों का निर्धारण, पर्यटन क्षेत्र में कौशल और जनशक्ति विकास, पर्यटन में विकास, निवेश, प्रोत्साहन, बाहरी सहायता आदि से संबंधित कार्यनीतियों सहित पर्यटन से जुड़े सभी नीतिगत मामलों की देख-रेख करता है।

II. नियोजन और विकास

नियोजन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्य का एक अनिवार्य क्षेत्र है और यह विभिन्न विषयों और उत्पादों के अंतर्गत गंतव्य विकास की योजना बनाकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए प्रयासों का पूरक है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम भी चलाता है।

III. समन्वयन

समन्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से किया जाने वाला एक आवश्यक कार्य है और पर्यटन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, उद्योग संघों और हितधारकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से बातचीत और समन्वय करता है।

IV. विनियम

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं के लिए प्रचालन दिशा-निर्देश तैयार करके और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करके पर्यटन के विभिन्न पहलुओं के लिए कार्यनीतियाँ और ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

V. गंतव्य विकास

पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना के निर्माण और पर्यटन अनुभवों को बेहतर बनाने के माध्यम से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

VI. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय पर्यटन का विपणन और संवर्धन

पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को लक्षित करते हुए व्यापक विपणन पहलों के माध्यम से कार्यनीतिक रूप से भारत को बढ़ावा देता है। डिजिटल अभियानों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और यात्रा व्यापार साझेदारियों के मिश्रण का उपयोग करते हुए, यह एक सम्मोहक कथानक विकसित करता है जो पर्यटन विकास और वैश्विक अपील को बढ़ावा देते हुए भारत के विविध आकर्षणों को दर्शाता है।

VII. अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन

मंत्रालय पर्यटन के विभिन्न पहलुओं की लगातार देखरेख और आकलन करता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विश्लेषण का संचालन करता है। यह दृष्टिकोण सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जिससे प्रभावी पर्यटन योजना बनाने और क्षेत्र के स्थायी विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाहरी सहायता

पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जुड़कर, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते करके वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह बाहरी सहायता के मामलों की जांच करता है और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में, विशेषज्ञता बढ़ाने और इस क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग के अवसर तलाशता है।

IX. सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना

पर्यटन मंत्रालय अपने स्वैच्छिक कार्यक्रमों के तहत होटल, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, पर्यटक परिवहन प्रचालक, गाइड आदि जैसे सेवा प्रदाताओं को मान्यता देता है।

X. निश पर्यटन उत्पाद

पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर विविध निश पर्यटन क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए समर्पित है।

XI. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित सहित विभिन्न अन्य मामलों में सक्रिय रूप से कार्यरत है:

क. वैधानिक और संसदीय कार्य

ख. स्थापना संबंधी मामले

ग. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा

घ. सतर्कता संबंधी मामले

ङ. राजभाषाः राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

च. वीआईपी संदर्भ

छ. बजट समन्वय और संबंधित मामले

ज. कल्याण, शिकायत और प्रोटोकॉल

2.3 सहक्रिया और अभिसरण

2.3.1 हितधारक

यह सुनिश्चित करना पर्यटन मंत्रालय का सतत प्रयास रहा है कि पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न वर्ग, साझेदार मंत्रालय और उनकी क्रियान्वयन एजेंसियां (संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझेदारी, निगम और उपक्रम), राज्य मशीनरी और उद्योग संघ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और पर्यटन के व्यापक लाभ के साथ आकांक्षाओं का संयोजन करें।

2.3.2 साझेदार मंत्रालय

अभिसरण के लिए अपने प्रयास के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों अर्थात वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि और विभिन्न राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर काम करता है।

2.3.3 सरकार की क्रियान्वयन एजेंसियां

मंत्रालय का उन कार्यकारी/कार्यात्मक एजेंसियों के साथ सुदृढ़ संबंध है जो अलग-अलग मंत्रालयों के अधीन कार्यरत हैं। इनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), भारतीय सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी), पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई), एक्सपीरियंस इंडिया सोसायटी इत्यादि जैसे संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझेदारियां, निगम और उपक्रम शामिल हैं।

2.3.4 केंद्रीय स्वायत्त निकाय

पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 केंद्रीय स्वायत्त निकाय हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन और व्यंजन के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना है। 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (सी आई एच एम) हैं जो मुख्य रूप से डिग्री स्तर की आतिथ्य शिक्षा प्रदान करते हैं; राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) आतिथ्य प्रबंधन शिक्षा के समन्वित विकास के लिए सर्वोच्च स्वायत्त निकाय है; भारतीय पाककला संस्थान (आईसीआई) पाककला के विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम चलाता है, जबकि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी है।

2.3.5 उद्योग संघ

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न उद्योग संघों यथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ट्रेवल एजेंट्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईटीटीए), एसोसिएशन ऑफ डॉमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एटीओआई), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई), होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई), इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन (आईएचएचए), एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी (एफएआईटीएच), और ऑल इंड़िया रिजॉर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन (एआईआरडीए) आदि के साथ सतत संवाद करता है।

2.3.6 पर्यटन क्षेत्र संबंधी अंर्तमंत्रालयी समन्वय समिति

पर्यटन अनिवार्य रूप से एक बहु-क्षेत्रक गतिविधि है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ लिंकेज और समन्वय की आवश्यकता होती है। देश में पर्यटन के विकास में निहित अंतर-मंत्रालयी /विभागीय मुद्दों के समाधान को सरल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित पर्यटन क्षेत्र संबंधी अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) के रूप में एक प्रभावी तंत्र मौजूद है।

इस समिति में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आदि शामिल हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय समिति के सदस्य संयोजक हैं। अब तक समिति की 8 बैठकें हो चुकी हैं।

2.3.7 पर्यटन कार्यबल का गठन

पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए पर्यटन क्षेत्रीय योजना पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह की सिफारिशों के आधार पर सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से प्रतिनिधि शामिल हैं। इन मुद्दों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

हवाई, रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट विकास के लिए पर्यटन स्थलों की पहचान करना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मार्ग, पर्यटन स्थलों पर ऐसे एयरपोर्ट जहां कस्टम एवं आप्रवासन की सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, पर्यटन स्थलों पर स्थित अप्रयुक्त एवं कम प्रयुक्त एयरपोर्ट, तीर्थ स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों/स्थलों को जोड़ने वाली पर्यटन ट्रेन शुरू करना और रलवे स्टेशनों का उन्नयन, पर्यटन स्थलों की सड़क कनेक्टिविटी,

- स्मारकों एवं संग्रहालयों सहित सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों का विकास एवं संवर्धन,
- क्रूज पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन आदि सहित निश पर्यटन वर्ग का संवर्धन,

- पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा,
- पर्यटकों को वीजा सुविधाएं प्रदान करना
- पर्यटन को प्रभावित करने वाला कोई अन्य अंतर मंत्रालयी/अंतर विभागीय मुद्दा

2.3.8 राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) पर्यटन मंत्रालय के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है। मौजूदा एनटीएसी का गठन दिनांक 21 जून, 2023 को माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में किया गया जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। इस समिति में महत्वपूर्ण मंत्रालय, यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र में अलग-अलग विशेषज्ञ और औद्योगिक संघों के पदेन सदस्य शामिल हैं।

****

मंत्री

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

माननीय पर्यटन मंत्री

श्री सुरेश गोपी

माननीय पर्यटन राज्य मंत्री

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

डॉ. श्रीवत्स कृष्णा, भा. प्र. से.
सचिव (भारत सरकार)

विशेष/अपर सचिव स्तर के अधिकारी

श्री सुमन बिल्ला
अपर सचिव एवं
महानिदेशक (पर्यटन)

सुश्री वंदना जैन
अपर सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार

श्री ज्ञान भूषण
वरिष्ठ आर्थिक
सलाहकार

संयुक्त सचिव और समकक्ष

डॉ. प्रोमोदिता सतीश
आर्थिक सलाहकार
(पर्यटन)

श्री एम. आर. सिनरेम
संयुक्त सचिव एवं
अतिरिक्त महानिदेशक
(पर्यटन)

श्री हरिकिशोर एस.
संयुक्त सचिव
(पर्यटन)

श्री वेंकट रमण आर. हेगड़े
अतिरिक्त महानिदेशक
(आईएसएस)

पर्यटन मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

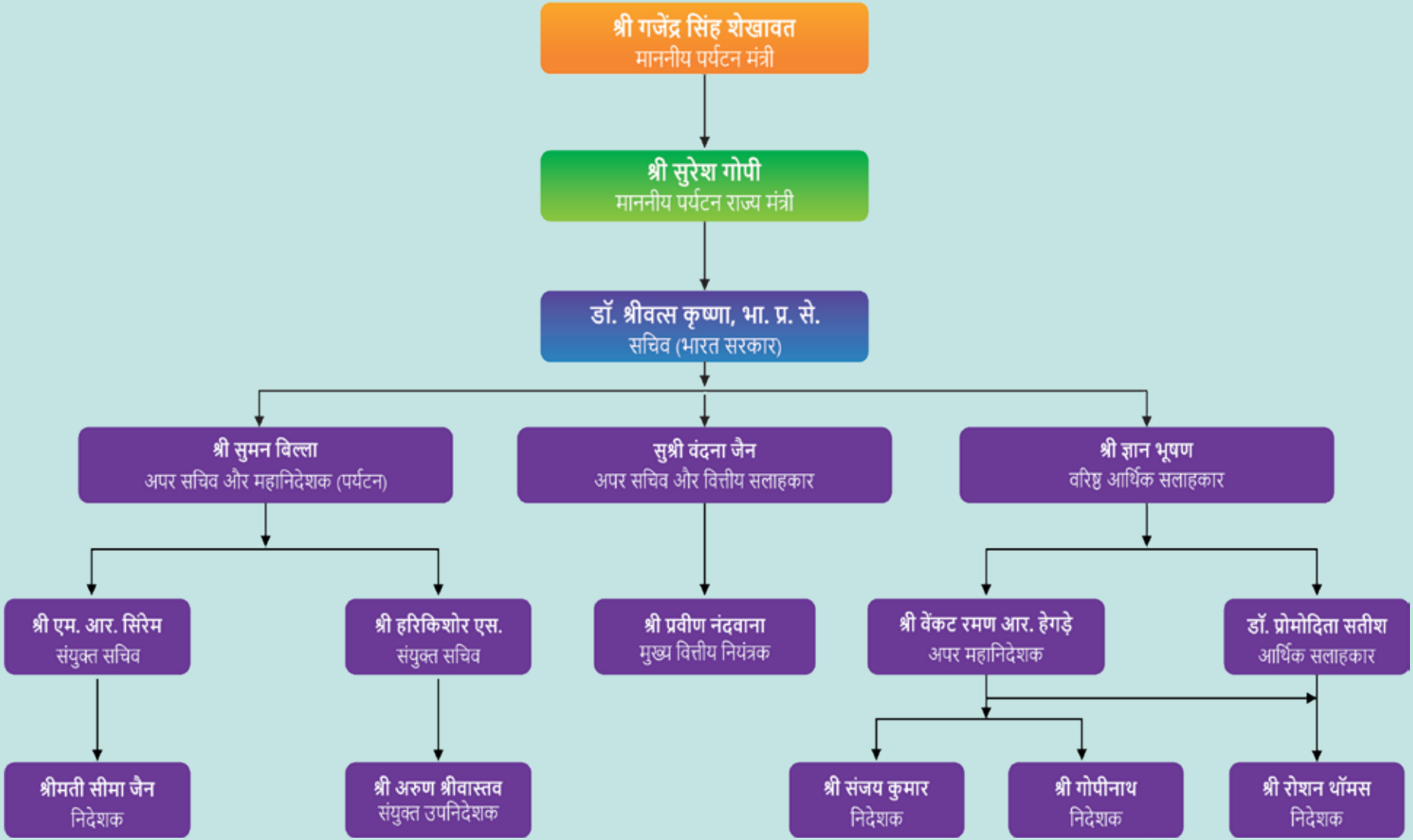

सत्यमेव जयते

विरुपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक

03 गंतव्य विकास

3.1. स्वदेश दर्शन

3.1.1. पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 2014-15 में 'स्वदेश दर्शन' नामक अपनी प्रमुख योजना शुरू की थी और 76 परियोजनाओं के लिए 5,290.33 करोड़ रुपये मंज़ूर किए है, जिनमें से 75 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंज़ूर की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	तटीय परिपथ 2016-17	लॉन्ग द्वीप - रॉस स्मिथ द्वीप - नील द्वीप - हैवलॉक द्वीप-बाराटांग द्वीप - पोर्ट ब्लेयर का विकास	27.57
2	आंध्र प्रदेश	तटीय परिपथ 2014-15	काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरु - एस यानम - कोटिपल्ली का विकास	67.83
3	आंध्र प्रदेश	तटीय परिपथ 2015-16	नेल्लोर – पुलिकट झील - उब्बलमाडुगु जल प्रपात - नेलापट् - कोठाकोडुरु - मायपाडु - रामतीर्थम – इस्कापल्ली का विकास	49.55
4	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ 2017-18	बौद्ध परिपथ: शालीहुंडम – बाविकोंडा – बोज्जनकोंडा – अमरावती - अनूपु का विकास	35.24
5	अरुणाचल प्रदेश	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2014-15	भालुकपोंग - बोमडिला और तवांग का विकास	49.77
6	अरुणाचल प्रदेश	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16	नफरा – सेप्पा - पप्पू, पासा, पक्के घाटियाँ – संगदूपोटा-न्यू सगाली – जीरो-योम्चा का विकास	96.72
7	असम	वन्यजीव परिपथ 2015-16	मानस – प्रोबितोरा – नामेरी – काजीरंगा – डिब्रू - सैखोवा का विकास	94.68

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
8	असम	विरासत परिपथ 2016-17	तेजपुर – माजुली - शिवसागर का विकास	90.98
9	बिहार	तीर्थंकर परिपथ 2016-17	वैशाली – आरा – मसाद – पटना – राजगीर – पावापुरी - चंपापुरी का विकास	33.96
10	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	कांवरिया मार्ग: सुल्तानगंज – धर्मशाला - देवघर का विकास	44.76
11	बिहार	बौद्ध परिपथ 2016-17	बौद्ध परिपथ का विकास - बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	95.18
12	बिहार	ग्रामीण परिपथ 2017-18	भितिहरवा – चंद्रहिया - तुर्कौलिया का विकास	44.27
13	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ 2017-18	मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	44.55
14	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ 2015-16	जशपुर – कुनकुरी – मैनपाट – कमलेशपुर – महेशपुर – कुर्दार – सरोधदादर – गंगरेल – कोंडागांव – नाथियानवागांव – जगदलपुर – चित्रकूट - तीर्थगढ़ का विकास	96.10
15	गोवा	तटीय परिपथ 2016-17	सिंक्वेरिम - बागा, अंजुना - वागाटोर, मोरजिम - केरी, अगुआड़ा किला और अगुआड़ा जेल का विकास	97.65
16	गोवा	तटीय परिपथ 2017-18	तटीय परिपथ II: रुआ डी ओरम क्रीक - डोना पाउला - कोलवा - बेनौलिम का विकास	99.35
17	गुजरात	विरासत परिपथ 2016-17	अहमदाबाद – राजकोट – पोरबंदर – बारदोली - दांडी का विकास	59.17
18	गुजरात	विरासत परिपथ 2016-17	वडनगर - मोढेरा का विकास	91.12
19	गुजरात	बौद्ध परिपथ 2017-18	जूनागढ़ - गिर सोमनाथ – भरूच – कच्छ – भावनगर – राजकोट - मेहसाणा का विकास	26.68
20	हरियाणा	कृष्ण परिपथ 2016-17	कुरुक्षेत्र में महाभारत से संबंधित स्थानों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास	77.39

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
21	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ 2016-17	हिमालय परिपथ: कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमपुर, चंबा का विकास	68.34
22	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	जम्मू – श्रीनगर – पहलगाम - भगवती नगर – अनंतनाग - सलामाबाद, उरी – कारगिल - लेह का विकास	77.33
23	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	जम्मू-राजौरी-शोपियां-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का विकास	81.60
24	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	पर्यटक सुविधाओं का विकास - पीएम विकास पैकेज के तहत 2014 में बाढ़ में नष्ट हुई परिसंपत्तियों के बदले परिसंपत्तियों का निर्माण	90.43
25	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	मंतलाई और सुधमहादेव में पर्यटक सुविधाओं का विकास	91.99
26	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	अनंतनाग – पुलवामा – किश्तवर – पहलगाम - जांस्कर पदुम – दक्सुम - रंजीत सागर बांध में पर्यटक सुविधाओं का विकास	86.39
27	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ 2016-17	गुलमर्ग – बारामूला – कुपवाड़ा - कारगिल - लेह में पर्यटक सुविधाओं का विकास	91.84
28	झारखंड	इको परिपथ 2018-19	इको पर्यटन परिपथ: दलमा - बेतला नेशनल पार्क – मिरचैया - नेतरहाट का विकास	30.44
29	केरल	इको परिपथ 2015-16	पथनमथिट्टा – गवी – वागामोन - तेक्कडी का विकास	64.08
30	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	सबरीमाला – एरुमेली – पम्पा - सन्निधानम का विकास	46.54
31	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्रीपद्मनाभ अर्नामूला का विकास	78.08
32	केरल	ग्रामीण परिपथ 2018-19	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35
33	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	शिवगिरीश्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मनिया - चेम्बझंथी श्री नारायण गुरुकुलम का विकास	66.42

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
34	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ 2015-16	पन्ना–मुकुंदपुर–संजय–दुबरी- बांधवगढ़–कान्हा – मुक्की - पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.10
35	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ 2016-17	सांची – सतना – रीवा – मंदसौर - धार का विकास	74.02
36	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ 2016-17	ग्वालियर – ओरछा – खजुराहो – चंदेरी – भीमबेटका – मांडू का विकास	89.82
37	मध्य प्रदेश	इको परिपथ 2017-18	गांधीसागर बांध - मंडलेश्वर बांध - ओंकारेश्वर बांध - इंदिरा सागर बांध - तवा बांध - बरगी बांध – भेड़ाघाट - बाणसागर बांध - केन नदी का विकास	93.76
38	महाराष्ट्र	तटीय परिपथ 2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ - सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), मितभव का विकास	19.06
39	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	वाकी – अदासा – धापेवाड़ा – पारदसिंघा – तेलनखंडी - गिराड का विकास	45.47
40	मणिपुर	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16	मणिपुर में पर्यटक परिपथ: इम्फाल -खोंगजोम का विकास	72.23
41	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्री गोविंदजी मंदिर, श्री बिजॉय गोविंदजी मंदिर – श्री गोपीनाथ मंदिर – श्री बंगशीबोदोन मंदिर – श्री कैना मंदिर का विकास	45.34
42	मेघालय	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2016-17	उमियम (लेक व्यू), यू लुम सोहपेटबनेंग - मावडियांगडियांग - आर्किड लेक रिज़ॉर्ट का विकास	99.13
43	मेघालय	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2018-19	वेस्ट खासी हिल्स (नोंगखलाव- क्रेम तिरोट - खुदोई और कोहमांग जलप्रपात - खरी नदी-मावथाद्रीशन, शिलांग), जयंतिया हिल्स (क्रांग सूरी फॉल्स- शिरमंग-इयूक्सी), गारो हिल्स (नोकरेक रिजर्व, कट्टाबील, सिजू गुफाएं) का विकास	84.97
44	मिजोरम	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16	थेनजोल और साउथ ज़ोटे, जिला सेरछिप और रईक का विकास	92.26

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
45	मिजोरम	इको परिपथ 2016-17	इको-एडवेंचर परिपथ आइजोल -रावपुइचिप - खवफाप - लेंगपुई - चटलांग- सकाव्रहमुइटुइतलांग - मुथी - बेराटलांग - तुइरियल एयरफील्ड - हमुइफांग का विकास	66.37
46	नागालैंड	जनजातीय परिपथ 2015-16	जनजातीय परिपथ पेरेन- कोहिमा- वोखा का विकास	97.36
47	नागालैंड	जनजातीय परिपथ 2016-17	मोकोकचुंग – तुएनसांग - मोन का विकास	98.14
48	ओडिशा	तटीय परिपथ 2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपाड़ा और तंपारा का विकास	70.82
49	पुडुचेरी	तटीय परिपथ 2015-16	दुबरायापेट – अरिकामेडु – वीरमपट्टिनम – चुन्नम्बर – नल्लावाडु/नरमबाई – मनापेट - कालापेट - पुडुचेरी - यानम का विकास	58.44
50	पुडुचेरी	विरासत परिपथ 2017-18	फ्रेंको - तमिल गांव, कराईकल, माहे और यानम का विकास	49.44
51	पुडुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ 2017-18	पुडुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	34.96
52	पंजाब	विरासत परिपथ 2018-19	आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर साहिब - फिरोजपुर - खटकर कलां - कलानौर - पटियाला का विकास	85.32
53	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ 2015-16	सांभर लेक टाउन और अन्य स्थलों का विकास	50.01
54	राजस्थान	कृष्ण परिपथ 2016-17	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का विकास	75.80
55	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	आध्यात्मिक परिपथ - 'चुरू (सालासर बालाजी) - जयपुर (श्री समोदके बालाजी, घाटके बालाजी, बंधेके बालाजी) - विराटनगर (बीजक, जैनसिया, अंबिका मंदिर) - भरतपुर (कमान क्षेत्र) - धौलपुर (मुचकुंड) – मेहंदीपुर बालाजी - चित्तौड़गढ़ (सांवलियाजी) का विकास	87.05

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
56	राजस्थान	विरासत परिपथ 2017-18	विरासत परिपथ राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) - जयपुर (जयपुर और नाहरगढ़ किले में अग्रभाग की प्रकाश व्यवस्था) -झालावाड़ (गागरोन किला) - चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ किला) - जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेड़ी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए-निलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेड़ता) - टोंक (सुनहरी कोठी) का विकास	70.61
57	सिक्किम	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16	रंगपो (प्रवेश) – रोराथांग – अरितार – फादमचेन – नाथंग – शेराथांग – सोंगमो – गंगटोक – फोडोंग – मंगन – लाचुंग –युमथांग – लाचेन – थांगु – गुरुडोंगमेर - मंगन – गंगटोक – तुमिनलिंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास	98.05
58	सिक्किम	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2016-17	सिंगटम–मका–टेमी – बेरमोइक टोकेल – फोंगिया – नामची – जोरथांग – ओखारे – सोम्बारिया – दारमदिन - जोरेथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास	95.32
59	तमिलनाडु	तटीय परिपथ 2016-17	(चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी) का विकास	73.13
60	तेलंगाना	इको परिपथ 2015-16	महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का विकास	91.62
61	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ 2016-17	मुलुगु – लकनावरम – मेदवरम – तड़वई – दमारवी – मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास	79.87
62	तेलंगाना	विरासत परिपथ 2017-18	कुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे-हयात बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास	96.90
63	त्रिपुरा	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16	अगरतला – सिपाहीजला - मेलाघर – उदयपुर – अमरपुर – तीर्थमुख - मंदिरघाट – डंबूर – नारिकेलकुंज – गंडाचरा - अंबासा का विकास	82.85

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
64	त्रिपुरा	उत्तर-पूर्वी परिपथ 2018-19	सूरमाचेर्रा – उनाकोटी - जम्पुई हिल्स – गुनाबती – भुवनेश्वरी–नीरमहल – बॉक्सनगर - चोट्टाखोला – पिलक - अवांगचारा का विकास	44.83
65	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ 2016-17	श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	87.89
66	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ 2016-17	चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45
67	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	आहर – अलीगढ़ – कासगंज - सरोसी (उन्नाव)– प्रतापगढ़–कौशांबी–मिर्जापुर – गोरखपुर – डुमरियागंज – बस्ती – बाराबंकी – आजमगढ़ – कैराना – बागपत - शाहजहांपुर का विकास	71.91
68	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	बिजनौर–मेरठ–कानपुर - कानपुर देहात – बांदा– गाजीपुर–सलेमपुर– घोसी – बलिया - अम्बेडकर नगर–अलीगढ़–फतेहपुर–देवरिया– महोबा– सोनभद्र – चंदौली – मिश्रिख - भदोही का विकास	67.51
69	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ 2016-17	कालिंजर किला (बांदा) - मगहरधाम (संतकबीर नगर) - चौरीचौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर) - महुअर शहीद स्थल (घोसी) - शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	36.65
70	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ 2017-18	अयोध्या का विकास	127.21
71	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	जेवर – दादरी – सिकंदराबाद – नोएडा – खुर्जा - बांदा का विकास	12.03
72	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपट्टन मंदिर (बलरामपुर) और वटवाशनी मंदिर (डुमरियागंज) का विकास	18.30
73	उत्तराखंड	इको परिपथ 2015-16	टिहरी झील और निकटवर्ती क्षेत्रों का नए गंतव्य के रूप में विकास के लिए इको-पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और संबद्ध पर्यटन संबंधी अवसंरचना का एकीकृत विकास - जिला टिहरी	69.17

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
74	उत्तराखंड	विरासत परिपथ 2016-17	कुमाऊं क्षेत्र में विरासत परिपथ – कटारमल – जोगेश्वर – बैजनाथ - देवीधुरा का एकीकृत विकास	76.32
75	पश्चिम बंगाल	तटीय परिपथ 2015-16	तटीय परिपथ: उदयपुर – दीघा – शंकरपुर – ताजपुर – मंदारमणि – फ्रेजरगंज - बक्खलाई - हेनरी द्वीप का विकास	67.99
76	-	मार्गस्थ परिपथ 2018-19	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी - गया; कुशीनगर – गया - कुशीनगर में मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	17.50
कुल				**5290.33**

3.1.2. इस योजना के तहत देश में विभिन्न गंतव्यों पर कई घटक/सुविधाएं विकसित की गईं। जिन सुविधाओं के लिए निधियां मंज़ूर की गई थीं, उनमें कई तरह के घटक शामिल है, जैसे कन्वेंशन सेंटर, लॉग हट्स, कैफेटेरिया, जन सुविधाएं, पर्यटक सुविधा केंद्र, स्मारिका की दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र, व्याख्या केंद्र, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्थलों पर रैंप की व्यवस्था, एडवेंचर एक्टिविटीज़, अग्रभाग का सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग (हार्ड और सॉफ्ट) का काम, पार्किंग आदि।

लाइट और साउंड शो, मुचकुंड, धौलपुर, राजस्थान

पर्यटक व्याख्या केंद्र, सांची, मध्य प्रदेश

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (सरही), मध्य प्रदेश में इको लॉग हट्स

3.1.3. पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के निर्माण के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 का नया नाम दिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों के परामर्श और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 29 परियोजनाएं, 2024-25 के दौरान 19 परियोजनाएं और 2025-26 के दौरान 5 और परियोजनाएं (30 अक्टूबर, 2025 तक) स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए स्वीकृत की है। स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2024-25	बापतला	सूर्यलंका बीच एक्सपीरियंस का विकास	97.52
2	आंध्र प्रदेश	2023-24	अरक्कू-लम्बासिंगी	अरक्कू में बोर्रा केव एक्सपीरियंस	29.88
3	अरुणाचल प्रदेश	2023-24	नाचो	अनलॉक नाचो अभियान	14.02
4	अरुणाचल प्रदेश	2023-24	मेचुका	मेचुका सांस्कृतिक हाट	18.48
5	अरुणाचल प्रदेश	2023-24	मेचुका	मेचुका एडवेंचर पार्क	12.75
6	असम	2023-24	कोकराझार	कोकराझार वेटलैंड एक्सपीरियंस	26.67
7	असम	2023-24	जोरहाट	रीइमेंजिनिंग सिन्नामारा टी एस्टेट	23.88
8	बिहार	2024-25	बोधगया	बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का विकास	165.44
9	छत्तीसगढ़	2024-25	कवर्धा	भोरमदेव कॉरिडोर विकास, कबीरधाम जिला	145.99
10	दादरा एवं नगर एवं हवेली तथा दमन एवं दीव	2024-25	दमन	दमन कन्वेंशन सेंटर	147.13
11	गोवा	2023-24	पोर्वोरिम	पोर्वोरिम क्रीक एक्सपीरियंस	24.07
12	गोवा	2023-24	कोलवा	कोलवा बीच एक्सपीरियंस	19.89
13	हरियाणा	2024-25	पंचकुला	टिक्कर ताल और एडवेंचर पार्क में एडवेंचर टूरिज्म हब का विकास	26.68
14	हरियाणा	2024-25	पंचकुला	यादविन्द्रा गार्डन का कायाकल्प	65.82

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
15	हिमाचल प्रदेश	2024-25	माँ चिंतपूर्णी मंदिर (जिला - ऊना)	मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर, ऊना का विकास	56.26
16	कर्नाटक	2023-24	हम्पी	'ट्रैवलर नूक्स' की स्थापना	25.64
17	कर्नाटक	2023-24	मैसूरु	टोंगा राइड हेरिटेज एक्सपीरियंस जोन	2.72
18	कर्नाटक	2023-24	मैसूरु	ईकोलोजिकल एक्सपीरियंस जोन	18.48
19	केरल	2023-24	कुमारकोम	कुमारकोम पक्षी अभयारण्य अनुभव	13.81
20	केरल	2024-25	अलप्पुझा	अलाप्पुझा: ए ग्लोबल वॉटर वंडरलैंड	93.18
21	केरल	2024-25	मलमपुझा	मलमपुझा गार्डन और लीजर पार्क में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना	75.87
22	लद्दाख	2023-24	लेह	जूले लेह जैव विविधता पार्क	23.17
23	लद्दाख	2023-24	कारगिल	एक्सप्लोरिंग एलओसी और हुंडरमन विलेज एक्सपीरियंस	11.91
24	लक्षद्वीप	2024-25	बंगारम	बंगाराम में पर्यटक अनुभव का संवर्धन	81.18
25	मध्य प्रदेश	2023-24	ग्वालियर	फूलबाग एक्सपीरियंस जोन	16.74
26	मध्य प्रदेश	2023-24	चित्रकूट	चित्रकूट में आध्यात्मिक एक्सपीरियंस	27.21
27	मध्य प्रदेश	2024-25	पीताम्बरा पीठ, दतिया	पीताम्बरा पीठ दतिया का विकास	44.24
28	महाराष्ट्र	2023-24	पुणे	शिवसृष्टि एतिहासिक थीम पार्क-फेज 3	76.22

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
29	मेघालय	2023-24	सोहरा	वॉटरफॉल ट्रेल्स एक्सपीरियंस	27.60
30	मेघालय	2023-24	सोहरा	मेघालयन एज केव एक्सपीरियंस	32.45
31	मिजोरम	2024-25	चम्फाई	केइलुंगलिया, ज़ोटे, नगुर और मुअलबुह्म, चम्फाई में इको रिज़ॉर्ट एक्सपीरियंस	38.85
32	मिजोरम	2024-25	चम्फाई	विरासत और सांस्कृतिक केंद्र, चम्फाई	33.87
33	मिजोरम	2025-26	थिंग्सुलथलिया	सम्मेलन केंद्र का निर्माण	99.71
34	नागालैंड	2023-24	चुमुकेदिमा	चुमुकेदिमा व्यू पॉइंट पर इको- पर्यटन एक्सपीरियंस	7.87
35	नागालैंड	2023-24	चुमुकेदिमा	मिडवे रिट्रीट में जनजातीय सांस्कृतिक एक्सपीरियंस	21.56
36	नागालैंड	2024-25	चुमुकेदिमा	चुमुकेदिमा के जैकब गांव में साहसिक पर्यटन का अनुभव	32.54
37	पुदुचेरी	2023-24	कराईकल	कराईकल बीच और वाटरफ्रंट एक्सपीरियंस	20.29
38	पंजाब	2023-24	कपूरथला	कांजिली वेटलैंड में इको पर्यटन एक्सपीरियंस	20.06
39	पंजाब	2023-24	अमृतसर	अटारी में सीमा पर्यटन एक्सपीरियंस	25.91
40	राजस्थान	2023-24	बूंदी	केशोरायपाटन में आध्यात्मिक अनुभव	21.65

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
41	राजस्थान	2024-25	सीकर	श्री खाटू श्याम जी मंदिर (सीकर) में विकास कार्य	87.87
42	राजस्थान	2024-25	करणी माता मंदिर, जिला बीकानेर	श्री करणी माता मंदिर, बीकानेर में विकास कार्य	22.58
43	राजस्थान	2024-25	मालासेरी डूंगरी (जिला - भीलवाड़ा)	मालासेरी डूंगरी, भीलवाड़ा जिले का विकास	48.73
44	सिक्किम	2023-24	ग्यालशिंग	युकसोम क्लस्टर में इको-वेलनेस एक्सपीरियंस	15.41
45	सिक्किम	2023-24	गंगटोक	गंगटोक सांस्कृतिक गांव	22.60
46	तमिलनाडु	2023-24	मामल्लापुरम	शोर मंदिर में इमर्सिव एक्सपीरियंस	30.02
47	तेलंगाना	2023-24	भोंगीर	भोंगीर किला एक्सपीरियंशियल जोन	56.82
48	तेलंगाना	2023-24	अनंतगिरि	अनंतगिरि वन में इको पर्यटन जोन	38.01
49	त्रिपुरा	2024-25	अगरतला	अगरतला में त्रिपुरा हेरिटेज विलेज और संगीत अनुभव (चरण-1 और 2)	48.95
50	उत्तर प्रदेश	2023-24	प्रयागराज	आजाद पार्क और देखो प्रयागराज ट्रेल एक्सपीरियंस	14.52
51	उत्तर प्रदेश	2023-24	नैमिषारण्य	वैदिक - वेलनेस एक्सपीरियंस	17.80

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
52	उत्तराखंड	2023-24	पिथौरागढ़	गुंजी में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर एक्सपीरियंस	17.86
53	उत्तराखंड	2023-24	चंपावत	टी गार्डन एक्सपीरियंस	19.89
कुल					**2208.27**

कोकराझार वेटलैंड अनुभव, कोकराझार, असम (चित्रण)

त्रिपुरा हेरिटेज विलेज और संगीत अनुभव, अगरतला, त्रिपुरा (चित्रण)

केशवरायपाटन, बूंदी, राजस्थान में आध्यात्मिक अनुभव (चित्रण)

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, देखो प्रयागराज - कहानियों का शहर (चित्रण)

मेचुका, अरुणाचल प्रदेश सांस्कृतिक हाट अनुभव (चित्रण)

जोरहाट, असम, रिइमेंजिनिंग सिन्नमारा टी एस्टेट (चित्रण)

मावम्लुह गुफाएं, सोहरा, मेघालय (चित्रण)

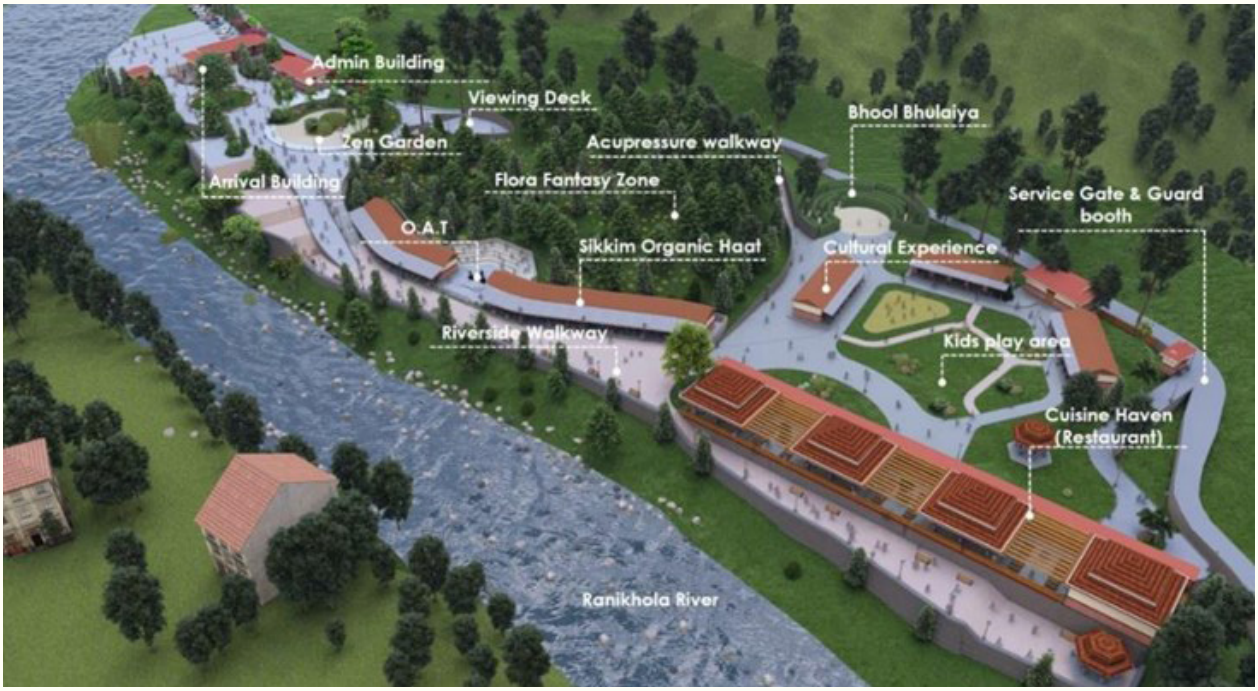

गंगटोक कल्चरल विलेज, गंगटोक, सिक्किम (चित्रण)

भोंगीर, तेलंगाना, भोंगीर किला एक्सपीरियंशियल जोन (चित्रण)

बोर्रा केव एक्सपीरियंस, अरक्कु-लंबासिंगी, आंध्र प्रदेश (चित्रण)

'ट्रैवलर्स नुक', हम्पी, कर्नाटक की स्थापना (चित्रण)

हेरिटेज एक्सपीरियंस ज़ोन (टोंगा राइड परिपथ), मैसुरू, कर्नाटक (चित्रण)

कुमारकोम पक्षी अभयारण्य अनुभव, कुमारकोम, केरल (चित्रण)

फूलबाग एक्सपीरियंस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (चित्रण)

3.1.4 यद्यपि इस योजना का मुख्य घटक पर्यटन और संबद्ध अवसंरचना और पर्यटन सेवाओं को निधियां प्रदान करना है, तथापि योजना का विशिष्ट उद्देश्य देश में अंतर्गामी और घरेलू पर्यटन के विकास की गति को बढ़ाना है। इस योजना में यह स्वीकार किया गया है कि किसी गंतव्य का विकास करने के लिए केवल मूर्त अवसंरचना ही नहीं, बल्कि अमूर्त अवसंरचना भी उतनी ही ज़रूरी है, जो आगंतुकों को एक अनूठा और संतोषजनक अनुभव देने के लिए मिलकर गंतव्य को तैयार करेंगे।

3.1.5. यह योजना संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर केंद्रित है और चिह्नित गंतव्यों का विकास करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव करती है। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने के लिए, इस योजना के तहत एक मजबूत संस्थागत कार्यढ़ाचा बनाया गया है।

3.1.6. पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप-योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। इस उप-योजना का उद्देश्य सभी पर्यटक मूल्य श्रृंखला में पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गंतव्यों का समग्र विकास करना है, ताकि हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी गंतव्य में बदला जा सके। इस उप-योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने 36 गंतव्यों से 36 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनकी कुल लागत 648.11 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2024-25	अहोबिलम - एक आध्यात्मिक यात्रा	आध्यात्मिक पर्यटन	25.00
2	आंध्र प्रदेश	2024-25	नागार्जुन सागर में बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक अनुभवों का संवर्धन	संस्कृति एवं विरासत	25.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2024-25	बिचोम बांध साहसिक और इको-पर्यटन परियोजना	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.90
4	अरुणाचल प्रदेश	2024-25	किभितो सीमांत पर्यटन - शांति का प्रवेश द्वार	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	4.96
5	असम	2024-25	पाणिधिंग पक्षी अभयारण्य, शिवसागर	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.99
6	बिहार	2024-25	सोनपुर मेला मैदान, सारण में पर्यटक सुविधाओं का विकास	संस्कृति एवं विरासत	24.29
7	छत्तीसगढ़	2024-25	मायाली बगीचा का इको-पर्यटन स्थल के रूप में विकास	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.97
8	गोवा	2024-25	मायेम गाँव में हरवलम जलप्रपात का सौंदर्यीकरण और विकास	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.81
9	गुजरात	2024-25	शर्मिष्ठा झील का रूपांतरण: वडनगर में प्रकाश और संस्कृति	संस्कृति एवं विरासत	17.29

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
10	गुजरात	2024-25	हरसिद्धि तट, पोरबंदर में पवित्र महासागर आश्रय स्थल	आध्यात्मिक पर्यटन	24.66
11	गुजरात	2024-25	थोल: परिवर्तनकारी पर्यटन 'सौहार्दपूर्ण स्थायित्व, अनुकूलित कौशल' अग्रणी प्रौद्योगिकी	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.96
12	हिमाचल प्रदेश	2024-25	काज़ा में पर्यटन अवसंरचना विकास	संस्कृति एवं विरासत	24.82
13	हिमाचल प्रदेश	2024-25	रक्छम, छितकुल में पर्यटन अवसंरचना विकास	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	4.96
14	झारखंड	2024-25	रामरेखा धाम, सिमडेगा में पर्यटन अवसंरचना विकास	आध्यात्मिक पर्यटन	18.87
15	केरल	2024-25	थालास्सेरी: आध्यात्मिक जुड़ाव	आध्यात्मिक पर्यटन	25.00
16	केरल	2024-25	वर्कला-दक्षिण काशी	संस्कृति एवं विरासत	25.00
17	लद्दाख	2024-25	मुश्कोह को एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में उन्नत बनाना: वन्यजीव दर्शन और सामुदायिक प्रगति का एकीकरण	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.82
18	मध्य प्रदेश	2024-25	मध्यकालीन वैभव 2.0, ओरछा	आध्यात्मिक पर्यटन	25.00
19	महाराष्ट्र	2024-25	अहमदनगर किले का विकास	संस्कृति एवं विरासत	25.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
20	मणिपुर	2024-25	मणिपुर की प्राचीन राजधानी, लंगथबल कोनुग का विकास	संस्कृति एवं विरासत	24.69
21	मेघालय	2024-25	मावफलांग सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र	संस्कृति एवं विरासत	24.87
22	मेघालय	2024-25	नर्तियांग आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	आध्यात्मिक पर्यटन	24.87
23	नागालैंड	2024-25	सोलफुल ट्रेल: इम्पुर विरासत अनुभव, इम्पुर गाँव	आध्यात्मिक पर्यटन	24.94
24	नागालैंड	2024-25	दोयांग पर विंग्स का विकास: एक इको पर्यटन स्थल, दोयांग जलाशय	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	10.00
25	पुदुचेरी	2024-25	व्हाइट टाउन का विकास	संस्कृति एवं विरासत	22.19
26	पंजाब	2024-25	हुसैनीवाला बॉर्डर, फिरोजपुर में सांस्कृतिक और विरासत खंड	संस्कृति एवं विरासत	25.00
27	पंजाब	2024-25	विरासत मार्ग - श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर में शांति और सद्भाव का प्रतीक	आध्यात्मिक पर्यटन	24.90
28	सिक्किम	2024-25	वीरता की गूँज: गनाथांग घाटी अनुभव, गनाथांग गाँव	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	5.00
29	सिक्किम	2024-25	काबी क्रॉनिकल्स: एकता और विरासत के माध्यम से एक यात्रा, काबी, मंगन	आध्यात्मिक पर्यटन	24.96
30	तमिलनाडु	2024-25	रामेश्वरम का प्रतीकात्मक परिवर्तन	आध्यात्मिक पर्यटन	20.01

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
31	तेलंगाना	2024-25	नलगोंडा के बुद्धवनम में डिजिटल अनुभव केंद्र	संस्कृति एवं विरासत	24.85
32	तेलंगाना	2024-25	निज़ाम सागर, कामारेड्डी में इको-पर्यटन परियोजना का विकास	इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल	9.98
33	उत्तर प्रदेश	2024-25	महोबा में सांस्कृतिक परिदृश्य का विकास	संस्कृति एवं विरासत	24.98
34	उत्तराखंड	2024-25	जादुंग उत्सव मैदान, जादुंग का विकास	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	4.99
35	उत्तराखंड	2024-25	कैंचीधाम परिसर, कैंचीधाम का विकास	आध्यात्मिक पर्यटन	17.60
36	उत्तराखंड	2024-25	माना हाट परियोजना	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	4.99
कुल					648.11

बिचोम बांध एडवेंचर और इको-पर्यटन परियोजना, अरुणाचल प्रदेश (चित्रण)

निज़ाम सागर, तेलंगाना में इको-पर्यटन परियोजना का विकास (चित्रण)

कैंची धाम परिसर, उत्तराखंड का विकास (चित्रण)

3.1.7 पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई योजना) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास

इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित मापदंडों के आधार पर ₹3295.76 करोड़ की राशि की 40 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है और इन्हें व्यय विभाग द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2024-25	गंडीकोटा में फोर्ट एवं गोर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन	77.91
2	आंध्र प्रदेश	2024-25	राजा महेंद्रवरम में अखंड गोदावरी- (हवेलोक ब्रिज और पुष्कर घाट)	94.44
3	अरुणाचल प्रदेश	2024-25	पासीघाट में सियांग एडवेंचर और इको-रिट्रीट	46.48
4	असम	2024-25	गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	97.12
5	असम	2024-25	शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण	94.76
6	बिहार	2024-25	सहरसा में मत्स्यगंधा झील का विकास	97.61
7	बिहार	2024-25	करमचट में करमचट इको पर्यटन और एडवेंचर हब	49.51
8	छत्तीसगढ़	2024-25	रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास	95.79
9	छत्तीसगढ़	2024-25	रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का विकास	51.87
10	गोवा	2024-25	पोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय	97.46
11	गोवा	2024-25	पोरवोरिम में टाउनस्क्वेयर	90.74
12	गुजरात	2024-25	केरली (मोकरसागर), पोरबंदर में इको-पर्यटन गंतव्य	99.50
13	गुजरात	2024-25	धोर्डो में टेंटेड सिटी और कन्वेंशन सेंटर	51.56
14	झारखंड	2024-25	कोडरमा में तिलैया का इको-पर्यटन विकास	34.87
15	कर्नाटक	2024-25	रोएरिच और देविका रानी एस्टेट टाटागुनि, बेंगलुरु में इको पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र	99.17
16	कर्नाटक	2024-25	बेलगावी में सवादत्ती यल्लम्मागुड्डा का विकास	100.00
17	केरल	2024-25	कोल्लम में अष्टमुडी जैव विविधता और इको मनोरंजन केंद्र	59.71
18	केरल	2024-25	सरगालया में मालाबार के सांस्कृतिक क्रूसिबल का ग्लोबल गेटवे	95.34
19	मध्य प्रदेश	2024-25	ओरछा एक मध्यकालीन वैभव	99.92
20	मध्य प्रदेश	2024-25	भोपाल में एमआईसीई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर	99.38

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
21	महाराष्ट्र	2024-25	सिंधुदुर्ग में आईएनएस-गुलदार अंतर्जलीय संग्रहालय, कृत्रिम चट्टान और पनडुब्बी पर्यटन	46.91
22	महाराष्ट्र	2024-25	नासिक में "राम-काल पथ" का विकास	99.14
23	मणिपुर	2024-25	लोकटक में लोकटक लेक एक्सपीरियंस	89.48
24	मेघालय	2024-25	मावखानू में एमआईसीई अवसंरचना	99.27
25	मेघालय	2024-25	शिलांग में उमियम झील का पुनर्विकास	99.27
26	ओडिशा	2024-25	हीराकुंड का विकास	99.90
27	ओडिशा	2024-25	सतकोसिया का विकास	99.99
28	पंजाब	2024-25	एसबीएस नगर में खटकर कलां में शहीद-ए-आजम, सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में हेरिटेज स्ट्रीट का विकास	53.45
29	राजस्थान	2024-25	जयपुर में आमेर-नाहरगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र का विकास	49.31
30	राजस्थान	2024-25	जयपुर में जल महल का विकास	96.61
31	सिक्किम	2024-25	नामची में स्काईवॉक, भालेढुंगा, यांगांग	97.37
32	सिक्किम	2024-25	नाथुला में बॉर्डर एक्सपीरियंस	68.19
33	तमिलनाडु	2024-25	मामल्लापुरम में नंदवनम हेरिटेज पार्क का विकास	99.67
34	तमिलनाडु	2024-25	ऊटी में रेस कोर्स में इको पार्क	70.23
35	तेलंगाना	2024-25	रामप्पा में रामप्पा क्षेत्र स्थायी पर्यटन परिपथ	73.74
36	तेलंगाना	2024-25	नल्लामाला में सोमसिल्ला निरोगता और आध्यात्मिक रिट्रीट	68.10
37	त्रिपुरा	2024-25	गोमती के बंडुआर में शक्ति पीठ पार्क	97.70
38	उत्तर प्रदेश	2024-25	आगरा जिले में बटेश्वर का विकास	74.05
39	उत्तर प्रदेश	2024-25	श्रावस्ती में एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास	80.24
40	उत्तराखंड	2024-25	प्रतिष्ठित शहर ऋषिकेश: ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन	100.00
कुल				**3,295.76**

मावखानू, मेघालय में एमआईसीई अवसंरचना (चित्रण)

स्काईवॉक, भालेधुंगा, यांगंग, सिक्किम (चित्रण)

एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश (चित्रण)

*****

3.2 प्रशाद

परिचय

पर्यटन मंत्रालय ने "राष्ट्रीय तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान" (प्रसाद) को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य चिह्नित तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना था। इस योजना का लक्ष्य चिह्नित गंतव्यों पर तीर्थस्थल/आध्यात्मिक पर्यटन अवसंरचना का विकास करना था।

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की हृदय (एचआरआईडीएवाई) योजना को बंद करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और विरासत गंतव्यों के विकास की परियोजना को प्रसाद योजना में शामिल करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है और अक्टूबर 2017 में इस योजना का नाम भी प्रसाद से बदलकर "तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)" कर दिया गया है।

अब तक, प्रशाद योजना के तहत 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 54 परियोजनाएं मंज़ूर की गई है। जनवरी 2015 में इसके लॉन्च होने के बाद से, 1726.74 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंज़ूर की जा चुकी है, और इन परियोजनाओं के लिए अब तक कुल 1200.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
2014-15	4	73.97
2015-16	7	179.72
2016-17	7	190.36
2017-18	5	186.04

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
2018-19	5	202.84
2019-20	1	48.53
2020-21	7	272.25
2021-22	2	84.88
2022-23	6	270.49
2023-24	1	45.38
2024 -25	9	172.28
कुल	**54**	**1726.74**

प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ

उपलब्धि:

- 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 1726.74 करोड़ रुपये की लागत की 54 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। अब तक 1200.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुके है।
- 32 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है, जबकि 18 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 3 परियोजनाएं निविदा के चरण में है, जबकि 1 परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- 12 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रशाद योजना के तहत विकास के लिए 16 नई साइट्स की भी पहचान की गई है।

प्रशाद योजना के तहत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास	2015-16	27.77	27.77	पूर्ण
2	आंध्र प्रदेश	श्रीसैलम मंदिर का विकास	2017-18	43.08	43.08	पूर्ण
3	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम मंदिर में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम	2022-23	54.04	27.37	कार्यान्वयन के अधीन
4	आंध्र प्रदेश	अन्नवरम मंदिर शहर में तीर्थ पर्यटन अवसंरचना का विकास	2024-25	25.33	6.74	कार्यान्वयन के अधीन
5	अरुणाचल प्रदेश	परशुराम कुंड, लोहित जिला का विकास	2020-21	37.88	31.02	कार्यान्वयन के अधीन
6	असम	गुवाहाटी में और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास	2015-16	29.80	29.80	पूर्ण
7	बिहार	पटना साहिब का विकास	2015-16	29.62	29.62	पूर्ण
8	बिहार	गया, बिहार में विष्णुपद मंदिर में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	3.63	3.63	पूर्ण
9	बिहार	अंबिका भवानी मंदिर, सारण का विकास	2024-25	13.29	0	निविदा के चरण में है
10	छत्तीसगढ़	डोंगरगढ़, राजनंदगांव जिला, छत्तीसगढ़ में माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास	2020-21	48.44	40.19	पूर्ण
11	गोवा	बोम जीसस बेसिलिका का विकास	2024-25	16.46	4.68	कार्यान्वयन के अधीन

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
12	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	10.46	10.46	पूर्ण
13	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थयात्री सुविधाओं का विकास	2016-17	45.36	45.36	पूर्ण
14	गुजरात	सोमनाथ में प्रोमेनेड का विकास	2018-19	47.12	47.12	पूर्ण
15	गुजरात	गुजरात में अंबाजी मंदिर बनासकांठा में तीर्थ सुविधाओं का विकास	2022-23	50.00	30.00	कार्यान्वयन के अधीन
16	हरियाणा	पंचकुला जिले में माता मनसा देवी मंदिर और नाडा साहेब गुरुद्वारा का विकास	2019-20	48.53	34.68	कार्यान्वयन के अधीन
17	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल दरगाह, श्रीनगर का विकास	2016-17	40.46	34.30	पूर्ण
18	झारखंड	बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर का विकास	2018-19	36.79	34.95	पूर्ण
19	कर्नाटक	मैसूरु में श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास	2023-24	45.38	13.33	कार्यान्वयन के अधीन
20	कर्नाटक	रेणुका येल्लामा देवी मंदिर का विकास	2024-25	18.37	0	निविदा के चरण में है
21	कर्नाटक	पापनाश मंदिर, बीदर जिले में बुनियादी सुविधाओं का विकास	2024-25	22.25	6.30	कार्यान्वयन के अधीन
22	केरल	गुरुवायूर मंदिर का विकास	2016-17	45.19	45.19	पूर्ण
23	मध्य प्रदेश	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	42.55	पूर्ण
24	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	43.93	43.93	पूर्ण

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
25	महाराष्ट्र	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	45.41	38.44	कार्यान्वयन के अधीन
26	मेघालय	मेघालय में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास	2020-21	29.29	27.78	पूर्ण
27	मिज़ोरम	मिज़ोरम राज्य में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन के लिए अवसंरचना का विकास	2022-23	44.89	26.37	कार्यान्वयन के अधीन
28	मिज़ोरम	चंफाई जिले के वांगछिया में प्रशाद योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं का विकास	2024-25	5.47	0	कार्यान्वयन के अधीन
29	नागालैंड	नागालैंड में तीर्थयात्रा अवसंरचना का विकास	2018-19	25.20	23.56	पूर्ण
30	नागालैंड	जुन्हेबोटो में तीर्थयात्रा पर्यटन अवसंरचना का विकास	2022-23	18.18	15.45	पूर्ण
31	ओडिशा	मेगा सर्किट के अंतर्गत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम - रामचंडी - देमुली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना का विकास	2014-15	50.00	10.00	बंद कर दी गई है।
32	पुडुचेरी	श्री धरबारण्येश्वर मंदिर के लिए तीर्थयात्रा सुविधाओं और पर्यटक आकर्षणों का विकास	2024-25	25.94	0	निविदा के चरण में है
33	पंजाब	अमृतसर में करुण सागर वाल्मीकि स्थल का विकास	2015-16	6.40	6.40	पूर्ण

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
34	पंजाब	चमकौर साहिब, रोपड़, पंजाब का विकास	2021-22	30.52	23.80	कार्यान्वयन के अधीन
35	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64	26.11	पूर्ण
36	सिक्किम	युकसोम में फोर पेट्रन सेंट्स में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	28.31	पूर्ण
37	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99	पूर्ण
38	तमिलनाडु	वेलंकनी का विकास	2016-17	4.86	4.86	पूर्ण
39	तमिलनाडु	8 नवग्रह मंदिरों का विकास	2024-25	40.94		कार्यान्वयन के अधीन
40	तेलंगाना	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	38.90	33.07	पूर्ण
41	तेलंगाना	रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, मुलुगु में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन अवसंरचना का विकास	2022-23	62.00	32.73	कार्यान्वयन के अधीन
42	तेलंगाना	भद्राचलम, भद्राद्रि कोठागुडेम जिले में तीर्थयात्रा अवसंरचना का विकास	2022-23	41.38	8.43	कार्यान्वयन के अधीन
43	तेलंगाना	देवी रेणुका येल्लम्मा देवस्थानम में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2024-25	4.22	0	कार्यान्वयन के अधीन
44	त्रिपुरा	त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	34.43	28.01	कार्यान्वयन के अधीन
45	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास - चरण-I	2015-16	18.73	18.73	पूर्ण
46	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	10.98	10.98	पूर्ण

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
47	उत्तर प्रदेश	गंगा, वाराणसी में रिवर क्रूज पर्यटन	2017-18	9.02	9.02	पूर्ण
48	उत्तर प्रदेश	वृंदावन में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36	9.36	पूर्ण
49	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास - चरण - II	2017-18	44.60	35.26	पूर्ण
50	उत्तर प्रदेश	गोवर्धन में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	2018-19	37.59	30.97	पूर्ण
51	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.77	34.77	पूर्ण
52	उत्तराखंड	बद्रीनाथजी धाम में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए अवसंरचना का विकास	2018-19	56.15	38.38	कार्यान्वयन के अधीन
53	उत्तराखंड	गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रा अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि	2021-22	54.36	10.22	पूर्ण
54	पश्चिम बंगाल	बेलूर मठ का विकास	2016-17	30.03	23.39	पूर्ण
		कुल		**1726.74**	**1200.47**	

प्रशाद योजना के तहत नए चिह्नित स्थलों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ	परियोजना का नाम
1	आंध्र प्रदेश	वेदगिरी लक्ष्मी नरसिंहस्वामी मंदिर, नेल्लोर जिला
2	बिहार	सिमरिया घाट , बेगूसराय जिला
3	छत्तीसगढ़	कुदरगढ़ मंदिर, सूरजपुर जिला
4	गुजरात	श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, सुनक, मेहसाणा
5	जम्मू और कश्मीर	पुरमंडल और उत्तरबेहनी , सांबा जिला
6	मध्य प्रदेश	शनिचरादेव मंदिर, मुरैना जिला
7	महाराष्ट्र	श्री घृष्णेश्वर शिवालय , औरंगाबाद जिला
8	महाराष्ट्र	तुलजापुर , उस्मानाबाद जिला
9	महाराष्ट्र	श्री क्षेत्र राजूर , गणपति मंदिर, जालना जिला
10	ओडिशा	चौसठ योगिनी मंदिर, रानीपुर , झरियाल , बलांगीर जिला
11	ओडिशा	मां किचकेश्वरी मंदिर, किचिंग , मयूरभंज जिला
12	पंजाब	दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर जिला
13	राजस्थान	सूर्य मंदिर, बूढ़ाहिता , कोटा जिला
14	उत्तर प्रदेश	आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री काली मंदिर , चौक, लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश	ब्रज के तीर्थ स्थल
16	उत्तराखंड	टिम्मर्सियन महादेव (देवनाथ), चमोली जिला

प्रशाद योजना के तहत पूर्ण घटकों के चित्र

कुसुम सरोवर, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश में प्रकाश व्यवस्था

पर्यटक सुविधा केंद्र, वृंदावन, उत्तर प्रदेश

सोमनाथ, गुजरात में सैरगाह

शिवगंगा तालाब, देवघर, झारखंड

सोमनाथ, गुजरात में सैरगाह

अमरावती, आंध्र प्रदेश में ध्यान बुद्ध

3.3 पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता:

पर्यटन गंतव्य पर पर्यटन अवसंरचना का विकास, इसके लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने और समाज को दूसरे सामाजिक-आर्थिक फायदे पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवेश बना सकता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई संभावित स्थल है।

3.3.1 "पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत केंद्रीय एजेंसियों को दी गई परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्थिति
1	डल झील, (नागीन झील) में साउंड और लाइट शो,	आईटीडीसी	25-06-2012	5.00	3.08	बंद कर दी गई है
2.	चेन्नई पोर्ट में मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	24-09-2012	17.24	17.24	पूर्ण
3	तिलयार झील में मल्टीमीडिया/लेजर शो का कार्यान्वयन	आईटीडीसी	30-04-2013	5.00	2.24	पूर्ण
4	विश्व विरासत स्थल हुमायूँ का मकबरा, नई दिल्ली में व्याख्या केंद्र का निर्माण	आगा खान फाउंडेशन	04-03-2014	49.45	49.45	पूर्ण
5	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	24-06-2014	8.79	7.67	पूर्ण
6	दीव किला,दीव में साउंड और लाइट शो	आईटीडीसी	28-02-2015	7.75	6.20	पूर्ण
7	वाराणसी/सारनाथ में स्मारकों का प्रदीप्तीकरण (सारनाथ में धमेख स्तूप सारनाथ में चौखंडी स्तूप, सारनाथ में लालकान का मकबरा और बनारस में मन महल)	आईटीडीसी	28-02-2015	5.12	3.81	पूर्ण
8	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में कानोजी आंग्रे लाइटहाउस का विकास	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	09-08-2016	15.00	15.00	पूर्ण
9	विलिंगडन द्वीप, कोचीन, केरल में वॉकवे/प्रोमेनेड का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	28-10-2016	9.01	8.26	पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्थिति
10	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	31-03-2017	21.41	19.12	पूर्ण
11	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसएआई त्रिवेंद्रम गोल्फ क्लब में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए परियोजना	एसएआई	31-03-2017	24.65	9.27	बंद कर दी गई है
12	यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर, हरियाणा में साउंड और लाइट शो	आईटीडीसी	16-10-2017	6.00	3.00	बंद कर दी गई है
13	पुट्टापार्थी, आंध्र प्रदेश में साउंड और लाइट शो	आईटीडीसी	27-11-2017	7.08	3.54	भौतिक रूप से पूर्ण
14	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/ आधुनिकीकरण।	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	29-12-2017	12.50	12.50	पूर्ण
15	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में तीन स्मारकों में प्रकाश व्यवस्था : 1. दशाश्वमेधघाट से दरबंगाघाट (300 मीटर का विस्तार) 2. तुलसी मानस मंदिर 3. सारनाथ संग्रहालय	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	21-12-2017	2.94	2.94	पूर्ण
16	जेसीपी अटारी, बाघा बोर्डर में अवसंरचना विकास	बीएसएफ	12-06-2018	12.87	11.27	पूर्ण
17	मोरमुगाओ में आव्रजन सुविधा में सुधार और मौजूदा क्रूज बर्थ को गहरा करना	मोरमुगोओ पोर्ट ट्रस्ट	24-08-2018	13.16	4.91	बंद कर दी गई है
18	कोचीन पोर्ट क्रूज टर्मिनल में अवसंरचना का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	12-12-2018	1.20	1.14	पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्थिति
19	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	12-12-2018	4.66	4.66	पूर्ण
20	विशाखापत्तनम पोर्ट के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज-सह-तटीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	14-12-2018	38.50	29.91	भौतिक रूप से पूर्ण
21	अमृतसर, पंजाब में 'जलियांवाला बाग स्मारक' के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पर किये जाने वाला अतिरिक्त कार्य	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	08-03-2019	23.02	22.50	पूर्ण
22	(पुराना किला) दिल्ली में साउंड और लाइट शो	आईटीडीसी	05-08-2019	14.04	5.37	भौतिक रूप से पूर्ण
23	नए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल में अतिरिक्त अवसंरचना का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	13-12-2019	10.29	8.88	पूर्ण
24	नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के भवन में प्रकाश व्यवस्था	एनसीएसएम	19-12-2019	3.80	3.04	पूर्ण
25	राष्ट्रीय संग्रहालय की चयनित सुविधाओं का विकास और नवीनीकरण	एनसीएसएम	26-12-2019	43.73	21.86	बंद कर दी गई है
26	राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 और 2 पर नदी क्रूज के चढ़ने/उतरने के मुख्य बिंदुओं पर जेट्टी का विकास	आईडब्ल्यूएआई	28-04-2020	28.03	7.01	जारी है
27	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बेलताल झील, दमोह, मध्य प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना	आईटीडीसी	29-09-2020	23.15	10.08	भौतिक रूप से पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्थिति
28	लेह, लद्दाख में साउंड और लाइट शो और पर्यटक सुविधा केंद्र, कारगिल, लद्दाख में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया शो	आईटीडीसी	26-11-2020	23.22	5.15	जारी है
29	एनजीएमए भवन की 3डी विजुअल प्रोजेक्शन मैपिंग	एनसीएसएम	31-03-2021	6.16	4.64	भौतिक रूप से पूर्ण
30	आइजोल में कन्वेंशन सेंटर और संबद्ध अवसंरचना का विकास	वैपकोस	31-03-2021	39.94	31.09	जारी है
31	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल और संबंध सुविधाओं का निर्माण	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	10-09-2021	50.00	40.00	जारी है
32	इंदिरा डॉक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/ आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	20-12-2021	37.50	30.00	जारी है
33	उत्तर-पूर्वी राज्य में 22 व्यू पॉइंट का विकास	एन एच आई डी सी एल	11-10-2022	44.44	35.55	जारी है
34	श्री तनोट कॉम्प्लेक्स, जैसलमेर सेक्टर में सीमा पर्यटन का विकास	बीएसएफ	05-07-2022	17.67	8.83	जारी है
35	संजीवैया पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना में वॉटर स्क्रीन और म्यूजिकल फाउंटेन सहित मल्टीमीडिया लेजर शो	बीईसीआईएल	31-10-2022	50.00	40.90	भौतिक रूप से पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्थिति
36	उस्मानिया कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद तेलंगाना में डिजिटल मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी और प्रकाश व्यवस्था की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं शुरूआत	बीईसीआईएल	22-12-2022	11.79	9.43	भौतिक रूप से पूर्ण
37	परियोजना राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का बड़े स्तर पर उन्नयन	एनसीएसएम	27-03-2023	31.80	0.18	जारी है
38	नवलसागर झील, बूंदी में म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन मल्टीमीडिया आधारित प्रोजेक्शन शो की स्थापना	आईटीडीसी	04-10-2023	9.25	2.13	जारी है
39	राष्ट्रपति भवन में साउंड और लाइट और मल्टीमीडिया शो का विकास	आईटीडीसी	28-03-2024	47.12	9.71	जारी है
40	बक्सर, बिहार में एक्वास्क्रीन प्रोजेक्शन और सांउड शो सहित 3डी मैकिंग और रामरेखा घाट, बिहार में डायनामिक लाइटिंग और मोटिफ	बीईसीआईएल	10-06-2024	5.99	0.59	जारी है
41	गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिला अरियालुर में प्रकाश व्यवस्था और संबंधित कार्य	आईटीडीसी	31-03-2025	11.47	0	जारी है

3.3.2 रेलवे मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 50:50 की साझा लागत के आधार पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2013-14	5	26.49	21.42
2	2014-15	2	10.40	9.42
3	2016-17	5	26.90	21.16
4	2017-18	4	17.76	10.28
5	2018-19	3	14.43	11.91
6	2019-20	2	9.54	4.76
7	2020-21	1	3.02	1.51
	कुल	**22**	**108.54**	**80.46**

इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	परियोजना की स्थिति
1	अमृतसर रेलवे स्टेशन	5.84	4.68	जारी है
2	राय-बरेली रेलवे स्टेशन	4.44	3.55	बंद कर दी गई है
3	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन (टीवीसी)	5.98	4.00	भौतिक रूप से पूर्ण
4	गया रेलवे स्टेशन	5.18	4.14	भौतिक रूप से पूर्ण
5	आगरा कैंट रेलवे स्टेशन	5.05	5.05	पूर्ण
6	अजमेर रेलवे स्टेशन	5.52	5.52	पूर्ण
7	जयपुर रेलवे स्टेशन	4.88	3.90	बंद कर दी गई है
8	हैदराबाद रेलवे स्टेशन	4.41	3.52	भौतिक रूप से पूर्ण
9	नांदेड़ रेलवे स्टेशन	5.18	2.59	बंद कर दी गई है
10	तिरुपति रेलवे स्टेशन	5.75	4.59	भौतिक रूप से पूर्ण
11	होस्पेट रेलवे स्टेशन	5.41	4.32	भौतिक रूप से पूर्ण
12	पुरी रेलवे स्टेशन	6.15	6.14	पूर्ण
13	रामेश्वरम रेलवे स्टेशन	4.70	3.75	पूर्ण
14	औरंगाबाद रेलवे स्टेशन	5.71	2.85	बंद कर दी गई है
15	रामपुरहाट रेलवे स्टेशन	3.48	1.74	भौतिक रूप से पूर्ण
16	तारकेश्वर रेलवे स्टेशन	3.87	1.93	जारी है
17	मदुरै रेलवे स्टेशन	4.48	3.56	भौतिक रूप से पूर्ण
18	कामाख्या रेलवे स्टेशन	4.96	4.02	पूर्ण
19	गुवाहाटी रेलवे स्टेशन	4.99	4.34	पूर्ण
20	न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन	4.55	2.27	बंद कर दी गई है
21	चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन	4.99	2.50	जारी है
22	कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन	3.02	1.51	बंद कर दी गई है

3.3.3 स्वीकृत अन्य रेलवे परियोजनाएं

I. **3 ग्लास टॉप कोच का निर्माण:** स्वीकृत और जारी की गई राशि 12.00 करोड़ रुपये। यह परियोजना ₹12.00 करोड़ की लागत से पूरी हुई।

- विजाग-अराकू घाटी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
- मार्ग दादर-मडगांव, मुंबई से गोवा
- क़ाज़ीगुंड- बारामूला, जम्मू और कश्मीर

II. **केआरसीएल के तहत 3 रेलवे स्टेशनों का विकास:** मडगांव, थिविम और करमाली रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए कुल 25.00 करोड़ रुपये (पूरी तरह से पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित) मंज़ूर किए गए है, जिसमें से अब तक 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके है।

iii. **कांचीगुडा रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग के अग्रभाग में प्रकाश व्यवस्था:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100% वित्तीय सहायता के साथ कांचीगुडा रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग के अग्रभाग में प्रकाश व्यवस्था को ₹3.41 करोड़ की कुल लागत से मंज़ूरी दी गई। यह परियोजना 2.24 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई।

****

ब्रिटिश रेजीडेंसी, उत्तर प्रदेश

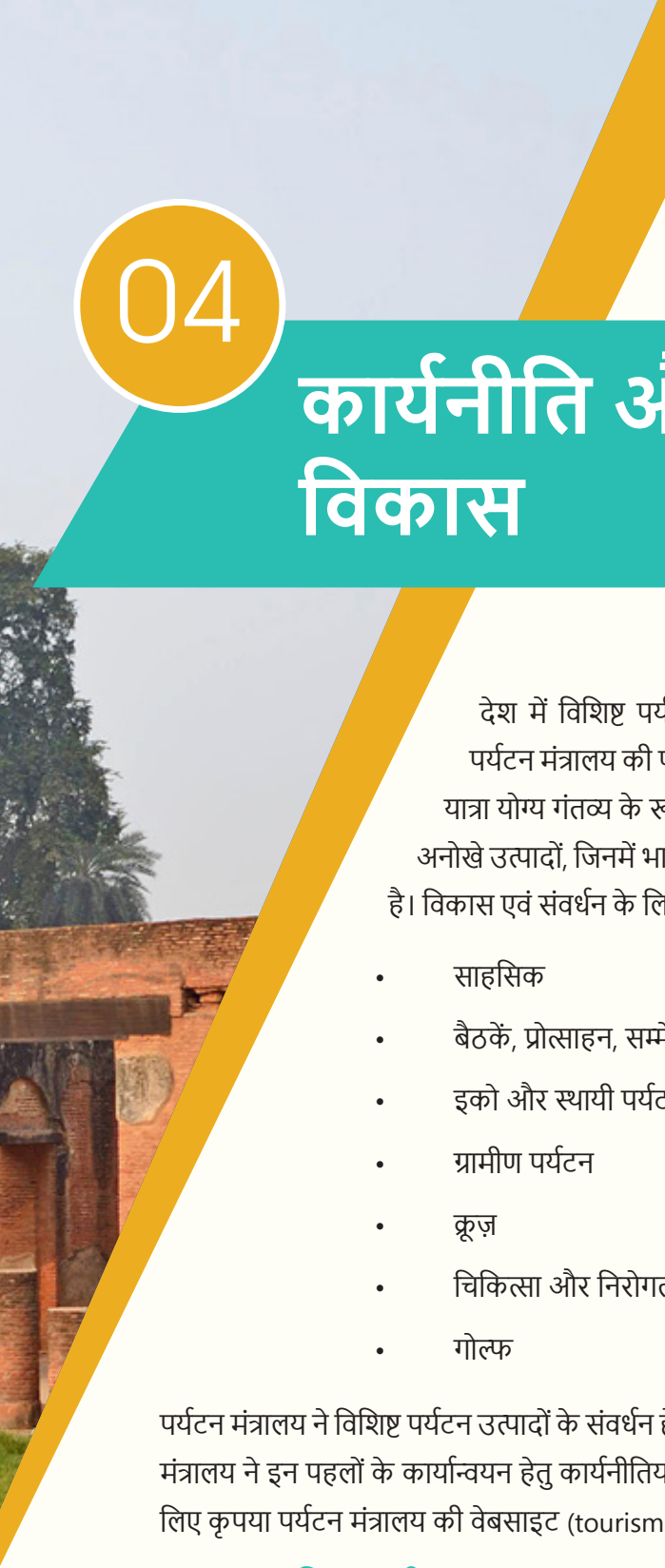

04 कार्यनीति और उत्पाद विकास

देश में विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन संबंधी पर्यटन मंत्रालय की पहल का उद्देश्य मौसमी प्रभाव को कम करना तथा भारत को वर्ष पर्यन्त यात्रा योग्य गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करना और अनोखे उत्पादों, जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, के लिए बार-बार यात्रा सुनिश्चित करना है। विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उत्पाद चिह्नित किए गए है :

- साहसिक
- बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)
- इको और स्थायी पर्यटन
- ग्रामीण पर्यटन
- क्रूज़
- चिकित्सा और निरोगता
- गोल्फ

पर्यटन मंत्रालय ने विशिष्ट पर्यटन उत्पादों के संवर्धन हेतु बोर्डों, कार्यबलों और समितियों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इन पहलों के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीतियाँ और दिशानिर्देश तैयार किए है। अधिक जानकारी और दस्तावेज़ों के लिए कृपया पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट (tourism.gov.in) देखें।

4.1 साहसिक पर्यटन

साहसिक पर्यटन एक प्रकार का विशिष्ट पर्यटन है जिसमें दूरस्थ, अनूठे और संभवतः प्रतिकूल क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जानना या उनकी यात्रा करना शामिल है। इसमें अक्सर ऐसे कार्यकलाप शामिल होते है जिनमें शारीरिक और कुछ हद तक जोखिम होता है, जो प्रतिभागियों को उत्साह और रोमांच से भर देते है। साहसिक पर्यटन में विविध कार्यकलाप और स्थल शामिल है और यह बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो गया है क्योंकि लोग अनोखे और यादगार अनुभव की तलाश में रहते है।

- पर्यटन मंत्रालय की राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन कार्यनीति का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर साहसिक पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है और इसमें साहसिक पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक स्तंभों को चिह्नित किया गया है :

  (i) राज्यों का आकलन, रैंकिंग और कार्यनीति

  (ii) कौशल, क्षमता निर्माण और प्रमाणन

  (iii) विपणन और संवर्धन

  (iv) साहसिक पर्यटन के सुरक्षा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना

  (v) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बचाव और संचार ग्रिड

  (vi) गंतव्य और उत्पाद विकास

  (vii) शासन और संस्थागत कार्य ढांचा

- सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें चिह्नित केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और औद्योगिक हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल है। यह बोर्ड देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कार्यनीति के संचालन और कार्यान्वयन का कार्य करेगा जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

  (i) विस्तृत कार्य योजना और समर्पित योजना तैयार करना

  (ii) प्रमाणन योजना

  (iii) सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश

  (iv) क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों की प्रतिकृति

  (v) राज्यों की नीतियों का आकलन और उनकी रैंकिंग

  (vi) विपणन और संवर्धन

  (vii) गंतव्य और उत्पाद विकास

  (viii) निजी क्षेत्र की भागीदारी

  (ix) साहसिक पर्यटन के लिए विशिष्ट कार्यनीतियाँ

  (x) देश में साहसिक पर्यटन के विकास के लिए अन्य उपाय।

- पर्यटन मंत्रालय ने स्वैच्छिक दिशानिर्देश जारी किए है, जिनमें भूमि, जल और वायु आधारित पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को वर्गीकृत किया गया है। इन दिशानिर्देशों में अनुपालन और संदर्भ हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है।

4.2. बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनियां (एमआईसीई)

- बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (एमआईसीई) पर्यटन उद्योग का एक विशेष खंड है जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजनों और सभाओं की योजना बनाना और आयोजन करना शामिल है। एमआईसीई का प्रत्येक घटक एक अलग प्रकार के आयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सभी घटक एकसाथ मिलकर वैश्विक पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते है।

- पर्यटन मंत्रालय ने एक एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 'मीट इन इंडिया' नामक एक विशिष्ट ब्रांड की शुरूआत की है। राज्यों और उद्योगों के सहयोग से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हें। पर्यटन मंत्रालय ने भारत का एक विवाह गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए 'इंडिया सेज़ आई डू' नामक अभियान की भी शुरूआत की है।

- मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 4 से 6 मई 2025 तक जयपुर के नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक एमआईसीई गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शीर्ष सरकारी अधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय एमआईसीई संचालकों, आतिथ्य क्षेत्र के हस्तियों और मीडिया सहित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर, इस सम्मेलन ने वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप नीति, बुनियादी ढांचे और ब्रांडिंग को पुनर्गठित करने के लिए एक सहयोगात्मक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में नीतिगत नवाचार, अवसंरचना विकास और भारत की एमआईसीई संबंधी क्षमताओं के विपणन पर केंद्रित उच्च-प्रभावशाली सत्र आयोजित किए गए।

मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव

- पर्यटन मंत्रालय ने इंडियन एग्जिबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) के समन्वय से 29 जुलाई 2025 को चेन्नई में एमआईसीई साउथ इंडिया थॉट लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एसआईटीएलसी) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने भारत के बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक एमआईसीई हब के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया।

आईईआईए माइस उद्योग लीडर्स कनेक्ट – फोकस साउथ

4.3. इको और स्थायी पर्यटन

- स्थायी पर्यटन, आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण और मेजबान समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करता है। इको पर्यटन, स्थायी पर्यटन का एक रूप है जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के परिरक्षण और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदारीयुक्त यात्रा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता परिरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता और सामुदायिक समावेशण जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित शैक्षिक और समृद्ध अनुभव प्रदान करते हुए पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।
- भारतीय पर्यटन क्षेत्र में स्थायित्व को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन के लिए भारत को एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए इको और स्थायी पर्यटन राष्ट्रीय कार्यनीतियों की शुरुआत की।
- पर्यटन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 2025 को नई दिल्ली में 'देश में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना' विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सतत पर्यटन के महत्व पर बल दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय विकास पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और समुदाय को समान लाभ पहुंचाने के साथ-साथ चलता है। यह भी बताया गया कि पर्यटन स्वाभाविक रूप से अंतर-क्षेत्रीय है—जो संस्कृति, बुनियादी ढांचे, आजीविका और पर्यावरण से जुड़ा है—और इसलिए इसके लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सतत पर्यटन विकास: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कार्यशाला एवं परामर्श

ट्रैवल फॉर लाइफ - मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली), भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो लोगों और समुदायों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करने का आग्रह करता है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थायी कार्य पद्धतियों को विकसित करने हेतु पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए मिशन लाइफ के तहत 'ट्रैवल फॉर लाइफ' (टीएफएल) कार्यक्रम शुरू किया। 'ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफ़एल) कार्यक्रम में स्थायी, जिम्मेदारीयुक्त और लचीले पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन क्षेत्र में

स्थायित्व को मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना की गई है। स्थायी पर्यटन के लिए किसी गंतव्य की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं को पहचानना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को सकारात्मक कार्यों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसे सांस्कृतिक स्थिरता को बढ़ावा देने संबंधी चर्चाओं में एकीकृत किया जा सकता है।

4.4 ग्रामीण पर्यटन

ग्रामीण पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास और रोजगार को बढ़ाने में बड़ा योगदान दे सकता है। गांव देश की संस्कृति, परंपरा, शिल्प, विरासत और कृषि-प्रथाओं के भंडार भी है। पर्यटन के माध्यम से इन स्थानीय उत्पादों को विकसित और प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा किया जा सकता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और इस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सकता है। अनुभवात्मक पर्यटन की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच, ग्रामीण पर्यटन पर्यटकों को ग्रामीण भारत के प्रचुर और अनूठे अनुभवों का आनंद लेने के लिए गांवों की यात्रा करने हेतु आमंत्रित करता है। देश में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावना को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने इस अंतर्निहित क्षमता का लाभ उठाने और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गतिशील, जिम्मेदारीयुक्त और स्थायी पर्यटन परिवर्तश बनाने की दृष्टि से भारत में ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां और रोडमैप तैयार किए है।

ग्रामीण पर्यटन के तहत पहलें

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता

राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुरूप, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य उन गांवों को सम्मानित करना है जो लोकप्रिय सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिसंपत्तियों वाले पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो समुदाय-आधारित मूल्यों, वस्तुओं और जीवन शैली को संरक्षित और बढ़ावा देते है और पर्यटन को सकारात्मक बदलाव के साधनों में से एक बनाने के व्यापक लक्ष्य के साथ, विकास, और सामुदायिक कल्याण के साथ अपने सभी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं में स्थायित्व हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इस प्रतियोगिता ने गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रेरित किया है और उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और चिरस्थायी रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करके वैश्विक ग्रामीण पर्यटन स्थलों के बीच अपनी आकर्षण क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया है। स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त यात्रा के प्रति बढ़ती जागरूकता और मांग के साथ-साथ इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि पर्यटन का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे। वर्ष 2023 और 2024 में आयोजित प्रतियोगिता के दो संस्करणों में, भारत के 71 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया था। कनेक्टिविटी, विपणन और डिजिटल अवसंरचना जैसी प्रमुख चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सत्रों और कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों और सामुदायिक जुड़ाव के मॉडल को रेखांकित करते हुए विजयी गांवों के लिए परिचय यात्राओं का आयोजन किया गया।

यूएनडब्ल्यूटीओ की 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' पहल में भागीदारी

पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' पहल में भाग लेता है, जो भारत के लिए स्थायित्व, संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन में अपनी पहलों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर

है। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा चुने गए गाँव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव नेटवर्क के सदस्य है। अपने सदस्यों के लिए नेटवर्क के मुख्य लाभों में ग्रामीण पर्यटन संबंधी एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा होना, उनके सर्वोत्तम अनुभवों को सीखना और साझा करना तथा विश्व स्तर पर पहचान बनाना और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन नीति संबंधी दस्तावेजों और दिशानिर्देशों में केस स्टडी के रूप में चित्रित किया जाना शामिल है। वर्ष 2021 संस्करण में, तेलंगाना में पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2022 में, नागालैंड में खोनोमा को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वर्ष 2023 में कच्छ, गुजरात के धोरडो गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया था और मध्य प्रदेश के मडला गाँव को उन्नयन कार्यक्रम के लिये चुना गया था। वर्ष 2024 में धुड़मारस, छत्तीसगढ़ को उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है।

राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गांवों के लिए परिचय यात्रा आयोजित की गई थीं।

4.5 क्रूज पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों की सहायता' योजना के अंतर्गत, क्रूज पर्यटन और नदियों के किनारे क्रूजिंग सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 तक सीट्रेड क्रूज ग्लोबल 2024, मियामी, यूएसए में भाग लिया। यह चार दिवसीय प्रदर्शनी दुनिया भर में क्रूज शिप उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन था। प्रतिनिधिमंडल ने क्रूज लाइनों, बंदरगाहों, गंतव्यों, टूर ऑपरेटरों, एसोसिएशनों, सीएलआईए, सीट्रेड आदि सहित क्रूज उद्योग के सभी पहलुओं को कवर करते हुए वैश्विक क्रूज व्यवसाय के हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की।

पर्यटन मंत्रालय ने 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक कॉन्क्लेव में भाग लिया, जहां उद्योग के रुझानों, समुद्री क्षेत्र संबंधी सुधारों और निवेश के अवसरों पर उच्च स्तरीय चर्चाएं हुईं।

क्रूज़ पर्यटन संबंधी कार्यबल

देश की तटरेखा और इसके अंतर्देशीय जलमार्गों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनांए है। इसका लाभ उठाने के लिए, सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता और सचिव (पोत परिवहन) की सह-अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल में बंदरगाहों, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क विभाग, सीआईएसएफ, तटीय राज्यों आदि के प्रतिनिधि शामिल है।

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025

4.6 चिकित्सा और निरोगता पर्यटन

देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है। कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है:

(i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना

(ii) चिकित्सा और निरोगता पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, सारमोली गांव, उत्तराखंड और डावर गांव, जम्मू एवं कश्मीर

(iii) ऑनलाइन चिकित्सा मूल्य यात्रा (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को सुगम बनाना

(iv) चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए पहुंच में वृद्धि

(v) निरोगता पर्यटन

(vi) शासन और संस्थागत कार्य ढांचा को बढ़ावा देना

4.7 गोल्फ पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए है। मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के तहत भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड के साथ मिलकर उसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र गोल्फ आयोजनों, गोल्फ कार्यक्रमों, गोल्फ प्रबंधन, कार्यशालाओं/कार्यक्रमों/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक गोल्फ क्लबों, गोल्फ कार्यक्रम प्रबंधकों राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अनुमोदित टूर ऑपरेटरों/अनुमोदित ट्रैवल एजेंटों और कारपोरेट घरानों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। ईओआई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईजीटीसी) की अपनी बैठकों में समय-समय पर किया जाता है।

*****

पट्टडक्कल, कर्नाटक

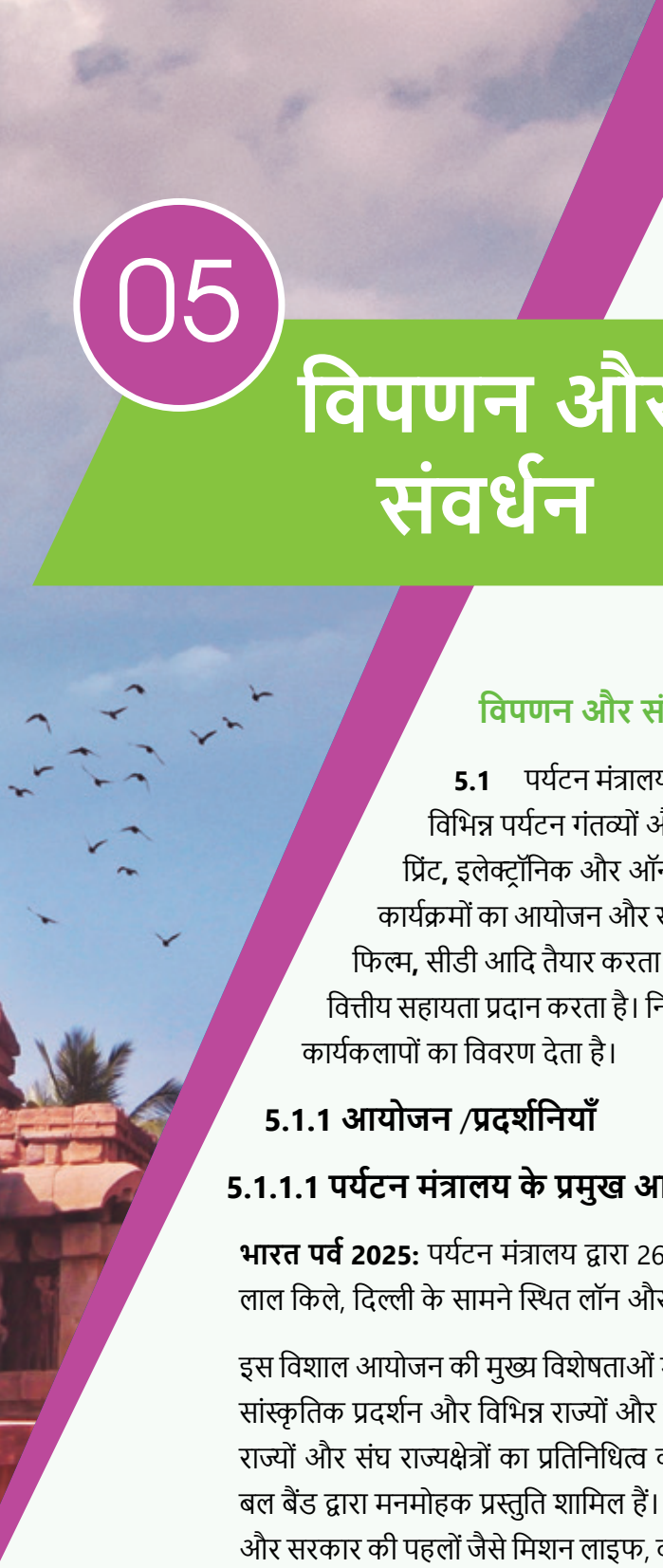

05 विपणन और संवर्धन

विपणन और संवर्धन (घरेलू) प्रभाग

5.1 पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन का समग्र रूप से संवर्धन करता है। यह मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन भी करता है, विभिन्न विषयों और गंतव्यों पर ब्रोशर, पत्रक, नक्शे, फिल्म, सीडी आदि तैयार करता है, प्रचार संबंधी कार्यकलापों के निष्पादन हेतु पर्यटन सेवाप्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित भाग सोशल मीडिया पर घरेलू स्तर पर किए गए संवर्धनात्मक कार्यकलापों का विवरण देता है।

5.1.1 आयोजन /प्रदर्शनियाँ

5.1.1.1 पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख आयोजन

भारत पर्व 2025: पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में लाल किले, दिल्ली के सामने स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया।

इस विशाल आयोजन की मुख्य विशेषताओं में गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले खाद्य स्टाल, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शन और सशस्त्र बल बैंड द्वारा मनमोहक प्रस्तुति शामिल हैं। इसमें 26 केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग द्वारा नागरिक केंद्रित योजनाओं और सरकार की पहलों जैसे मिशन लाइफ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (एक जिला एक उत्पाद), विकसित भारत, नारी शक्ति, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन किया गया। देखो अपना देश को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीक के माध्यम से एक एक्सपीरिएंश्यल ज़ोन (अनुभवात्मक क्षेत्र) भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विविध पाक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों की पेशकश करते स्टालों के साथ एक फूड कोर्ट स्थापित किया गया । सांस्कृतिक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, एक अखिल भारतीय शिल्प बाजार स्थापित किया गया, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा स्टाल थे, जिनसे समग्र प्रदर्शन को समृद्ध और जीवंत बनाया गया। मुख्य प्रदर्शनियों में 59 खाद्य स्टॉल, 70 हस्तशिल्प और हैंडलूम स्टॉल, 34 राज्य पर्यटन पवेलियन और केंद्रीय मंत्रालयों की 24 प्रदर्शनियां शामिल थी। दिल्ली स्थित विभिन्न क्षेत्रीय

सांस्कृतिक संघों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह पर्व देश भर के स्थानीय कारीगरों के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रहा है, जो अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं।

भारत पर्व 21 से 31 जनवरी, 2026

'विविधता का अमृत महोत्सव' का दूसरा संस्करण (6 और 9 मार्च, 2025): - भारत की समृद्ध विविधता के आयोजन के लिए राष्ट्रपति भवन में 'विविधता का अमृत महोत्सव' आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया। दूसरे संस्करण में दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी की विरासत और जीवंत संस्कृतियों के प्रदर्शन पर केंद्रित था।

इस महोत्सव ने कलाकारों, कारीगरों, परफॉर्मर्स, लेखकों और पाक विशेषज्ञों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनियों, साहित्यिक गतिविधियों, कार्यशालाओं और क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान दिया। इसमें 400 से ज़्यादा कलाकारों ने लोक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत रूपों का प्रदर्शन किया, जिसमें दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सार को जीवंत रूप से दिखाया गया। पर्यटन मंत्रालय ने एक परस्पर संवादात्मक क्षेत्र, एक स्टूडियो किचन एवं संबंधित दक्षिणी क्षेत्र के खाद्य स्टॉलों को स्थापित किया जिसने महोत्सव की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विविधता का अमृत महोत्सव

मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव (4 मई 2025): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से जयपुर में 14वां ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार एक्सपो के साथ-ही 'मीट इन इंडिया' कॉन्क्लेव एक्सपो का आयोजन किया।

इस समारोह में पैनल चर्चाएं हुई, जिनमें भारत की तैयारियों और भारत को एक पसंदीदा एमआईसीई गंतव्य बनाने के अवसरों, तथा भारत में सम्मेलनों और कन्वेंशनों का आयोजन करते समय समारोह योजनाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर फोकस किया गया। समारोह के दौरान, विशेषज्ञों ने भारत की तैयारियों और भारत को एक पसंदीदा एमआईसीई गंतव्य बनाने के अवसरों पर चर्चाएं की गई।

'मीट इन इंडिया' कॉन्क्लेव

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2025):-

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के अवसर पर "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम के साथ देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में 40 सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें निरोगता को पर्यटन से जोड़ते हुए तथा भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाया गया।

समारोह में नागरिकों, पर्यटकों, छात्रों, योग चिकित्सकों और गणमान्य व्यक्तियों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें 11 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे, जो योग के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करते हैं। योग विशेषज्ञों ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा के एक कालातीत उपहार के रूप में रेखांकित किया, जो समग्र स्वास्थ्य और आत्म-साक्षात्कार को बढ़ावा देता है, और संयुक्त राष्ट्र के अपनाने के बाद से वर्ष 2015 में इसके वैश्विक महत्व को बढ़ावा मिल रहा है।

निरोगता पर्यटन को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने स्वस्थ खाद्य महोत्सव आयोजित करने, पौष्टिक क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन करने एवं रूचिकर खाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आईएचएम और आईसीआई का लाभ लिया। इस पहल को व्यापक डिजिटल आउटरीच और सोशल मीडिया अभियानों द्वारा जोड़ा गया, जिससे विशेष रूप से युवाओं और वैश्विक दर्शकों के बीच सार्वजनिक जुड़ाव और पहुंच में वृद्धि हुई।

कुल मिलाकर, आईडीवाई 2025 समारोह ने योग, संस्कृति और पर्यटन के सामन्जस्य को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया, निरोगता पर्यटन के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया और स्वास्थ्य एवं सद्भाव की अपनी स्थायी विरासत को बढ़ावा दिया।

विश्व पर्यटन दिवस- (27 सितंबर, 2025): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2025 को वैश्विक थीम "पर्यटन और सतत परिवर्तन" के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने सरकार, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित हितधारकों को एक साथ किया, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इस आयोजन में मुख्य आकर्षणों में नेटफ्लिक्स, अतिथि फाउंडेशन और प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (ओटीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर शामिल थे। नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी का उद्देश्य सिनेमाई कहानी कहने, क्यूरेटेड ट्रेलरों और भारत यात्रा को प्रेरित करने के लिए वैश्विक पहुंच का लाभ पाकर भारतीय गंतव्यों को बढ़ावा देना है। अतिथि फाउंडेशन और ओटीए के साथ समझौता ज्ञापन कार्यनीतिक अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और यात्रा के बाद आगंतुक प्रतिक्रिया संग्रह को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा डेटा-संचालित नीतिगत निर्णय लेने में और सक्षम बनाया जा सके।

भारत पर्यटन डेटा संग्रह का विमोचन

विश्व पर्यटन दिवस

वर्ल्ड फूड इंडिया: भारत की बहुमूल्य पाक कला का पुनरूत्थान (25-28 सितंबर 2025):-

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण के भाग के रूप में 25-28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया - रिवाइविंग द क्यूलिनरी ट्रेजरेस ऑफ इंडिया" शीर्षक से एक विशेष पाक कला कार्यक्रम का आयोजन किया। चार दिवसीय कार्यक्रम में भारत की समृद्ध पाक विरासत को दर्शाया गया तथा इसका उद्देश्य भारतीय व्यंजनों को वैश्विक मंच पर स्थापित करना था।

यह पहल विस्मृत खाद्य परंपराओं का पुनः शुरु करने, खाना पकाने की प्राचीन तकनीकों को दर्शाने और स्वदेशी सामग्रियों की निर्यात क्षमता की खोज करने पर केंद्रित थी। इसमें प्रसिद्ध शेफ, खाद्य इतिहासकारों, पाक विशेषज्ञों

और उद्योग जगत के नेताओं की भागीदारी से पैनल चर्चा, इंटरैक्टिव मास्टरक्लास और प्रामाणिक भोजन नमूना सत्र शामिल थे। प्रमुख विषयों में जीआई-टैग सामग्री का पुनरुद्धार, आयुर्वेद-आधारित खाद्य परंपराएं, मोटे अनाज के नवाचार और स्वदेशी खाद्य-आधारित स्थिरता प्रथाएं शामिल हैं, जो स्थायी और विविध गैस्ट्रोनॉमी के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करती हैं।

विश्व खाद्य भारत भारत के पाककला खजाने को पुनर्जीवित कर रहा है

मैसूरु संगीत सुगंधा महोत्सव (11-12 अक्टूबर, 2025) - मंत्रालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव 11 और 12 अक्टूबर 2025 को मैसूर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव ने संगीत, संस्कृति और पर्यटन के संगम का जश्न मनाया, जिसका लक्ष्य मैसूर को एक प्रमुख संगीत पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक और हिंदुस्तानी परंपराओं के 106 कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की वोकल फॉर लोकल और देखो अपना देश पहल के अनुरूप कर्नाटक के क्षेत्रीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और हथकरघा का भी प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव को दर्शकों और मीडिया से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में मैसूर की स्थिति को मजबूत किया और पर्यटन के माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

इस महोत्सव ने व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया और कलाकारों, शिल्पकारों एवं पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। लाइव-स्ट्रीम किए गए प्रदर्शनों ने इस कार्यक्रम की पहुंच को बढाया, जिससे वैश्विक दर्शकों को कर्नाटक की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ा गया।

मैसूरु संगीत सुगंध महोत्सव

"राष्ट्रीय एकता दिवस – भारत पर्व 2025" एकता नगर, गुजरात (1-15 नवंबर 2025): सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के भाग के रूप में, भारत सरकार ने भारत की सांस्कृतिक, पाक और कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए 1 से 15 नवंबर 2025 तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, गुजरात में "राष्ट्रीय एकता दिवस – भारत पर्व 2025" का आयोजन किया। पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा आयोजित, इस कार्यक्रम को भारत पर्व की तर्ज पर क्यूरेट किया गया था और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के साथ जोड़ा गया।

पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत थीम पवेलियन, आईएचएम अहमदाबाद के माध्यम से स्टूडियो किचन, एनएएसवीआई के माध्यम से अखिल भारतीय फूड स्टॉल स्थापित किए और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन पवेलियन के लिए समन्वय किया। अतुल्य भारत पवेलियन (100 वर्ग मीटर) में पर्यटन, वन्य जीवन, निरोगता, व्यंजन, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को स्थलों पर इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित किए गए। पच्चीस राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पर्यटन पवेलियनों के माध्यम से भाग लिया, जबकि स्टूडियो किचन और पैन-इंडिया फूड स्टॉल ने 30 से अधिक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के क्षेत्रीय, जनजातीय, बाजरा-आधारित व्यंजनों और स्ट्रीट फूड का प्रदर्शन किया, जिससे भारत पर्व 2025 विविधता में एकता का एक सफल आयोजनकर्ता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मंच बन गया।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) (13–16 नवंबर, 2025) :- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का 13वां संस्करण 13 से 16 नवंबर, 2025 तक सिक्किम के गंगटोक में आयोजित किया गया था। आईटीएम पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, वियतनाम और अन्य सहित लगभग 19 देशों के प्रतिनिधियों सहित विश्व के 500 प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम में 45 अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, 3 अंतर्राष्ट्रीय इंफ्लयुएंसर, 50 घरेलू क्रेता, 9 घरेलू इंफ्लयुएंसर एवं ट्रैवल मीडिया और क्षेत्र के 90 विक्रेता शामिल हुए। मार्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकनीकी सत्रों, पैनल चर्चाओं, उत्पाद प्रस्तुतियों और बी2बी बैठकों की एक श्रृंखला शामिल की गई थी। संबंधित मंत्रालयों के साथ फिल्म पर्यटन, क्षेत्र में इनर लाइन परमिट के मुद्दों आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, सभी 7 राज्यों ने इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक और नए पर्यटन उत्पादों और विकास का प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों द्वारा उत्पाद प्रस्तुतियों में नदी क्रूज पर्यटन, वन्यजीव, होमस्टे और आतिथ्य, सांस्कृतिक पर्यटन, स्थिरता और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

'कृष्णवेणी संगीत नीरजनम (6–7 दिसंबर 2025) :- कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का तीसरा संस्करण 6 से 7 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संस्कृति और वस्त्र मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया गया, और आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक संगीत एवं तेलुगु संस्कृति की समृद्ध विरासत का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की जीवंत संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करना, स्थानीय कारीगरों और कलाकारों का समर्थन करना और युवाओं के बीच आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देना

था। इसने कर्नाटक संगीत के साथ संबंध को प्रेरित करने और आंध्र प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने की भी मांग की गई।

संगीत कार्यक्रमों के साथ-ही, आंध्र प्रदेश के जीआई-टैग और पारंपरिक शिल्प एवं वस्त्रों की एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी में कोंडापल्ली के खिलौने, एटिकोप्पका लेकवेरवेयर, उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, लेदर पप्पेटरी, नरसापुर लेस और मंगलगिरी, वेंकटगिरी, चिराला, उप्पाडा एव मोरागुडी सहित प्रसिद्ध हथकरघा समूहों का प्रदर्शन किया गया।

इस प्रदर्शनी ने वोकल फॉर लोकल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिससे कारीगरों और बुनकरों को दर्शकों एवं बाजारों से सीधे जुड़ने में मदद मिली।

कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025 ने संगीत, शिल्प और पाक विरासत को जोड़ा, स्थानीय समुदायों का सहयोग करते हुए सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध बनाया। इसने आगामी सांस्कृतिक पर्यटन पहलों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया, जो भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

5.1.2 ई-ब्रोशर/कोलैटरल/क्रिएटिव/फिल्मों का विकास

भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय विविध भाषा वाले बाजारों में व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न विषयों पर क्रिएटिव विकसित करता रहता है ताकि देश के विषयगत पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके।

23 से 31 जनवरी तक लाल किला लॉन, नई दिल्ली में आयोजित भारत पर्व के मेगा फेस्टिवल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश का प्रचार करते हुए 7 प्रिंट क्रिएटिव विकसित किए गए। प्रिंट क्रिएटिव का उपयोग दिल्ली एनसीआर में दैनिक पत्रों और समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के लिए भी किया गया था।

कृष्णवेणी संगीता नीराजनम

5.1.3 ब्रांडिंग संबंधी कार्यकलाप

गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में 23 से 31 जनवरी तक आयोजित मेगा फेस्टिवल 'भारत पर्व' के अवसर पर, मंत्रालय ने एनसीआर में समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन जारी किए और कार्यक्रम की ब्रांडिंग की।

5.1.4 सोशल मीडिया प्रमोशन

i. पर्यटन मंत्रालय द्वारा @tourismgoi और @yuvatourism हैंडल पर सोशल मीडिया प्रचार किया गया। @ tourismgoi के फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे 05 अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट हैं, जबकि @yuvatourism के 4 हैंडल पर अकाउंट हैं।

ii. पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलों का व्यापक संवर्धन और प्रचार किया गया है।

iii. पर्यटन उत्पादों और विरासत पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्थायी पर्यटन, मेलों और उत्सवों आदि जैसे विषयों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई विविध पहलों का सोशल मीडिया प्रचार किया गया।

iv. निधि, साथी, स्वदेश दर्शन और प्रशाद जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय की पहल और अवसंरचना परियोजनाओं को पूरे वर्ष विधिवत रूप से उजागर और प्रचारित किया गया।

v. पर्यटन मंत्रालय के एसएम हैंडल के माध्यम से एक निरंतर सोशल मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के परिणामस्वरूप फोलोअर्स और संपर्कता में वृद्धि हुई है।

@ tourismgoi –31 दिसम्बर 2025 तक की स्थिति के अनुसार

एक्स (पूर्व में ट्विटर) - 395 हजार फोलोअर्स

फेसबुक – 237 हजार फोलोअर्स

इंस्टाग्राम – 219 हजार फोलोअर्स

5.1.5 आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना

- घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए और घरेलू पर्यटक यात्राओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप चलाता है।
- इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देना है। सामाजिक जागरूकता संबंधी संदेश फैलाना और ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना जो पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।

5.1.6 उत्सव पोर्टल

उत्सव पोर्टल वेबसाइट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित और शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी कार्यक्रमों, महोत्सवों और लाइव दर्शनों का प्रदर्शन करना है। ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा दिया जा सके यह पोर्टल महोत्सवों, कार्यक्रमों और ऑनलाइन पूजा/आरती पर माह-वार और राज्यवार कैलेंडर सामग्री प्रदर्शित करता है। उत्सव पोर्टल को श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय मंत्री (पर्यटन, संस्कृति और डीओएनईआर) द्वारा नई दिल्ली में 12-13 अप्रैल 2022 को आयोजित 'अमृत समागम सम्मेलन' के उद्घाटन दिवस पर लॉन्च किया गया था। उत्सव पोर्टल का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में सभी कार्यक्रमों, महोत्सवों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करना है। पोर्टल पर https://utsav.gov.in/द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस पोर्टल में अब विस्तृत आकर्षणों के साथ 28 राज्यों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों में 1196 से अधिक कार्यक्रमों, महोत्सवों और 55 से अधिक लाइव दर्शनों की जानकारी शामिल है। यह वेबसाइट डायनेमिक है और समय-समय पर अपडेट की जाने वाली सभी आगामी घटनाओं, महोत्सवों और प्रदर्शनियों के बारे में अतिरिक्त नई जानकारी के साथ लगातार विकसित हो रही है। उत्सव पोर्टल में आधिकारिक सोशल मीडिया लिंक, आधिकारिक वेबसाइट, ब्रोशर, आयोजन समिति के संपर्क विवरण और हवाई, रेल और सड़क के माध्यम से आसानी से गंतव्य तक पहुंचने का विवरण भी होगा, इस प्रकार पर्यटकों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा और आगंतुकों को इन गंतव्यों की यात्रा की योजना बनाने में सहायता मिलेगी। गहन अनुभव-आधारित सामग्री वेबसाइट पर कला और संस्कृति, आध्यात्मिक, संगीत, मौसम का प्रभाव, पाक कला, नृत्य, खेल और साहसिक, हार्वेस्ट और एक्सपो तथा प्रदर्शनियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्ध कराई जाती है। एक खंड है जो भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों को सूचीबद्ध करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री इन महोत्सवों के लिए अपनी यात्राओं की योजना पहले से ही बनाया जा सकें। वेबसाइट का उद्देश्य पर्यटन जागरूकता, आकर्षण और यात्रा के अवसरों को बढ़ाते हुए सम्मोहक, संबद्ध और प्रासंगिक डिजिटल अनुभवों के साथ पर्यटकों की सहायता करके वैश्विक क्षेत्र में महोत्सवों की भूमि, भारत के सौंदर्य को प्रदर्शित करना है।

5.1.7 अतुल्य भारत वेबसाइट

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया। अतुल्य भारत कंटेंट हब एक व्यापक डिजिटल भंडार है, जिसमें भारत में पर्यटन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक समृद्ध संग्रह है। यह भंडार टूर ऑपरेटरों, पत्रकारों, छात्रों, शोधकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं, लेखकों, इंफ्लुएंसर्स, सामग्री निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और राजदूतों सहित विविध हितधारकों के उपयोग के लिए है। कंटेंट हब, जो नए अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल का हिस्सा है, का उद्देश्य दुनिया भर में यात्रा व्यापार (ट्रैवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट) के लिए अतुल्य भारत पर उनकी जरूरत की हर चीज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर पहुंच को आसान और सुविधाजनक बनाना है, ताकि वे अपने सभी विपणन और प्रचार प्रयासों में अतुल्य भारत का प्रचार कर सकें। कंटेंट हब के पास वर्तमान में लगभग 5,000 सामग्री परिसंपत्तियां हैं। इस संग्रह पर उपलब्ध सामग्री पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय और अन्य सहित कई संगठनों द्वारा सहयोगात्मक प्रयास का एक उत्पाद है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल एक पर्यटक-केंद्रित, वन-स्टॉप डिजिटल समाधान है जिसे भारत आने वाले आगंतुकों के यात्रा अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संशोधित पोर्टल यात्रियों को उनकी यात्रा के

हर चरण में खोज और अनुसंधान से लेकर योजना, बुकिंग, यात्रा और वापसी तक आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है। संशोधित पोर्टल वीडियो, चित्र और डिजिटल मानचित्र जैसी मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करते हुए गंतव्यों, आकर्षणों, शिल्प, महोत्सवों, यात्रा डायरी, यात्रा कार्यक्रमों, और बहुत कुछ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म का 'बुक योर ट्रैवल' फीचर उड़ानों, होटलों, कैब, बसों और स्मारकों के लिए बुकिंग सुविधा प्रदान करता है, जिससे यात्रियों के लिए पहुंच बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, एआई-संचालित चैटबॉट प्रश्नों के उत्तर देने और यात्रियों को वास्तविक जानकारी प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल सहायक के रूप में कार्य करता है। अन्य विशेषताओं में मौसम की जानकारी, टूर ऑपरेटर विवरण, मुद्रा परिवर्तक, हवाई अड्डे की जानकारी, वीज़ा-गाइड और बहुत कुछ शामिल है।

मेलों/महोत्सवों/पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता:

पर्यटन मंत्रालय मेलों/महोत्सवों/पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन योजना के तहत प्रति राज्य 80 लाख रुपये और प्रति संघ राज्यक्षेत्र 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2025-26 में अब तक मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए 12 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों को कुल 950 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

5.2 विपणन एवं संवर्धन (अंतर्राष्ट्रीय)

पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए पर्यटन सृजनकारी बाजारों में पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। एकीकृत विपणन एवं संवर्धनात्मक कार्यनीति तथा ट्रैवल ट्रेड, राज्य सरकारों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से एक संयुक्त अभियान के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

1. **जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी।**

   पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण पर्यटक सृजनकारी बाजारों के साथ-साथ उभरते और संभावित बाजारों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

एफआईटीयूआर (22-26 जनवरी 2025)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पेन और मुख्य रूप से स्पैनिश भाषी देश के स्रोत बाजार में भारत को एक संभावित अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मैड्रिड, स्पेन में आयोजित प्रमुख यात्रा मेलों में से एक - एफआईटीयूआर में भाग लिया। पर्यटन के क्षेत्र में एक बेंचमार्क इवेंट मानी जाने वाली एफआईटीयूआर में प्रदर्शनी 22 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई । एफआईटीयूआर पर्यटन पेशेवरों के लिए वैश्विक बैठक बिंदु है एवं इबेरो-अमेरिका में बाजारों के लिए प्रमुख मेला है।

कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य सरकारों सहित 23 से अधिक सह-प्रदर्शकों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एफआईटीयूआर में अतुल्य भारत बैनर के तहत अपने अद्वितीय पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को प्रदर्शित किया। पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारत के राजदूत ने अन्य मंत्रिस्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

स्पेन भी भारत में इनबाउंड यात्रा के लिए शीर्ष 20 पर्यटक-उत्पादक बाजारों में शामिल है, जिसमें 2023 में लगभग 70,000 स्पेनिश पर्यटक देश में आएंगे – जो वर्ष 2022 में दर्ज की गई संख्या से लगभग दोगुना है।

आईटीबी बर्लिन 2025 (4 से 6 मार्च 2025)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने मेसे बर्लिन में 4 से 6 मार्च तक आयोजित आईटीबी बर्लिन 2025 में भाग लिया। आईटीबी बर्लिन टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, होटल व्यवसायियों, परिवहन कंपनियों, गंतव्यों और तकनीकी कंपनियों सहित वैश्विक उद्योग के लिए एक प्रमुख बैठक बिंदु है।

भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए जर्मनी शीर्ष दस स्रोत बाजारों में से एक बना हुआ है, जिसमें वर्ष 2023 में 0.20 मिलियन जर्मन भारत आ रहे है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल सहित अन्य राज्यों की राज्य सरकारों ने वैश्विक बाजार के लिए अपने नए गंतव्यों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आईटीबी में 'अतुल्य भारत' पवेलियन में भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की जीवंत सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन उत्पादों की विशाल श्रृंखला और व्यापक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय यात्रा उद्योग के लगभग 40 हितधारकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के जर्मनी में राजदूत ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों की उपस्थिति में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।

वर्ल्ड एक्सपो 2025

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 21 से 28 सितंबर 2025 तक ओसाका, जापान में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लिया। मंत्रालय ने डिजिटल माध्यम के जरिए देश की सांस्कृतिक धरोहर, भोजन (कुज़ीन), प्राकृतिक दृश्य, योग और साहसिक पर्यटन अवसरों को प्रदर्शित किया। इस पर्यटन सप्ताह का आयोजन यूएनिब्लूटीओ विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के उत्सव के साथ भी मेल खाता था।

विश्व यात्रा बाजार (डब्ल्यूटीएम- 4 - 6 नवंबर 2025)

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 4 से 6 नवंबर 2025 तक आयोजित WTM में प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया। इस प्रतिनिधि मंडल में 30 हितधारक शामिल थे, जिन्होंने भारत की जीवंत सांस्कृतिक विविधता, विस्तृत पर्यटन उत्पादों और अनुभवात्मक पर्यटन अवसरों को प्रदर्शित किया

जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य पर्यटन विभागों सहित टूर ऑपरेटरों, गंतव्य प्रबंधन कंपनियों और आईआरसीटीसी ने इंडिया पवेलियन में भाग लिया। भाग लेने वाले अन्य राज्य पर्यटन विभागों में गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। ये राज्य अपने अनूठे पर्यटन अनुभवों को प्रदर्शित कर रहे हैं और दुनिया भर के संभावित ग्राहकों और सहभागीदारों से जुड़े हुए हैं।

भारतीय पवेलियन का उद्घाटन यूनाइटेड किंगडम में भारत के उप उच्चायुक्त द्वारा संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राजस्थान के उपमुख्यमंत्री एवं गोवा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया।

2. आतिथ्य योजना

i. पर्यटन मंत्रालय ने जापान के सात सदस्यीय समूह के लिए परिचय यात्रा की मेजबानी की, जिसमें टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और जापान एयरलाइंस के 2 मुख्य रैंक के अधिकारी शामिल थे। अतिथियों ने 22 से 28 मार्च, 2025 तक दिल्ली, आगरा, जयपुर और वाराणसी का दौरा किया। व्यापार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए जापान एयरलाइंस और टूर ऑपरेटरों के लिए जयपुर में पैलेस समान होटल के निरीक्षण/व्यावसायिक दौरे की भी व्यवस्था की गई।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने 28 अगस्त को हैम्बर्ग स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से कोच्चि आने वाले जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के एक मीडिया समूह के लिए एक आतिथ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस यात्रा का आयोजन जर्मनी की शीर्ष टूर ऑपरेटर कंपनियों में से एक - मैसर्स गेबेको द्वारा किया गया । इस समूह को कारीगरों, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से एक व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ।

iii. मंत्रालय ने 14 से 20 अगस्त 2025 तक दुशांबे में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में मेसर्स अशोक होटल के दो शेफ की सहभागिता के लिए भी सहयोग किया। खाद्य महोत्सव का आयोजन दुशांबे स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से किया गया था।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने 24 से 27 सितंबर 2025 तक कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में मेसर्स अशोक होटल के दो शेफ की भागीदारी के लिए व्यवस्था की। कजाकिस्तान के बाजार में भारतीय पाक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास, अस्ताना के सहयोग से खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया ।

v. पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 24 नवंबर, 2025 को ट्रांसपोर्ट भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में मीडिया सेंटर में टेरानोवा रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड के मुख्य कहानीकार श्री डोव कलमैन द्वारा "उच्च स्तरीय इजरायली बाजार की विकास संभावना - अब क्यों?" पर एक परिचय सत्र का आयोजन किया। सत्र में इजरायली बाजार की संरचना और गतिशीलता एवं उभरते अवसरों में गहन और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। इस सत्र में इजरायली बाजार की कार्यनीतिक संभावना के बारे में समझ और भारत के लिए बेहतर जुड़ाव एवं विकास के अवसरों की पहचान करने की पेशकश की गई।

3. पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों को शुरू करने हेतु मंत्रालय का विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ नियमित समन्वय है। भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित देशों में आयोजित की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा हेतु प्राथमिकता वाले बाजारों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई हैं। मंत्रालय भारतीय मिशनों के साथ डिजिटल पर्यटन प्रचार सामग्री भी साझा करता है, जिसमें अतुल्य भारत ब्रांड की फिल्में, उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां और अन्य प्रचार संपार्श्विक शामिल हैं, जिनका उपयोग मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में किया जा सकता है।

****

तमिलनाडु का यरकौड शहर

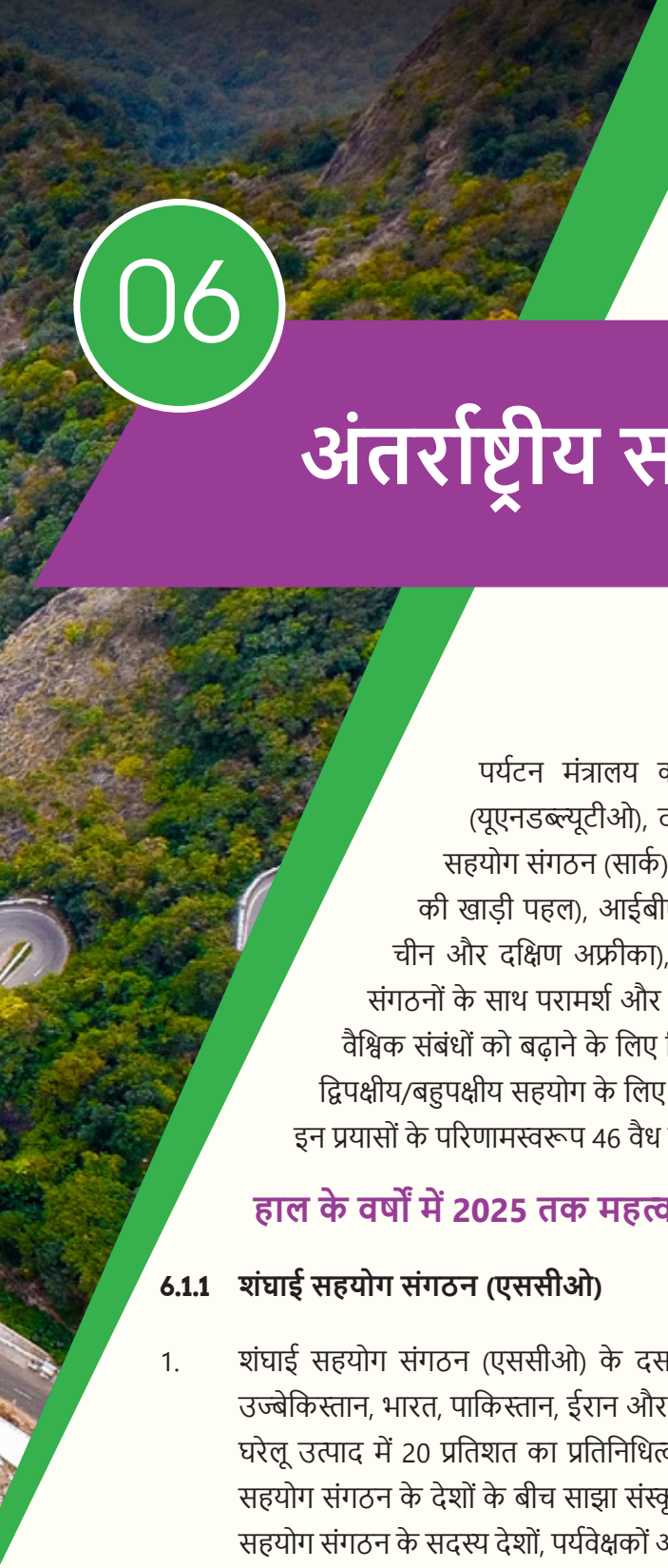

06

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

पर्यटन मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन), जी-20 जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श और वार्तालाप में सक्रिय रूप से शामिल है। ये वार्तालाप पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक संबंधों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन सहभागिताओं का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के लिए समझौते/समझौता ज्ञापन (एमओयू) स्थापित करना भी है। वर्तमान में, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 46 वैध समझौता ज्ञापन मौजूद हैं।

हाल के वर्षों में 2025 तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियाँ

6.1.1 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

1. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दस सदस्य देश (चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस) दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच साझा संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाकर बढ़ावा दिया जा सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और भागीदारों की कुल सांस्कृतिक विरासत में 207 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं।

2. भारत ने 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य महामारी के कारण क्षेत्र की रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करना था, साथ ही सदस्य देशों के बीच सतत और समायोजनीय विकास को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक नीतियों को परिभाषित करना था। भारत की अध्यक्षता के दौरान, कई पहल और उपक्रम शुरू किए गए।

3. वर्ष 2025 में, दिनांक 16 जून 2025 को आयोजित पर्यटन पर एससीओ विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की बैठक में संयुक्त महानिदेशक (पर्यटन) ने भाग लिया और बैठक के दौरान एससीओ के सदस्य देशों ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के पर्यटन विभागों के नेताओं की बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे पर चर्चा की।

4. संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने 7 जुलाई 2025 को पर्यटन विभागों के एससीओ लीडर्स की बैठक में भाग लिया, इसके बाद 6 जुलाई 2025 को चीन के किंग्डाओ में आयोजित एससीओ विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की बैठक हुई। बैठक के दौरान सदस्य देश ने (शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पर्यटन विभागों के लीडर्स के) मसौदा कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया और उस पर हस्ताक्षर किए। कार्यवृत्त के प्रमुख बिंदु: (i) संबंधों को मजबूत बनाना, (ii) चीन की पहलों का आकलन, (iii) फोरम संबंधी पहल, (iv) संवर्धन में सहायता, (v) सतत विकास, (vi) डिजिटलीकरण, (vii) एससीओ पर्यटन पूंजी आदि हैं।

6.1.2. आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ)

आसियान की स्थापना इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देने के मूल उद्देश्य से की गई थी। इसमें 10 सदस्य देश ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत वर्तमान में रणनीतिक हिस्सेदार की स्थिति में है।

आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बाजार है और इसलिए भारत के पर्यटन उत्पाद को इस बाजार में अतुल्य भारत अभियान और अन्य प्रचार और विपणन कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। भौगोलिक निकटता और अधिकांश आसियान सदस्य देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी के कारण भारत आसियान क्षेत्र से पर्यटन सृजन की अपार संभावनाएँ देखता है। पर्यटन मंत्रालय आसियान बाजार में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने जनवरी 2012 में इंडोनेशिया में तीसरी भारत-आसियान पर्यटन मंत्री-स्तरीय बैठक के दौरान आसियान-भारत पर्यटन सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर (वर्ष में दो बार) और पर्यटन मंत्री स्तर पर (वर्ष में एक बार) नियमित वार्तालाप किया जाता है।

- **वर्ष 2025 (आसियान-भारत पर्यटन मंत्री-स्तरीय 12वीं बैठक और 33वीं पर्यटन कार्यकारी समूह बैठक)**

1. माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोहोर, मलेशिया में दिनांक 20 जनवरी 2025 को 12वीं आसियान-भारत पर्यटन मंत्री-स्तरीय की बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया और पर्यटन संबंधी आदान-प्रदान में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 2024 में 662,000 आगंतुकों ने आसियान से भारत की और 4.27 मिलियन भारतीयों ने आसियान की यात्रा की। भारत ने कनेक्टिविटी, सतत पर्यटन, क्षमता निर्माण, क्रूज पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर फोकस करते हुए संयुक्त पर्यटन कार्य योजना (2023-2027) को आगे बढ़ाने के लिए आसियान-भारत कोष के तहत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। वर्ष 2026 में अगले बैठक की मेजबानी फिलीपींस करेगा।

2. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने जोहोर, मलेशिया में दिनांक 17 जनवरी 2025 को 33वीं आसियान-भारत पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक में पर्यटन संबंधी सहयोग बढ़ाने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं विकास के लिए नए अवसरों को तलाशने पर ध्यान दिया गया। मुख्य चर्चाओं में भारत के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में आसियान-भारत पर्यटन वर्ष 2025 की योजना बनाना शामिल था।

3. सतत पर्यटन पर आसियान-भारत संयुक्त नेताओं के स्टेटमेंट (2025) को 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में अपनाया गया, जो स्थिर, उत्तरदायी और समावेशी पर्यटन के क्षेत्र में आसियान-भारत सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह ग्रीन, ब्लू और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और क्षमता निर्माण, डिजिटल नवाचार तथा ज्ञान साझाकरण को बढ़ाता है।

4. वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया था, जिसे भारत द्वारा पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारत तथा आसियान के बीच लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस उत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

- जीआईटीबी 2025 (4-6 मई 2025) में गोलमेज सम्मेलन
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) 2025, सिक्किम

6.1.3 यूएनडब्ल्यूटीओ (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन)

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसके कुल 160 देश सदस्य हैं, यह पर्यटन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष बहुपक्षीय एजेंसी है। भारत 1975 से यूएनडब्ल्यूटीओ का सदस्य रहा है। भारत को अनेक बार कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है, जो यूएनडब्ल्यूटीओ का एक शासी बोर्ड है और इसमें 35 सदस्य हैं। भारत यूएनडब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण समितियों, जैसे कार्यक्रम और बजट समिति, सांख्यिकी समिति और संबद्ध सदस्यता से संबंधित मामलों की समिति का भी सदस्य है। पर्यटन मंत्रालय कार्यकारी परिषद और विभिन्न समितियों में दक्षिण एशिया आयोग (जिसमें 9 देश शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करता है।

1. इंडोनेशिया में भारत के राजदूत, मिशन के उप प्रमुख और काउंसेलर ने 15-16 अप्रैल, 2025 को पूर्वी एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन आयोग और दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन आयोग की 37वीं संयुक्त बैठक के साथ-साथ जकार्ता, इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन आयोग की 60वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान यूएनडब्ल्यूटीओ के समक्ष सीएसए और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के लिए फिर से चुनाव की बात रखी गई।

2. **संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यकारी परिषद की बैठक का 123वां सत्र-** कार्यकारी परिषद की बैठक का 123वां सत्र 29 से 30 मई, 2025 तक स्पेन के सेगोविया में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक ने स्पेन में कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया।

3. **संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा:** माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और श्री सुमन बिल्ला, अपर सचिव एवं महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय तथा रियाद में सिथत भारतीय मिशन के अधिकारियों के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने 7-11 नवंबर, 2025 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा के छब्बीसवें सत्र में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा के छब्बीसवें सत्र के साथ-साथ, कार्यकारी परिषद की 124वीं और 125वीं बैठक आयोजित की गई।

26वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा (7-11 नवंबर 2025) में भागीदारी की मुख्य विशेषताएँ

भारत ने 7-11 नवंबर 2025 तक आयोजित 26वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा में सक्रिय रूप से भाग लिया। महासचिव-निर्वाचित एच.ई. शेखा अल नोवैस को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला और सबसे युवा महासचिव के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने पर भारत की ओर से बधाई दी गई। कार्यक्रम और बजट समिति की बैठक में, सदस्य राष्ट्र के अंशदान को 4% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जबकि कार्यकारी परिषद ने बाद में महासभा में 2% की कैलिब्रेटेड वृद्धि की सिफारिश की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के कार्य संबंधी कार्यक्रम को 8-10 रणनीतिक प्राथमिकताओं के आसपास पुनर्संरचित करने की वकालत की, जिसमें प्रत्येक को परिभाषित संसाधनों, आधारभूत मेट्रिक्स और मापने योग्य परिणामों के अनुरूप बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विषयगत चर्चा के दौरान, भारत ने पर्यटन में एआई के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, पर्यटन में एआई के लिए नैतिकता के वैश्विक चार्टर के विकास का प्रस्ताव दिया, और एक बहु-हितधारक सलाहकार तंत्र के साथ-साथ डेटा संबंधी संप्रभुता और पारदर्शिता पर सुरक्षा उपायों के लिए आह्वान किया। महासभा के इतर,

माननीय मंत्री जी ने श्रीलंका और मालदीव के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और मेजबान अधिकारियों ने भारत की सकारात्मक भागीदारी की सराहना की।

6.1.4. जी-20

1. **जी-20-** महानिदेशक (पर्यटन) ने 5 मार्च, 2025 को दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में पहली जी-20 पर्यटन कार्यकारी समूह (टीडब्ल्यूजी) की बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एआई-संचालित नवाचार, स्थायी पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी पर बल दिया गया। पर्यटन स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को समर्थन देने पर जोर देते हुए, भारत डिजीयात्रा और डिजिलॉकर जैसे एआई उपकरणों का लाभ उठा रहा है, साथ ही वैश्विक पर्यटन डैशबोर्ड के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के साथ सहयोग कर रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से 50 विशिष्ट पर्यटन स्थलों को विकसित करने, नगर पालिका बॉन्ड सहित विभिन्न वित्तपोषण मॉडलों की खोज करने और जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने की देश की योजना पर प्रकाश डाला गया। हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के प्रयासों के अंतर्गत क्षेत्रीय केंद्रों का विस्तार और डिजिटल नोमैड-अनुकूल गंतव्यों के विकास के साथ-साथ लंबी दूरी की विमानन संबंधी भागीदारी को मजबूत करने का भी उल्लेख किया गया। भारत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्थायी पर्यटन को एकीकृत कर रहा है और पर्यटन मित्र कार्यक्रम के तहत पर्यटन हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। जी 20 सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, भारत वैश्विक पर्यटन पहलों को उन्नत बनाने और सितंबर 2025 में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन तक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में सहायता देने के लिए समर्पित है।

2. **द्वितीय जी 20 पर्यटन कार्यकारी समूह-** डॉ. थल्मा जॉन डेविड, काउंसल जनरल और श्री प्रेम सागर केसरपू, चांसरी प्रमुख, भारतीय महावाणिज्य दूतावास, डरबन, दक्षिण अफ्रीका ने 11 से 13 मई, 2025 तक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित दूसरी जी 20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लिया। द्वितीय जी-20 पर्यटन कार्यकारी समूह का उद्देश्य उन मसौदा वितरण दस्तावेजों पर चर्चा करना है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की सहायता से तैयार किया गया है। इन दस्तावेजों में 5 मार्च को आयोजित पहली बैठक के बाद

प्राप्त सुझावों, सर्वेक्षण के परिणामों और जी 20 पर्यटन कार्यकारी समूह के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए शोध एवं केस स्टडीज को ध्यान में रखा गया है।

दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्यकारी समूह की 4 प्राथमिकताएँ इस प्रकार थीं: यात्रा और पर्यटन स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जन-केंद्रित एआई और नवाचार; समानता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन वित्तपोषण और निवेश; निर्बाध यात्रा के लिए हवाई कनेक्टिविटी; और समावेशी एवं सतत पर्यटन विकास के लिए अधिक लचीलापन।

3. संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने 29 जुलाई 2025 को आयोजित विशेष जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में (वर्चुअली) भाग लिया। बैठक के दौरान, सदस्य देशों ने दूसरी प्राथमिकता: 'सतत विकास के लिए पर्यटन वित्तपोषण और निवेश', तीसरे पर्यटन कार्यकारी समूह और मंत्रिस्तरीय बैठक की तैयारियों तथा प्रस्तावित 'जी20 2025 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा' पर चर्चा की।

4. पर्यटन मंत्रालय ने 12 सितंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रिटोरिया में स्थित उच्चायुक्त ने किया और उनके साथ सहायक महानिदेशक (एमपी एंड आईसी) भी उपस्थित रहे। इस दौरान चर्चाएँ चार प्राथमिकताओं: जन-केंद्रित एआई और नवाचार, सतत पर्यटन के लिए वित्तपोषण, हवाई कनेक्टिविटी और लचीलापन के इर्द-गिर्द 'जी20 पर्यटन कार्य योजना' को अंतिम रूप देने पर केंद्रित रहीं। पर्यटन मंत्रियों की घोषणा में भारत की 2023 की अध्यक्षता के परिणामों को भी स्वीकार किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड शामिल है।

6.1.5 ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात नामक 10 देश शामिल हैं। वर्ष 2024/25 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया गया और वे इसमें शामिल हुए।

पिछले कुछ समय से, ब्रिक्स देश राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान के तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं। वर्तमान में ब्राजील 2025 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष है।

1. वर्ष 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जाएगी।

2. महानिदेशक (पर्यटन) ने, **17 मार्च 2025** को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित पहली ब्रिक्स पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सहयोग, सतत पर्यटन और उभरते यात्रा रुझानों पर प्रकाश डाला गया। भारत ने साझा किया कि सांस्कृतिक पर्यटन पर फोकस करते हुए पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1,440 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। फोमो, पोमो और जोमो से प्रेरित उपभोक्ता व्यवहार में होने वाले बदलाव व्यक्तिगत यात्रा विकल्पों को आकार दे रहे हैं, जबकि अब 55% यात्री सतत पर्यटन को प्राथमिकता देते हैं। भारत ने कौशल विकास, सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरण के अनुकूल होमस्टे और वेलनेस एवं साहसिक पर्यटन सहित विशिष्ट पर्यटन के विकास पर बल दिया। भारत ने ब्रिक्स के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन सहयोग और तकनीक-सक्षम कार्यनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

3. **ब्रिक्स पर्यटन कार्यकारी समूह-** प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में श्री संदीप कुमार कुजूर, मिशन के उप प्रमुख, श्री सूरज अनंत जाधव, प्रथम सचिव (वाणिज्य एवं प्रेस, सूचना) और श्री अवध कुमार, अताशे (राजनीति एवं संस्कृति) ने 9 मई से 12 मई 2025 तक ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन कार्यकारी समूह और मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लिया। ये बैठकें ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा थीं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय पर्यटन अधिकारियों को एक साथ लाना और पर्यटन कार्यकारी समूह के भीतर सहयोग को आगे बढ़ाना था। यह चर्चाएँ वर्ष 2025 में ब्रिक्स पर्यटन कार्यकारी समूह के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों और नियोजित परिणामों पर केंद्रित रहीं।

6.1.6 बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)

बिम्सटेक 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्य देश भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हैं। बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) की पहली पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक 23 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत ने फरवरी 2005 में कोलकाता में पर्यटन पर पहली बिम्सटेक गोलमेज सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया था।

1. पर्यटन पर बिम्सटेक कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 18 से 19 मार्च 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई। एचसीआई कोलंबो ने बैठक में भाग लिया।

2. सांस्कृतिक सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक 24 अप्रैल 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें एजेंडा बिंदु 4: बिम्सटेक बौद्ध सर्किटों का संवर्धन और इसके लिए किए जाने वाले चरणबद्ध कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में सहायक महानिदेशक (आईसी) ने भाग लिया।

6.1.7 वर्ष 2025 में संयुक्त कार्यकारी समूह/द्विपक्षीय और अन्य महत्वपूर्ण बैठकें

1. पर्यटन सहयोग को और मजबूत करने के लिए, माननीय पर्यटन मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन महासभा के दौरान 9 नवंबर 2025 को श्रीलंका और 10 नवंबर 2025 को मालदीव के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों से चल रहे सहयोग की समीक्षा करने और पर्यटन संवर्धन, क्षमता निर्माण और जन-जन के बीच आपसी आदान-प्रदान के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिला।

2. 20 जनवरी 2025 को, मलेशिया के जोहोर में आयोजित आसियान बैठकों के दौरान, माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मलेशिया के पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री वाईबी दातो श्री तियोंग किंग सिंग और कंबोडिया के पर्यटन मंत्री श्री हुओत हक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। चर्चा का मुख्य विषय पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना, संपर्क बढ़ाना और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना था। कंबोडिया पक्ष ने पर्यटन को आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बताते हुए कंबोडिया के सफल और हरित पर्यटन सीजन की सराहना की।

3. 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवहन भवन में इज़राइल के पर्यटन मंत्री महामहिम श्री हैम काट्ज़ के साथ बैठक की। इस बैठक में महानिदेशक (पर्यटन), सहायक महानिदेशक (आईसी), संयुक्त सचिव (विदेश मंत्रालय) और अवर सचिव (विदेश मंत्रालय) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और इज़राइल के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ाना था। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संपर्क सुधारने पर बल दिया गया।

4. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय पर्यटन मंत्री और श्री उमिद शादिएव, अध्यक्ष, पर्यटन समिति, उज्बेकिस्तान सरकार के बीच 19-21 फरवरी, 2025 को भारत के नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जो दिल्ली में आयोजित एसएटीटीई-2025 पर्यटन कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के हिस्से के रूप में हुई थी।

5. **जेएससी यूएई -** 19 मार्च, 2025 को संयुक्त सचिव (पर्यटन), संयुक्त महानिदेशक (पर्यटन) के साथ, भारत-यूएई सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त समिति की बैठक में शामिल हुए। चर्चा का मुख्य विषय भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत करना था, जिसमें यूएई के युवाओं को भारत की समृद्ध विरासत से परिचित कराने पर विशेष बल दिया गया।

6. **तमिलनाडु परियोजना -** भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में 18 मार्च, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "तमिलनाडु एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना (टीएनआईटीडीपी) के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव", पीपीआर आईडी - टी12461 पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की गई, ताकि न्यू डेवलपमेंट बैंक से निधि प्राप्त की जा सके।

7. **शिष्टाचार भेंट -** 20 मार्च 2025 को पर्यटन महानिदेशक ने भारत में बेलारूस के राजदूत महामहिम श्री मिखाइल कास्को के साथ द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सार्थक बैठक की। चर्चा का मुख्य विषय पारस्परिक अवसरों की पहचान करना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना था।

8. **शिष्टाचार भेंट -** पेरू की विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्री सुश्री उर्सुला देसिलू लियोन ने 20 मार्च 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार के पर्यटन मंत्री से मुलाकात की और उन्हें पेरू आने का निमंत्रण दिया।

9. पर्यटन सहयोग पर जापान और भारत के बीच चौथी संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह बैठक पर्यटन महानिदेशक और जापान पर्यटन एजेंसी के आयुक्त की सह-अध्यक्षता में हुई। बैठक के एजेंडा में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे:-

i. पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार।

ii. सूचनाओं का आदान-प्रदान और डेटा साझा करना।

iii. भारत में जापानी विश्वविद्यालयों से छात्रों के आगमन में वृद्धि। iv. पर्यटन और आतिथ्य संस्थानों के छात्रों/संकाय के बीच विनिमय कार्यक्रम।

iv. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों, मीडिया, विचारकों, सोशल मीडिया हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा यात्राओं को प्रोत्साहित करना।

v. भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाले जापानी पर्यटकों को प्रोत्साहित करना।

vi. पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्रों में निवेश के अवसर।

vii. भारत और जापान के बीच हवाई संपर्क में वृद्धि।

viii. पर्यटन नीतियों का अवलोकन और वर्तमान में अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन की स्थिति।

ix. भारत और जापान दोनों में निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटन आदान-प्रदान का विस्तार (दोनों देशों के बीच पर्यटक प्रवाह को बढ़ाना)।

x. अन्य विषयों में भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष का सार शामिल है।

10. 27 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट (एटीएम) 2025 के दौरान, माननीय पर्यटन मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री से मुलाकात की। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भारत-संयुक्त अरब अमीरात पर्यटन से संबंधित रणनीतिक संवाद को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में पारस्परिक हित और सहयोग के विभिन्न अवसरों का पता लगाना था।

11. भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग (जेसीईसी) का 22वां सत्र 5 जून 2025 को आयोजित हुआ। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने उक्त जेसीईसी की सह-अध्यक्षता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी बैठक में भाग लिया, जहां दोनों पक्षों ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

12. ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव के बीच 23 जून 2025 (सोमवार) को परिवहन भवन, नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित क्षेत्रों में ग्वाटेमाला, अल-साल्वाडोर और होंडुरास के साथ अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

13. 18 जून, 2025 को नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में दक्षिण कोरिया और पोलैंड से संबंधित हवाई सेवाओं के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई। पर्यटन मंत्रालय की ओर से संयुक्त महानिदेशक ने उक्त बैठक में भाग लिया।

14. 30 जुलाई 2025 को माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जापान परिवहन एवं पर्यटन अनुसंधान संस्थान (जेटीटीआरआई) के अध्यक्ष एवं इंटरनेशनल हाई स्पीड रेल एसोसिएशन (आईआरए) के अध्यक्ष श्री शुकुरी मसाफुमी के बीच एक शिष्टाचार भेंट हुई। इसका उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय और जेटीटीआरआई के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाना था, साथ ही सूचना आदान-प्रदान और सहयोगात्मक अनुसंधान सहित पर्यटन के क्षेत्र में भारत और जापान के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करना था।

15. आईआरआईजीसी-टीईसी: सहायक महानिदेशक (आईसी) ने 14 अगस्त, 2025 को आयोजित 26वें आईआरआईजीसी-टीईसी के मसौदा प्रोटोकॉल पर विशेषज्ञ परामर्श में भाग लिया। चर्चा के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने 2024 में 1.55 लाख पर्यटकों के आगमन के साथ रूस को भारत के लिए 12वें सबसे बड़े स्रोत बाजार के रूप में उजागर किया और समुद्र तटों, विरासत, संस्कृति और स्वास्थ्य पर्यटन जैसे रुचि के क्षेत्रों पर जोर दिया। पर्यटन मंत्रालय ने प्रोटोकॉल के लिए एक मसौदा पैरा भी प्रस्तावित किया, जिसमें पर्यटन संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान, संयुक्त प्रचार और होटल एवं पर्यटन अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने में सहयोग पर बल दिया गया, साथ ही यह भी बताया गया कि भारत के होटल उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

16. एसएएसईसी: आगामी एसएएसईसी कार्यकारी समूह की बैठकों और एसएएसईसी पर्यटन ज्ञान कार्यशाला (24-25 नवंबर 2025 को काठमांडू में आयोजित होने वाली है) के संबंध में, संयुक्त महानिदेशक (पर्यटन) ने आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव (एफबी) की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2025 को एक तैयारी संबंधी ब्रीफिंग बैठक में भाग लिया। समन्वय और सुझावों पर चर्चा करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि बैठक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। इसके बाद एसएएसईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2025 का आयोजन 8-9 दिसंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

17. फिलीपींस के माननीय पर्यटन मंत्री ने 6 अगस्त, 2025 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री से शिष्टाचार भेंट की।

18. गृह मंत्रालय के अपर सचिव (एफ एवं यूटी) की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2025 को भारतीय वीजा व्यवस्था के युक्तिकरण और सरलीकरण पर आयोजित बैठक में संयुक्त महानिदेशक (पर्यटन) ने भाग लिया।

19. भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश गोपी ने 2 सितंबर, 2025 को वियतनाम के हनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया।

20. पर्यटन मंत्रालय के सहायक महानिदेशक ने 1 सितंबर, 2025 को वाणिज्य भवन में आयोजित भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के साथ भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की वार्ताओं के संबंध में मंत्रालय के मसौदा सुझावों पर चर्चा की। पर्यटन मंत्रालय ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के आर्थिक सहयोग अध्याय में शामिल किए जाने वाले पर्यटन से संबंधित सहयोग क्षेत्रों/प्रमुख कार्यों आदि पर मसौदा सुझाव प्रस्तुत किए।

6.1.8 वर्तमान वैध समझौता ज्ञापन/समझौते/एलओआई

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पर्यटन सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसका उद्देश्य सहयोग के कई क्षेत्रों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय, मलेशिया सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2024 में मलेशियाई राष्ट्रपति की भारत की वीवीआईपी यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित हैं:

1. पर्यटन उत्पादों और सेवाओं का प्रचार और विपणन;

2. विनिमय कार्यक्रमों सहित पर्यटन अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में विस्तार;

3. पर्यटन अवसंरचना, सुविधाओं, उत्पादों और सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना;

4. चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में सूचना का आदान-प्रदान और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करना;

5. व्यावसायिक पर्यटन, जिसमें बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ (एमआईसीई) शामिल हैं;

6. पर्यटन हितधारकों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना;

7. समुदाय आधारित पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन और जिम्मेदार पर्यटन का प्रचार और विकास।

पर्यटन मंत्रालय ने अब तक 44 द्विपक्षीय और 2 बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी आज भी वैध हैं।

6.1.9 ई-वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाना

1. **आसियान -** पर्यटन सचिव ने 25 मार्च 2025 को प्रमुख यात्रा संघों आईएटीओ, एटीओओआई, एबीटीओ, आईसीपीबी, ईईएमए और आईबीसी के साथ ई-वीज़ा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने, वीज़ा शुल्क में छूट देने और आसियान देशों के साथ हवाई संपर्क स्थापित करने के विषय पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और डीजीसीए के प्रतिनिधि भी शामिल थे। हितधारकों ने आने वाले पर्यटकों द्वारा सामना की जाने वाली ई-वीज़ा संबंधी कई समस्याओं, हवाई संपर्क में सुधार और आसियान देशों से बौद्ध तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रकाश डाला। इन मुद्दों को गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है, जिसके लिए उनके साथ-साथ एनआईसी और बीओआई के साथ भी बैठक आयोजित की गई थी।

****

कन्याकुमारी, तमिलनाडु

07 अनुसंधान एवं विश्लेषिकी

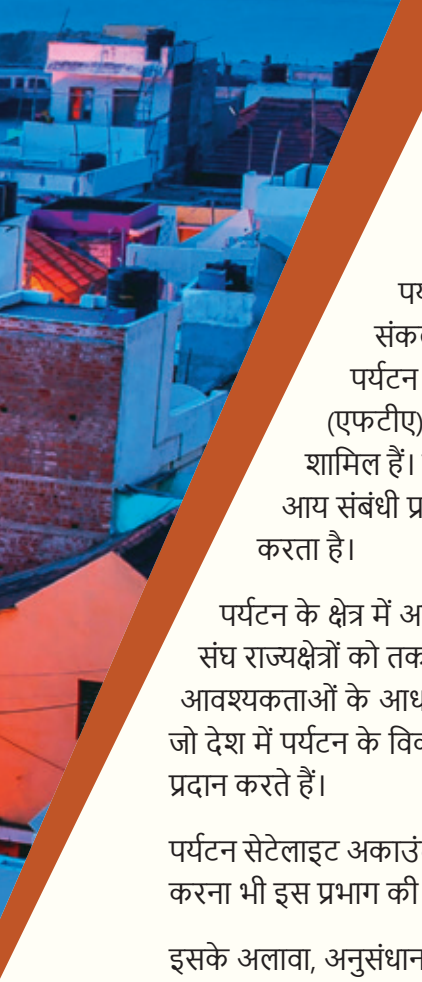

डेटा, सुदृढ़ साक्ष्य आधारित निर्णय लेने, किसी भी नीति और कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने के लिए अपरिहार्य उपकरण हैं। इसके परिणामस्वरूप, डेटा के विवरण और विश्वसनीयता का स्तर, साथ ही इसकी व्याख्या और उपयोग का स्तर, ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावशीलता पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यटन सांख्यिकी उनमें से एक है।

पर्यटन मंत्रालय का अनुसंधान एवं विश्लेषिकी (आर एंड ए) प्रभाग पर्यटन संबंधी आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है, जिसमें भारत में अंतर्गामी, बहिर्गामी और घरेलू पर्यटन शामिल है। प्रभाग द्वारा एकत्र किए गए प्रमुख सांख्यिकीय संकेतकों में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए), घरेलू पर्यटकों की यात्रा (डीटीवी), पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) पर संबंधित डेटा डेटा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों की प्रोफाइल का, उनके व्यय के पैटर्न, आय संबंधी प्रवृत्ति, उनकी पसंद और संतुष्टि के स्तर सहित आकलन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण भी करता है।

पर्यटन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं पर्यटन सांख्यिकी और बाजार संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना इस प्रभाग के अन्य प्रमुख कार्य हैं। मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर, यह प्रभाग पर्यटन सर्वेक्षण और आर्थिक एवं सांख्यिकीय अनुसंधान अध्ययन भी करता है, जो देश में पर्यटन के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने और तथ्य आधारित योजना बनाने के लिए इनपुट प्रदान करते हैं।

पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में पर्यटन के योगदान को मापता है, को तैयार करना भी इस प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, अनुसंधान एवं विश्लेषिकी प्रभाग डेटा साझा करने और अनुसंधान संबंधी सहयोग तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), प्रशांत एशिया यात्रा संघ (पीएटीए) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करता है।

7.1 सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के तहत बाजार अनुसंधान पेशेवर सेवा (एमआरपीएस)

बाजार अनुसंधान पेशेवर सेवा (एमआरपीएस) की गतिविधियों का मूल उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश में पर्यटन के विकास के लिए नीति निर्माण और योजना बनाने के लिए विश्वसनीय जानकारी जुटाना है। एमआरपीएस योजना का उद्देश्य नीतिगत निर्देशों के लिए समकालीन अनुसंधान इनपुट प्रदान करके

और नीतिगत पहलों के संकेंद्रित कार्यान्वयन के तरीके का समर्थन करके पर्यटन की व्यवस्थित योजना बनाने में व्यावसायिकता लाना है।

एमआरपीएस की गतिविधियों के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनसे संबंधित विषयों पर अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण/व्यवहार्यता अध्ययन करने/मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। यह पर्यटन क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करने और पर्यटन के विकास के लिए विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, उद्योग, बुद्धिजीवियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के लिए संस्थानों को भी सीएफए प्रदान करता है।

मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार एमआरपीएस की गतिविधियों के दायरे में अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण भी किए गए हैं जो पर्यटन के लिए नीतियों और योजनाओं के विकास के लिए आधार बने।

एमआरपीएस की गतिविधियों के तहत वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान किए जा रहे हैं:

नीति निर्माण तथा नियोजन के प्रयोजनार्थ मंत्रालय को संगत डेटा/सूचना/रिपोर्ट/इनपुट उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन, प्लान, बाजार अनुसंधान/व्यवहार्यता अध्ययन/प्रकाशन आदि।

क्र. सं.	वर्ष	विषय	संस्थान/एजेंसी
1	2025-26	"आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास" संबंधी अध्ययन	आईआईटीटीएम
2	2025-26	राजस्थान और गुजरात के विशेष संदर्भ में "देहाती समुदाय आधारित पर्यटन प्रणाली" संबंधी एक अध्ययन	आईआईटीटीएम
3	2025-26	पीपुल्स चॉइस के माध्यम से पर्यटन स्थल पुरस्कार	डीलॉइट

वर्ष 2025-26 के दौरान सर्वेक्षण/अध्ययन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन/पर्यटन संबंधी पत्रिकाओं के लिए संस्थानों/विश्वविद्यालयों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विषय
1	2016-17	केरल	निरंतर पर्यटन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए केरल सरकार को सीएफए
2	2022-23	महाराष्ट्र	"महाराष्ट्र राज्य के लिए पर्यटन संबंधी आंकड़ों के संग्रह पर सर्वेक्षण के लिए एजेंसी/परामर्शदाता की नियुक्ति (2022-23)" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
3	2022-23	लद्दाख	वर्ष 2022-23 के दौरान "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
4	2022-23	मिज़ोरम	वर्ष 2021-22 के दौरान "मिजोरम में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति के कार्यान्वयन" के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता मांगने का प्रस्ताव

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विषय
5	2022-23	तेलंगाना	वर्ष 2022-23 के दौरान "तेलंगाना राज्य में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रस्ताव
6	2022-23	त्रिपुरा	मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान "त्रिपुरा राज्य में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रस्ताव
7	2023-24	पंजाब	वर्ष 2023 के दौरान "पंजाब में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
8	2023-24	तमिलनाडु	वर्ष 2023 के दौरान "तमिलनाडु में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
9	2023-24	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2023 के दौरान "आंध्र प्रदेश में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
10	2023-24	झारखण्ड	"झारखंड में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
11	2023-24	दिल्ली	"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
12	2023-24	छत्तीसगढ़	"छत्तीसगढ़ में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
13	2023-24	पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
14	2023-24	मेघालय	"मेघालय में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
15	2024-25	जम्मू और कश्मीर	"जम्मू और कश्मीर में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
16	2024-25	गोवा	"गोवा में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
17	2024-25	उत्तराखंड	"उत्तराखंड में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
18	2024-25	असम	"असम में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विषय
19	2024-25	उत्तर प्रदेश	"उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 में आध्यात्मिक पर्यटक सर्वेक्षण" के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रस्ताव
20	2024-25	हरियाणा	हरियाणा में सूरजकुंड मेला 2025 के दौरान सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रस्ताव
21	2024-25	नागालैंड	"नागालैंड में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
22	2025-26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	"अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
23	2025-26	अरुणाचल प्रदेश	"अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति का कार्यान्वयन" नामक परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
24	2025-26	आईएचएम, पूसा	होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान (आईएचएमसी एंड एन) पूसा, नई दिल्ली को द्वि-वार्षिक पर्यटन अनुसंधान पत्रिका के लिए सीएफए

7.2 वर्ष 2025 के दौरान पर्यटन सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं

क. अंतर्गामी पर्यटन

- **विदेशी पर्यटक आगमन**

7.2 वर्ष 2024 के दौरान पर्यटन सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं

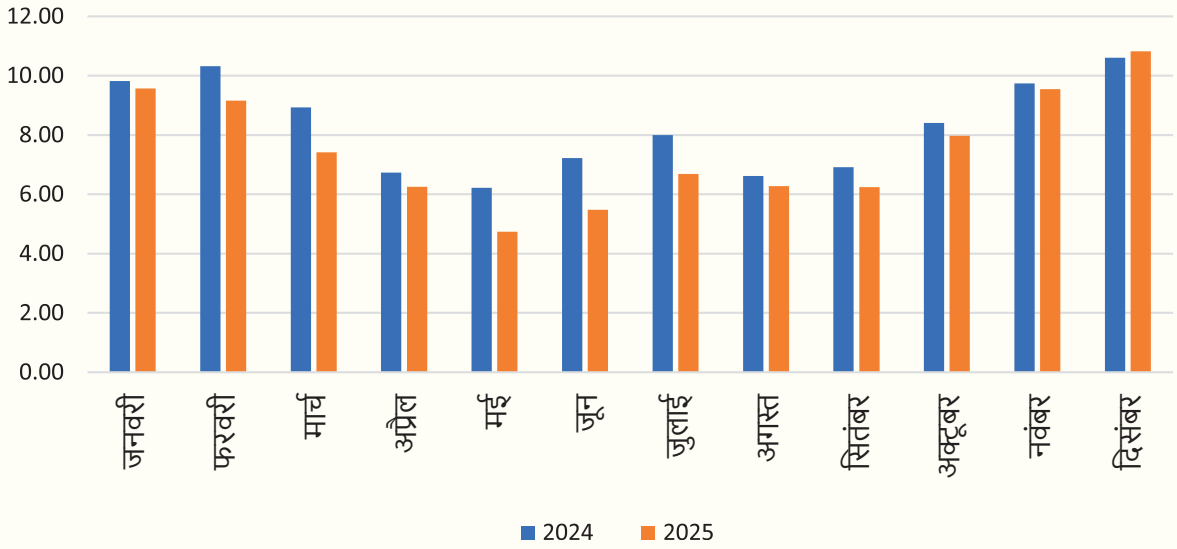

2025 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 9.02 मिलियन (अनंतिम) था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.4% की गिरावट दर्शाते हैं।

- **अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) का आगमन**

  वर्ष 2014 से, पर्यटन मंत्रालय ने वार्षिक आधार पर अनिवासी भारतीयों के आगमन के आंकड़े को संकलित करना शुरू किया और वर्ष 2024 के दौरान भारत में 10.62 मिलियन अनिवासी भारतीय आए।

- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए)**

  यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुरूप आईटीए में एफटीए और एनआरआई आगमन दोनों शामिल हैं। वर्ष 2024 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) 20.57 मिलियन था।

- **विदेशी मुद्रा आय (एफईई)**

  वर्ष 2025 की अवधि के दौरान फईई (अनंतिम अनुमान) ₹2,73,638 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.6% की कमी दर्शाता है।

  वर्ष 2025 की अवधि के दौरान फईई (अनंतिम अनुमान) 31.331 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.5% की कमी को दर्शाता है।

ख. बहिर्गामी पर्यटन

- **भारतीय नागरिक प्रस्थान (आईएनडी)**

2024 और 2025 के दौरान भारत से भारतीय नागरिकों का प्रस्थान (लाखों में)

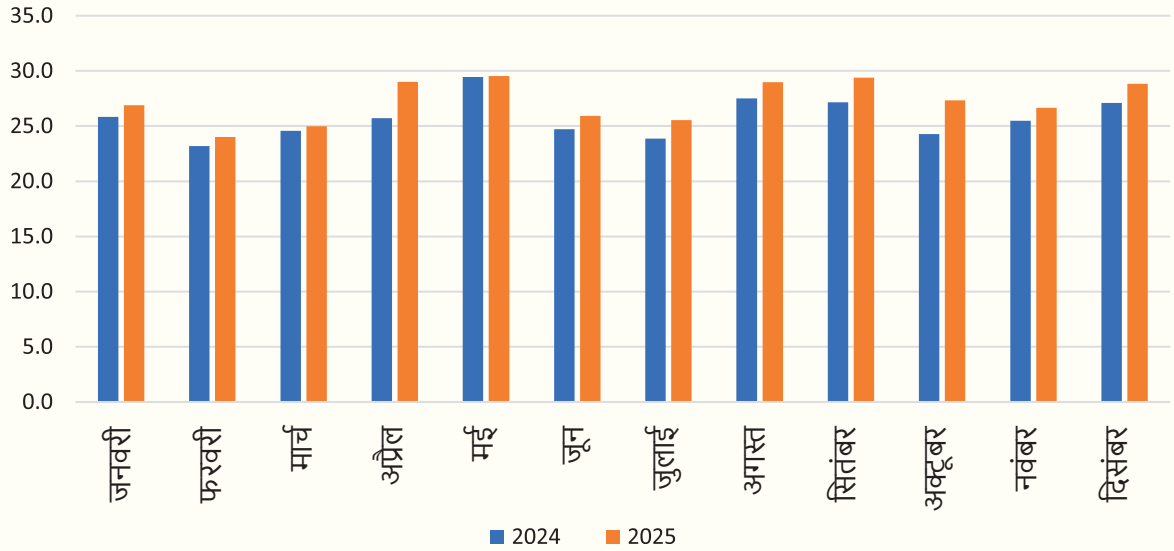

वर्ष 2025 के दौरान आईएनडी 32.71 मिलियन (अनंतिम) था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक है।

ग. घरेलू पर्यटन

घरेलू पर्यटन इस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान देश भर में घरेलू पर्यटक यात्रा (डीटीवी) की संख्या 4132.8 मिलियन थी और विदेशी पर्यटक यात्रा (एफटीवी) की संख्या 24.01 मिलियन (अनंतिम) थी।

7.3 पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट (टीएसए)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हर वर्ष तैयार किया जाने वाला राष्ट्रीय लेखा देश की जीडीपी की गणना करते समय विनिर्माण, कृषि, सेवा के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि के विकास एवं योगदान का मूल्यांकन करता है। तथापि, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जीडीपी में पर्यटन के योगदान का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, उद्योग को जिस रूप में परिभाषित करती है उसके अनुसार पर्यटन उद्योग की श्रेणी में नहीं है।

पर्यटन मांग पर आधारित संकल्पना है, जिसे इसके उपभोग द्वारा, न कि इसके आउटपुट द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि इसका उपभोग पर्यटक या गैर पर्यटक द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय लेखा में परिभाषित उद्योग, जैसे कि हवाई परिवहन, होटल और रेस्टोरेंट समान आउटपुट पैदा करते हैं। वह पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला उपभोग है जो पर्यटन संबंधी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है, जो राष्ट्रीय लेखा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जीडीपी में पर्यटन के योगदान का आंकलन करने के लिए पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट तैयार करने की आवश्यकता है।

अब तक पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा संस्तुत कार्य पद्धति का अनुसरण करके वर्ष 2006, 2012 और 2018 में संदर्भ वर्ष 2002-03, 2009-10 और 2015-16 के लिए भारत के तीन टीएसए तैयार कराए हैं। टीएसए - संस्तुत कार्य पद्धति रूपरेखा (टीएसए : आरएमएफ) 2008 के अनुसार, किसी देश के टीएसए में 10 मानक तालिकाओं का सेट शामिल होता है, जो अर्थव्यवस्था में पर्यटन के आर्थिक योगदान का अनुमान लगाने की कुंजी हैं। मानक संस्तुत फार्मेट में तालिकाएं तैयार करने तथा मानक विस्तृत कार्य पद्धति का अनुसरण करने से देशों के बीच समरूपता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं संभव होती हैं।

भारत के तीसरे पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट, 2015-16 की रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके तैयार की गई है अर्थात घरेलू पर्यटन सर्वेक्षण (2014-15), अंतर्राष्ट्रीय यात्री सर्वेक्षण (2015-16), वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015), उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (2011-12), राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (2017), आपूर्ति और उपयोग तालिका, सीएसओ (2012-13) और पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न सांख्यिकीय प्रकाशन। घरेलू पर्यटन सर्वेक्षण घरेलू पर्यटन पर एक अखिल भारतीय घरेलू सर्वेक्षण (डीटीएस 2014-15) है, जो जुलाई 2014 से जून 2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा अपने 72वें दौर के नमूना सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में किया गया था। वर्ष 2015-16 के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री सर्वेक्षण भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया था।

हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है:

पर्यटन जीडीपी:

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23(स:)	2023-24(अ:)
जीडीपी में पर्यटन की कुल हिस्सेदारी(%)	5.18	1.50	1.75	5.09	5.22
प्रत्यक्ष (% में)	2.69	0.78	0.91	2.65	2.72
अप्रत्यक्ष (% में)	2.49	0.72	0.84	2.44	2.50

स: संशोधित अनुमान, अ: अनंतिम अनुमान

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 पर आधारित अनुमान

पर्यटन रोजगार:

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पर्यटन प्रत्यक्ष रोजगार (मिलियन में)	30.28	29.68	30.55	33.22	36.90
पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी (%)	5.89	5.63	5.52	5.48	5.82
कुल (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पर्यटन रोजगार (मिलियन में)	69.44	68.07	70.04	76.17	84.63
नौकरियों में कुल हिस्सेदारी (% में)	13.50	12.91	12.66	12.57	13.34

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर आधारित अनुमान

7.4 पर्यटन संबंधी आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्षमता निर्माण

पर्यटन मंत्रालय का अनुसंधान एवं विश्लेषिकी प्रभाग राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर घरेलू पर्यटक यात्रा (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्रा (एफटीवी) के डेटा संकलित करता है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े समान पैटर्न में नहीं हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए गैर-समान डेटा के मुद्दों को दूर करने और घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्रा के पर्यटन संबंधी आंकड़ों के व्यापक संग्रह के लिए, आर एंड ए प्रभाग ने एक मानक पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति विकसित की है, जो संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी के अनुरूप है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न जिलों और पर्यटन संबंधी आकर्षणों में पर्यटन संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों के संग्रह का मानकीकरण करने में मदद करेगी। पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति के कार्यान्वयन से पर्यटन संबंधी महत्वपूर्ण आँकड़े सामने आएंगे, जैसे कि विभिन्न आकर्षणों पर घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या, आगंतुकों की प्रोफाइलिंग, यात्रा का उद्देश्य, रहने की अवधि, खर्च, निवास स्थान के अनुसार आगंतुक, होटल अधिभोग आदि। यह डेटा बुनियादी ढांचे के उन्नयन, पर्यटन उत्पाद विकास आदि की योजना बनाने में पर्यटन मंत्रालय और राज्यों के पर्यटन विभाग के लिए काफी उपयोगी होगा। अब तक 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने मानक पर्यटन सर्वेक्षण पद्धति को लागू करने के लिए एजेंसियों को नियुक्त किया है, जिनमें से 12 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मंत्रालय ने इस पद्धति के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को मंजूरी दी है, जबकि 3 अन्य राज्यों में सीएफए के लिए मंजूरी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, 6 राज्यों ने चरण-I पूरा कर लिया है और कई अन्य राज्यों द्वारा जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने की योजना है।

****

रामेश्वरम, तमिलनाडु

08 सुविधा एवं मानक

8.1 होटल और यात्रा व्यापार

8.1.1 होटलों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

यह मंत्रालय पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों का विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से अनुपालन करने हेतु स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, होटलों को वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या बगैर फोर स्टार और फाइव स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल रेटिंग प्रदान की जाती है। यह वर्गीकरण इस मंत्रालय द्वारा गठित होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) द्वारा किए जाने वाले होटलों के निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। प्रचालनरत होटल के वन स्टार से थ्री स्टार की श्रेणियों में वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में स्थित 5 क्षेत्रीय समितियों को निरीक्षण करने/निरीक्षण में समन्वय करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण के दिशानिर्देशों को 19 जनवरी 2018 को संशोधित किया गया है।

8.1.1.1 राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डेटाबेस

1. पर्यटन मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को सुगम बनाने और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यापार में सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डेटाबेस (या निधि) नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली की स्थापना की है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के विज़न के अनुरूप है। यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है ताकि उद्योग को शोकेसिंग, स्टार वर्गीकरण आदि जैसी संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सके। निधि पोर्टल विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, कुशल मानव संसाधन की आवश्यकताओं का आकलन करने और विभिन्न स्थलों पर पर्यटन के प्रचार/विकास के लिए नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करने में मदद करेगा।

2. इस पहल को निधि+ के रूप में अपग्रेड किया गया है, ताकि इसमें न केवल आवास इकाइयों का वर्गीकरण/अनुमोदन बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाइयों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स और कन्वेंशन सेंटरों के अनुमोदन/वर्गीकरण/पंजीकरण को भी शामिल किया जा सके। नई प्रणाली में हमारे उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की एक बड़ी भूमिका की भी परिकल्पना की गई है। इस पोर्टल पर https://nidhi.tourism.gov.in से पहुँचा जा सकता है।

3. निधि+ को राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के विजन के अनुरूप एक तकनीक-संचालित प्लेटफॉर्म पर निर्मित किया गया है और यह मापनीय और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील उन्नयन की अनुमति देगा।

4. राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (एनडीटीएम) का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर पर्यटन के ईको-सिस्टम में हितधारकों को डिजिटल रूप से जोड़ना है। डिजिटलीकरण पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को एकीकृत प्रणाली के तहत लाने और इस प्रकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। निधि+ को एनडीटीएम के छोटे लेकिन जरूरी हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है।

8.1.2 आवास इकाइयों की अन्य अनुमोदित श्रेणियां

टाइम शेयर रिजॉर्ट, प्रचालित मोटल, अतिथि गृह, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे प्रतिष्ठान, तंबूनुमा आवास तथा ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिट, कनवेंशन सेंटर, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट जैसी श्रेणियों में अनुमोदन के लिए मंत्रालय की स्वैच्छिक योजनाएं भी हैं।

8.1.2.1 हेरिटेज होटल

हेरिटेज होटल की लोकप्रिय संकल्पना 1950 से पहले निर्मित उन पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गों तथा आवासों को आवास इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए की गई थी, जो बीते युग के परिवेश और जीवनशैली को पुन: प्रस्तुत करते हैं। ऐसे होटलों को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधा एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड में वर्गीकृत किया जाता है। 16 दिसंबर 2014 से हेरिटेज होटल की एक नई श्रेणी अर्थात हेरिटेज क्लासिक (अल्कोहल सेवा के बगैर) शुरू की गई है।

8.1.2.2 लिगेसी विंटेज होटल

लिगेसी विंटेज होटल की संकल्पना विरासत संपत्तियों/भवनों (अर्थात ऐसी संपत्ति या भवन जो वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित/स्थापित किए गए हैं) की सामग्रियों से निर्मित होटलों को शामिल करने के लिए की गई है, बशर्ते होटल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री विरासत संपत्ति या भवन से प्राप्त की गई हो। ऐसे होटल बीते युग के परिवेश एवं वातावरण को पुन: सृजित करने में मदद करेंगे। ऐसे होटलों को 3 उप-श्रेणियों अर्थात लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) में वर्गीकृत किया जाएगा। लिगेसी विंटेज होटलों के वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

8.1.2.3 स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का पंजीकरण

रेस्टोरेंट पर्यटकों द्वारा किसी स्थान की यात्रा के अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं यात्रा को सुखद बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों में रेस्टोरेंट लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे अथेंटिक फूड, विशेष रूप से देश के विभिन्न राज्यों के पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निधि+ पोर्टल पर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट स्वंय अपना पंजीकरण कर पाएगें।

8.1.2.4 अपार्टमेंट होटलों का अनुमोदन

अपार्टमेंट होटल व्यावसायी यात्रियों में उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं, जो असाइनमेंट या फैमिली हॉलीडे आदि के लिए भारत के दौरे पर आते हैं जो कई बार कई महीनों के लिए होता है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने फाइव स्टार डीलक्स, फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार की श्रेणियों में पूर्णत: क्रियाशील अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

8.1.2.5 मोटलों का अनुमोदन

मोटल अतिथि सत्कार क्षेत्र का एक महत्पूर्ण अंग है जो सस्ता आवास प्रदान करता है। मोटल अपनी सुविधाओं एवं सेवाओं के माध्यम से रोड ट्रैवलर की आतिथ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं जिसमें अक्सर निचले ब्लाक में कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं और जिनके बिल्कुल बाहर पार्किंग की सुविधा होती है। समग्र पर्यटन उत्पाद के घटक के रूप में इस हिस्से को पहचान प्रदान करने तथा मोटलों की सुविधाओं एवं सेवाओं का मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने प्रचालनरत मोटलों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है। प्रचालनरत मोटलों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश 25 सितंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

8.1.2.6 अतिथि गृहों का अनुमोदन

घरेलू एवं विदेशी दोनों बजट पर्यटकों के लिए होटल आवास की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि गृहों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उनमें संशोधन किया है ताकि स्वच्छता, साफ-सफाई और उन्नत सुविधाओं एवं प्रथाओं के कतिपय मानकों का पालन किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य बदलती आवश्यकताओं तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के सरोकारों पर ध्यान देना था। स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ-सफाई तथा पेस्ट कंट्रोल के उपायों पर बल दिया गया है। यदि अतिथि गृह तथा अन्य प्रकार की आवास इकाइयां सुविधाओं और सेवाओं के कतिपय मानकों को पूरा करती हैं, तो उनको इस योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है। इन कदमों से बजट श्रेणी में न केवल होटल आवास की संख्या में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है, अपितु राज्यों के लिए रोजगार एवं राजस्व भी उत्पन्न हो सकता है।

8.1.2.7 टाइम शेयर रिजॉर्ट का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

टाइम शेयर रिजॉर्ट (टीएसआर) लीजर हॉलीडे और फैमिली हॉलीडे आदि के लिए उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने थ्री स्टार, फोर स्टार और फाइव स्टार की श्रेणियों में पूर्णत: प्रचालनरत टाइम शेयर रिजॉर्ट के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

8.1.2.8 अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे योजना

यह योजना विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ ठहरने और सौहार्दपूर्ण आतिथ्य का लुत्फ उठाने एवं स्वच्छ तथा किफायती स्थान में भारतीय संस्कृति एवं व्यंजन का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करती है। पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में होमस्टे/अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के संवर्धन पर जागरुकता संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अतुल्य भारत की बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों तथा अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठानों के वर्गीकरण तथा पुन: वर्गीकरण के संशोधित दिशानिर्देश 10 दिसंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सामान्य राष्ट्रीय मानक होंगे जिसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र मुख्य नियमों को अक्षुण्य रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनाएंगे। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इसमें संशोधन करने तथा सामान्य राष्ट्रीय मानकों के अलावा उपयुक्त मानदंड/मापदंड लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पर्यटन मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में बीएंडबी/होमस्टे प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सामान्य राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ऐसे वर्गीकरण के लिए अपना स्वयं का तंत्र स्थापित नहीं कर लेंगे। आवेदनों के निपटान के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को सक्रिय किया गया है। अनुमोदित इकाइयों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। आवदेन **https://nidhi.tourism.gov.in** पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

8.1.2.9 स्टैंड-अलोन एयर केटरिंग इकाइयों का पंजीकरण

एयर केटरिंग सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए देश में स्टैंड-अलोन एयर केटरिंग इकाइयां भी निधि+ पोर्टल पर पंजीकरण कर सकती हैं।

8.1.2.10 सम्मेलन केंद्रों का पंजीकरण

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण घटक हैं। तेजी से वैश्विकृत होती उच्च वृद्धि वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में एमआईसीई पर्यटन का विकसित होना तय है तथा इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश को अधिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्रों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए सम्मेलन केंद्र निधि+ पोर्टल पर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

8.1.2.11 ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए)

ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए) के अनुमोदन/पुन: अनुमोदन की योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा 10 दिसंबर, 2018 को इन्हें अधिसूचित किया गया है। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और पर्यटन मंत्रालय से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए कोई आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर बाध्य नहीं है।

8.1.2.12 अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 अक्टूबर, 2017 को देश में होटल रूम की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची अधिसूचित की है जिसमें 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 स्टार या उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 26 अप्रैल 2021 की अधिसूचना

के माध्यम से "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई मद को सम्मिलित करके "प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र" को परिभाषित करते हुए एक फुटनोट के साथ अवसंरचना उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र" को शामिल किया गया है।

8.1.3 पर्यटन क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहन

पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समय-समय पर जीएसटी के कराधान स्लैब का मुद्दा उठाया है जिसके फलस्वरूप पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जीएसटी के रेट स्लैब में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने होटल रूम टैरिफ पर कर दर में कटौती की घोषणा की जिसका उद्देश्य आतिथ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रति रात्रि 7500 रुपए तक की टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (आईटीसी के बगैर) कर दी गई है। इसी तरह, 7500 रुपए से अधिक रूम टैरिफ पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। प्रति रात्रि 1000 रुपए से कम रूम टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।

लागू दर के निर्धारण के आधार को घोषित टैरिफ से बदलकर वास्तविक टैरिफ कर दिया गया है।

वातानुकूलित होने या न होने पर ध्यान दिए बगैर रेस्टोरेंट की खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। यदि रेस्टोंरेट होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या आवासीय अथवा लॉजिंग के प्रयोजनार्थ किसी व्यवसायिक स्थल के परिसर के अंदर स्थित है, जहां दैनिक टैरिफ 7500 रुपए प्रतिदिन प्रति यूनिट या उससे अधिक है, तो कर 18 प्रतिशत होगा।

टूर ऑपरेटर सेवाओं के लिए, बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% जीएसटी (लेकिन ऐसे ही व्यवसाय में इनपुट सेवाओं के आईटीसी की अनुमति है) इस शर्त के अधीन लगाया जाता है कि इस सेवा की आपूर्ति के लिए जारी बिल दर्शाता हो कि इसमें इस तरह के टूर के लिए आवश्यक आवास और परिवहन शुल्क शामिल हैं एवं बिल में ली गई राशि शुल्क सहित इस टूर की ली गई सकल राशि है जिसमें इस टूर के लिए आवश्यक आवास और परिवहन, या आईटीसी सहित 18% जीएसटी है। क्रूज पर्यटन पर 18% जीएसटी की मानक दर लागू होती है।

8.1.4 निर्भया निधि

सरकार ने निर्भया निधि नामक एक गैर व्यपगत कॉर्पस फंड की स्थापना की है जिसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उपयोग महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूएंडसीडी) इसका नोडल मंत्रालय है, जिसके पास प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन/सिफारिश करने, संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने की जिम्मेदारी है।

'मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा करने के परिणामस्वरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूएंडसीडी) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और इसके बाद सचिव (पर्यटन), भारत सरकार की स्वीकृति से तीन वर्षों की अवधि में 16.79 करोड़ रुपये (लगभग) जारी करने/खर्च करने पर सहमति व्यक्त की गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 27.99 करोड़ रुपये (लगभग) है, जिसमें धनराशि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में यानी क्रमशः 16.79 करोड़ रुपये और 11.20 करोड़ रुपये के रूप में वितरित किया जाएगा।

'निर्भया निधि' के तहत केंद्र सरकार के 16.79 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल वित्तीय हिस्से में से 6.24 करोड़ रुपये (लगभग) की पहली किस्त 19 मार्च, 2021 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पक्ष में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड से पहली और दूसरी किस्त (केंद्र और राज्य के हिस्से) की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः पर्यटन मंत्रालय द्वारा 5.27 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की दूसरी तथा 5.27 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। इस प्रकार केंद्र के 16.79 करोड़ रुपये के कुल हिस्से में से कुल 16.78 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

8.1.5 वेब आधारित सार्वजनिक डिलिवरी प्रणाली

जनवरी, 2023 से निधि+पोर्टल के माध्यम से यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता भी प्रदान की जाती है। इस प्रणाली का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक यात्रा व्यापार सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुमोदन प्रदान करने में पारदर्शिता लाना है। नई प्रक्रिया सेवा प्रदाताओं से आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकार करती है जिसकी वजह से यह प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है।

सभी आवेदन https://nidhi.tourism.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं और पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनकी जांच करने, संसाधित करने और अनुमोदित/अस्वीकृत करने का काम पूरा किया जाता है। यह पहल अनुमोदन आदि के लिए ई-शासन की ओर अग्रसर होने के मंत्रालय के उद्देश्य का भाग है।

आत्मनिर्भर के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ग्रीनशूट/स्टार्टअप एजेंसियों की श्रेणी की पेशकश की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने 20 नवंबर, 2024 तक कुल 1644 स्टेकहोल्डर्स को मान्यता दी है। इनमें से 318 ट्रैवल एजेंट, 118 पर्यटक परिवहन ऑपरेटर और 1208 टूर ऑपरेटर हैं।

8.1.6 ई-वीजा

भारत में विदेशी पर्यटकों, पेशेवरों और कुशल कार्यबल, व्यवसायियों, छात्रों आदि सहित विदेशियों के वैध आवागमन को सक्षम करने के लिए एक सुदृढ़ वीजा व्यवस्था है। सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-ही आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय अवसंरचना में वृद्धि करने की दृष्टि से वीजा व्यवस्था को उदार, कारगर और सरल बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक पहलें की हैं।

भारतीय वीजा व्यवस्था, विशेष रूप से पर्यटक वीजा व्यवस्था को उदार और सरल बनाने हेतु उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम ई-वीजा सुविधा की शुरूआत है। इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) के साथ यह सुविधा, जिसे नवंबर, 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू किया गया था, वर्तमान में 33 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 08 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों और 2 थल मार्ग पत्तनों के माध्यम से 172 देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश हेतु उपलब्ध है।

वर्तमान में ई-वीजा 14 उप-श्रेणियों यानी ई-पर्यटक वीजा (30 दिन/01 वर्ष/05 वर्ष के लिए), ई-व्यवसाय वीजा, ई-चिकित्सा वीजा, ई-चिकित्सा सहायक वीजा, ई-सम्मेलन वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष सहायक वीजा ई-छात्र वीज़ा, ई-छात्र आश्रित वीज़ा, ई-ट्रांजिट वीज़ा, ई-पर्वतारोहण वीज़ा, ई-फिल्म वीज़ा, ई-प्रवेश वीज़ा और ई-उत्पादन निवेश वीज़ा के तहत उपलब्ध है।

ई-वीजा प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। एक विदेशी कहीं से भी ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकता है। ई-वीजा की शुरूआत ने पर्यटन, व्यवसाय और चिकित्सा आदि जैसे वैध उद्देश्यों के लिए भारत में विदेशियों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करने में मदद की है।

दोहरे प्रवेश सहित 30 दिनों के लिए ई-पर्यटक वीजा को वर्ष 2019 में 25 अमेरिकी डॉलर के शुल्क के साथ शुरू किया गया था। ऑफ सीजन में (अप्रैल-जून) पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस मंदे अवधि के दौरान वीजा शुल्क को 25 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 10 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।

8.1.7 घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए बाजार विकास सहायता

2020 में कोविड-19 का वैश्विक प्रकोप सभी समाजों और आजीविकाओं पर जबरदस्त प्रभाव के साथ एक अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल रहा है। यात्रा और पर्यटन इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में एक है जिसके कारण सभी यात्रा - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय - को पूर्ण रूप से कम कर दिया गया। जब स्थिति सुधर जाएगी, तो ऐसी संभावना है कि घरेलू यात्रा और पर्यटन देश में पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार में आगे रहेगा। इसलिए इस समय मंत्रालय का ध्यान घरेलू पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित और बहाल करने पर है।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की योजना के दिशानिर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- हितधारकों को घरेलू बाजार के लिए अपने विपणन कार्यक्रमों के भाग के रूप में अल्प ज्ञात और अनछुए गंतव्यों सहित देश के पर्यटन स्थलों का प्रचार करने के लिए प्रेरित करना।
- हितधारकों को पूरे देश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों से परिचित कराना ताकि वे उनको घरेलू उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी ढंग से प्रचारित कर सकें और उन्हें उनके पैकेज में शामिल करवा सकें।

- हितधारकों को देश में पर्यटन के क्षेत्र में नए गंतव्यों, उत्पादों और विकास से परिचित कराना।
- हितधारकों को पर्यटन उद्योग को देश की महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कार्यकलाप बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

एमडीए के दिनांक 28 नवंबर, 2020 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के भीतर प्रचार के निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; राष्ट्रीय पर्यटन, व्यापार और आतिथ्य संघों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित पर्यटन से संबंधित सम्मेलनों/संगोष्ठियां/सेमिनारों में भाग लेना; देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो में भाग लेना।

इसके अलावा, देश के अंदर संवर्धनात्मक कार्यकलापों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लीफलेट के निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों और टूर पैकेज का प्रचार करना तथा पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

8.1.8 बहुभाषी पर्यटक इन्फोलाइन

पर्यटन मंत्रालय ने 8 फरवरी 2016 को हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की है। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश में पर्यटक हेल्पलाइन द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवा टोल फ्री नंबर 1800-11-1363 पर या शॉर्ट कोड 1363 पर उपलब्ध है तथा वर्ष में 24x7 (सभी दिन) चालू है तथा निर्धारित भाषाओं में "बहुभाषी हेल्पडेस्क" की सेवाएं प्रदान करती है।

इस बहुभाषी हेल्पलाइन का उद्देश्य निर्धारित भाषाओं में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में यात्रा एवं पर्यटन से संबंधित सूचना प्रदान करने की दृष्टि से सहायता सेवा प्रदान करना और कॉल करने वाले व्यक्ति को भारत में यात्रा के दौरान संकट के समय में उठाए जाने वाले कदम के बारे में सलाह देना और आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकारियों को चौकस करना है।

यह पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का एक विशेष प्रयास है और विदेशी पर्यटकों में भारत में यात्रा करते समय सुरक्षा की भावना पैदा करता है।

-8.1.9 क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आरसीएस- उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना/बढ़ावा देना है।

एयरलाइन संचालकों को (1) क्षेत्रीय मार्गों/अन्य सहायता उपायों पर एयरलाइन संचालन की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों (संदर्भ में संघ राज्यक्षेत्रों को भी शामिल माना जाएगा, जब तक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो) और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा रियायत देकर (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन संचालन और अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर, यदि कोई हो, को कम करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्य अंतराल वित्त पोषण या वीजीएफ) सहायता द्वारा समर्थन देते हुए आरसीएस के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क की वहनीयता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

आरसीएस उड़ान पर्यटन के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय किया है तथा प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 53 पर्यटन मार्गों को चालू किया है।

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लगभग 226.11 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है, जिसमें से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 43.70 करोड़ रुपये जारी किए गए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 60.50 करोड़ रुपये जारी किए गए और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 121.91 करोड़ रुपये जारी किए गए।

8.1.10 पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर

पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर 5 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी3 टर्मिनल के आगमन द्वार पर खोला गया था। इसके बाद, पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी, बोधगया, बेंगलूरू, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर भी पर्यटक सुविधा काउंटर शुरू किए हैं यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के 9 अलग-अलग हवाई अड्डों पर कुल 9 पर्यटक सुविधा काउंटर खोले गए हैं।

आगंतुकों के लिए सुविधा केंद्र खोलना देश में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत मददगार होगा। काउंटर गैर-अंग्रेजी भाषी पर्यटकों की आवश्यताएं भी पूरी करेंगे क्योंकि ये काउंटर मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन - '1363' से भी कनेक्ट होते हैं जहां पर्यटक विदेशी भाषा एजेंट से सीधे बात कर सकते हैं और फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, जापानी, कोरियन, चीनी और अरबी में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

8.1.11 पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत/पर्यटक पुलिस योजना

i. पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, समर्पित पर्यटक पुलिस की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष मामला उठाया गया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा पर्यटक पुलिस की तैनाती की गई है।

ii. भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की जरूरतों के प्रति पर्यटक पुलिस को जागरुक बनाने के लिए "राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस की कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन" नाम से एक अध्ययन कराया जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईआईटीटीएम द्वारा दिया गया प्रशिक्षण मॉड्यूल गृह मंत्रालय को भी अग्रेषित किया गया जिसे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भी परिचालित किया गया।

iii. पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ विदेशी और घरेलू पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला। गृह मंत्रालय की इच्छा के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने 25 पर्यटक स्थलों की सूची अग्रेषित की, जिन्हें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक अलग पुलिस इकाई के गठन के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में लिया जा सकता है।

iv. एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन शुरू किया और बहुत व्यापक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के विश्लेषण और सिफारिशों को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। पर्यटकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समान पर्यटक पुलिस के कार्यान्वयन के उद्देश्य से गृह मंत्रालय और बीपीआरएंडडी के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस योजना पर 19 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभाग के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

v. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना की दृष्टि से सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा के दौरान संकट की स्थित में पर्यटकों को उपयुक्त मार्गदर्शन की पेशकश करने के लिए घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, रूसी, चाइनीज, जापानी, कोरियन, अरबी) सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 पर या संक्षिप्त कोड 1363 पर 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्प लाइन शुरू की है।

vi. पर्यटन मंत्रालय ने सभी हितधारकों के साथ मिलकर—जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग शामिल हैं—'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है। यह आचार संहिता दिशानिर्देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े सभी पक्षों जैसे आवास इकाइयों, परिवहन संचालकों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को प्रोत्साहित करना है। यह पहल विभिन्न संस्थाओं के योगदान को स्वीकार कर और उन्हें बढ़ावा देकर पर्यटन उद्योग के विकास को सशक्त बनाती है। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त साझेदारों को अंतरराष्ट्रीय रोड शो और यात्रा प्रदर्शनियों में मूल्यवान प्रचार और एक मंच प्राप्त होता है। यह अवसर उन्हें पर्यटन पैकेजों और उत्पादों को प्रदर्शित व विपणन करने में सक्षम बनाता है, जिससे देश के पर्यटन उद्योग को समग्र रूप से मजबूती मिलती है।

8.2 उद्योग विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुविधा और मानक

पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की कार्यनीति

एफ एंड एस प्रभाग संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों के विकास, निवेश संवर्धन और सुविधा एवं पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यापार में सुगमता से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

भारत के आर्थिक विकास और संवृद्धि में पर्यटन में निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन क्षेत्र एक बहुआयामी गतिविधि है जिसमें आतिथ्य, परिवहन, मनोरंजन और विभिन्न अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं, जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करके अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परिदृश्य, ऐतिहासिक स्मारकों और जीवंत परंपराओं का प्रदर्शन कर सकता है। होटल, परिवहन नेटवर्क और पर्यटक आकर्षण जैसी पर्यटन अवसंरचना में रणनीतिक निवेश न केवल रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, एक संपन्न पर्यटन क्षेत्र, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर और राजनयिक संबंधों को मजबूत करके भारत की वैश्विक छवि को सुधारता है। भारत सही निवेश के माध्यम से अपनी अप्रयुक्त क्षमता का दोहन कर सकता है, दुनिया भर में यात्रियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर सकता है, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और स्थायी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। चूंकि दुनिया आपस में अधिक जुड़ती जा रही है, अतः पर्यटन में निवेश के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह भारत के समावेशी और स्थायी विकास के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है।

होटल उद्योग में निवेश आवास अवसंरचना और आगंतुक अनुभवों को बेहतर बनाकर भारतीय पर्यटन को उत्प्रेरित कर सकता है। पर्याप्त वित्त पोषण विश्व स्तरीय होटलों, रिसॉर्ट्स और बुटीक आवास के विकास को सुगम बनाता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लुभाते हैं। उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करते हुए गंतव्यों के आकर्षण में योगदान देते हैं। यह निवेश न केवल रोजगार पैदा करता है बल्कि सेवा मानकों को भी ऊपर उठाता है, जिससे पर्यटक अनुकूल राष्ट्र के रूप में भारत की सकारात्मक धारणा को बढ़ावा मिलता है। बेहतर आवास के विकल्प समग्र पर्यटन इको-सिस्टम को प्रेरित करते हैं तथा भारत को प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करते हैं और अंततः आगंतुकों के खर्च में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

पर्यटन मंत्रालय एक स्वैच्छिक कार्यक्रम संचालित करता है जिसका उद्देश्य होटल, बेड और ब्रेकफास्ट इकाइयों, परिवहन संचालकों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों सहित पर्यटन क्षेत्र के विविध हितधारकों को मान्यता प्रदान करना है। यह पहल विभिन्न संस्थाओं के योगदान को स्वीकार और प्रोत्साहित करके पर्यटन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके अलावा, इन मान्यता प्राप्त साझेदारों को अंतरराष्ट्रीय रोड शो और यात्रा प्रदर्शनियों में मूल्यवान एक्सपोजर और मंच मिलता है। यह अवसर उन्हें पर्यटन पैकेजों और उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे देश के पर्यटन उद्योग को समग्र रूप से मजबूत करने में योगदान करते हैं।

8.2.1 उद्योग विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुविधा और मानक (आवास इकाइयां) की गतिविधियां

एफ एंड एस प्रभाग, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से निम्नलिखित अधिदेश को लागू किया है:

- संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों के विकास से संबंधित सभी मामले
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में एफडीआई सहित निवेश को बढ़ावा देने एवं सुगमता से संबंधित सभी मामलें
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यापार में सुगमता से संबंधित सभी मामले

दिनांक 21 जून, 2024 को माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उद्योग हितधारकों के बीच पर्यटन मंत्रालय ने एक इंटेरेक्टिव सत्र का आयोजन किया, जिसमें भारत में पर्यटन और आतिथ्य हितधारकों के समक्ष आने वाले मुद्दों के बारे में एक निर्णायक चर्चा की गई और नीति निर्धारण के सुझावों पर ध्यान दिया गया।

विश्व पर्यटन दिवस समारोह के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2024 को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के उद्योग की स्थिति पर एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई। इस पुस्तिका में उद्योग का दर्जा प्रदान करने से जुड़े लाभों के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सर्वोत्तम पद्धतियों और उद्योग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से आग्रह करता रहा है।

दिनांक 27 सितंबर, 2025 को विश्व पर्यटन दिवस, 2025 के अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के साथ समन्वय से होमस्टेज़ के लिए जन समर्थ पोर्टल पर मुद्रा ऋण चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया पर चरण-दर-चरण सहायता उपलब्ध करवाने वाली एक पुस्तिका का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में 11 सितंबर, 2025 को होमस्टेज़ के लिए मुद्रा ऋण के प्रावधान पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

8.3 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर - विशेष बल

8.3.1 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

I. एमडीए के दिनांक 28 नवंबर 2020 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, देश में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए पर्यटन सेवाप्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; एडीटीओआई, एटीओएआई, एफएचआरएआई, आईएटीओ, एबीटीओ, आईसीपीबी, आईएचएचए, आईटीटीए, एचएआई, टीएएआई, टीएएफआई एवं एफएआईटीएच सहित राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों और देश में प्रतिष्ठित वाणिज्य, उद्योग एवं व्यापार संगठनों/संघों जैसे कि सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त अन्य व्यापार संघों द्वारा आयोजित पर्यटन संबद्ध सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना; केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना; देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रोड शो में भाग लेना। इसके

अलावा, देश में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

II. इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसी राज्य, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का दौरा करने के लिए एक अतिरिक्त टूर (उपर्युक्त तीन टूर के अलावा) की अनुमति होगी। जहां तक पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का संबंध है, ग्रीन शूट्स/स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख/अंडमान एवं निकोबार/लक्षद्वीप में प्रचालन करने वाले अनुभवी टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए मान्यता प्रदान करने के मानदंडों में प्रदत्त पूंजी, वार्षिक टर्नओवर और कार्यालय स्थान के संदर्भ में छूट प्रदान की गई है।

8.3.2 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित किया जाता है और इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में चिह्नित द्वीपों के लिए 31 दिसंबर, 2022 के बाद आगे और 5 वर्ष अर्थात् 31 दिसंबर, 2027 तक की अवधि के लिए पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में 31 दिसंबर, 2022 के बाद और आगे 5 वर्ष की अवधि तक पीएपी/आरएपी से छूट देने संबंधी मामले को पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

****

कोनासीमा, आंध्र प्रदेश

09 कौशल एवं क्षमता निर्माण

मंत्रालय का कौशल और क्षमता निर्माण प्रभाग आतिथ्य, खानपान प्रौद्योगिकी, यात्रा, पर्यटन और इससे संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले चार शैक्षणिक संस्थानों के कार्य देखता है। इसके अलावा, यह एक अधीनस्थ संस्थान भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान (आईआईएसएम), जो कि साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है, के प्रशासनिक और प्रचार संबंधी मामलों को देखता है।

9.1 होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)

पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि आवश्यक अवसंरचना सहायता सहित प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाए जो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने में सक्षम हो। अब तक, 56 होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), (जिसमें 21 केंद्रीय आईएचएम और 33 राज्य आईएचएम, पीपीपी मोड के तहत चल रहे 2 राज्य आईएचएम) और **13 खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)** शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालय से सहायता प्राप्त है। जदगीशपुर, उत्तर प्रदेश में एक (1) केन्द्रीय आईएचएम निर्माणाधीन है। इन संस्थानों की स्थापना आतिथ्य शिक्षा/ आतिथ्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के विशिष्ट अधिदेश सहित स्वायत्त समितियों के रूप में की गई थी। जबकि आईएचएम मुख्य रूप से डिग्री स्तर की आतिथ्य शिक्षा देते हैं, एफसीआई कौशल स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

9.2 राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), पर्यटन मंत्रालय

आईएचएम और एफसीआई के शैक्षिक प्रयासों को संचालित करने और विनियमित करने के लिए, वर्ष 1982 में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) की स्थापना की थी। एनसीएचएमसीटी का अधिदेश अपने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य प्रबंधन शिक्षा के विकास में वृद्धि और सामान्य उन्नति का समन्वय करना है। परिषद का अधिकारक्षेत्र प्रवेश, शुल्क, उप-नियम, अध्ययन, पाठ्यक्रम, अनुसंधान और परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, परिणाम, भवन योजनाओं और उपकरणों को विनियमित करने, प्रशिक्षण, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन सहित प्रशासनिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला, साथ ही समय-समय पर निर्धारित ऐसी सरकारी अनुमोदित गतिविधियों को भी पूरा करने तक फैला हुआ है। एनसीएचएमसीटी संबद्धता प्रदान करने वाला निकाय भी है और 21 सीआईएचएम, 33 एसआईएचएम, 1 पीएसयू आईएचएम, 2 एसआईएचएम

जो पीपीपी मोड के तहत चलाए जाते हैं और 13 एफसीआई जो मंत्रालय से सहायता प्राप्त हैं, प्रवेश और परीक्षा के नियमों के लिए इससे संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी को निजी आईएचएम को संबद्ध करने का अधिदेश भी दिया गया है। अब तक 25 निजी संस्थान एनसीएचएमसीटी से संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी अपने संबद्ध संस्थानों के लिए आतिथ्य और होटल प्रशासन में 3 वर्षीय बीएससी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) भी आयोजित करता है। आतिथ्य प्रशासन में एमएससी में प्रवेश केंद्रीय रूप से परिषद द्वारा एक प्रवेश परीक्षा (एमएससी जेईई) के माध्यम से किया जाता है। अन्य पाठ्यक्रमों के मामले में, यानी पीजी डिप्लोमा इन एकोमोडेशन ऑपरेशन, पीजी डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड हॉस्पिटल फूड सर्विस, पीजी डिप्लोमा इन होटल कंसल्टेंसी, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन; खाद्य और पेय सेवा में डिप्लोमा; हाउस कीपिंग ऑपरेशन में डिप्लोमा, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन में डिप्लोमा, बेकरी और कन्फेक्शनरी में डिप्लोमा, फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स, फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसेरी में क्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स और प्रोफेशनल बारटेंडिंग में सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार संबंधित संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश दिए जाते हैं।

विभिन्न अल्पकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा, **वर्ष 2024-25** के दौरान कुल **23,495 छात्रों** ने एनसीएचएमसीटी द्वारा पेश किए गए विभिन्न नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नामांकन किया।

9.3 भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), पर्यटन मंत्रालय

वर्ष 1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), यात्रा और पर्यटन शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी है। यह पर्यटन और यात्रा उद्योग के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है। यह वर्तमान में अपने ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा स्थित केंद्रों से निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है:

- दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (पर्यटन और यात्रा प्रबंधन)
- तीन साल का पूर्णकालिक बीबीए (पर्यटन और यात्रा) कार्यक्रम
- पर्यटन में पीएच.डी. डिग्री

आईआईटीटीएम द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपरोक्त यूजी, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) की सहयोगी योजना के तहत हैं।

ये केन्द्र विभिन्न अल्पकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं।

आईआईटीटीएम को पिछले कई वर्षों से सरकारी या निजी क्षेत्र में छात्रों के 100% प्लेसमेंट होने का गौरव प्राप्त है।

आईआईटीटीएम के प्रस्तावित नए केंद्र

शिलांग और बोधगया में आईआईटीटीएम के नए केन्द्र खोलने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच, अल्पावधि कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शिलांग, मेघालय और बोधगया, बिहार में आईआईटीटीएम का एक शिविर शुरू किया गया है।

9.4 राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस)-आईआईटीटीएम, गोवा

भारत में शिक्षा/प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श तथा लीजर वॉटर स्पोर्टस संवर्धन की जारी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा को आईआईटीटीएम में शामिल किया गया था। वर्तमान में, एनआईडब्ल्यूएस परामर्श गतिविधियों, पेशेवर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम) रखरखाव, फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी) नौका मरम्मत, टिलर नियंत्रित पावरबोट हैंडलिंग, रिमोट कंट्रोल पावरबोट हैंडलिंग, जीवन रक्षक तकनीक, सर्फ जीवन रक्षक तकनीक आदि की पेशकश कर रहा है। यह कुछ कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है जैसे विंडसर्फिंग, नौकायन, वाटर स्कीइंग, कयाकिंग आदि। अत्याधुनिक सुविधाओं सहित एनआईडब्ल्यूएस-आईआईटीटीएम गोवा के नए परिसर का उद्घाटन दिनांक 06 फरवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया।

9.5 भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान (आईआईएसएम) गुलमर्ग

आईआईएसएम की स्थापना वर्ष 1987 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पाठ्यक्रम संचालित करके साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आईआईएसएम पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्थायी अधीनस्थ कार्यालय है। साहसिक कौशल विकसित करने के अलावा, यह देश में साहसिक पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय साहसिक नीतियों/कार्यक्रमों के निर्माण और विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार और निजी एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय के लिए पर्यटन मंत्रालय के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए साहसिक के सभी क्षेत्रों में साहसिक प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन करता है ताकि एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और देश में नए साहसिक स्थलों को विकसित किया जा सके। संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न साहसिक कौशल में जम्मू-कश्मीर सहित राष्ट्र के युवाओं को प्रशिक्षित करता है।

आईआईएसएम द्वारा वर्षपर्यंत आयोजित किए जाने वाले कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम हैं:

(क) दिसम्बर से मार्च तक स्नो स्कीइंग पाठ्यक्रम

(ख) जून से सितम्बर तक वाटर स्कीइंग पाठ्यक्रम

(ग) मई से अक्तूबर तक पैरासेलिंग पाठ्यक्रम

(घ) मई से नवम्बर तक ट्रेकिंग पाठ्यक्रम

(ङ) अक्तूबर से दिसम्बर तक हॉट एयर बैलून पाठ्यक्रम

(च) लघु कॉरपोरेट और स्कूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

9.6 भारतीय पाक कला संस्थान, तिरुपति

पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों से 97.92 करोड़ रुपये की कुल लागत से तिरुपति में एक भारतीय पाक कला संस्थान (आईसीआई) की स्थापना की है:-

(i) विरासतीय भारतीय व्यंजनों का परिरक्षण सुनिश्चित करना, (ii) अनुसंधान, प्रलेखन, संग्रहालय और पाक कला के संसाधन केन्द्र की स्थापना करना; और

(iii) पाक कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना। भारतीय पाक कला संस्थान अपने विशिष्ट क्षेत्र में एक संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। 98.50 करोड़ रुपए की कुल लागत से आईसीआई तिरुपति का एक खंड नोएडा में स्थापित किया गया है।

आईसीआई ने 2018-19 से आईसीआई, तिरुपति और नोएडा के लिए प्रत्येक में 60 छात्रों के प्रवेश के साथ 3 वर्षीय बीबीए पाक कला शुरू की है; तिरुपति और नोएडा परिसरों में 2019-20 शैक्षणिक वर्ष से एमबीए पाठ्यक्रम भी 30 छात्रों के साथ शुरू किया गया है। विभिन्न अल्पकालिक क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों के अलावा, वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 433 छात्रों (पिछले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान 187 छात्रों की तुलना में) ने आईसीआई द्वारा पेश किए गए विभिन्न नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के तहत नामांकन किया है।

इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट, तिरुपति

9.7 पर्यटन मंत्रालय की आईएचएम/एफसीआईएस/आईआईटीटीएमएस/एनसीएच एमसीटी/आईसीआई/पीएसयू की सहायता योजना

पर्यटन मंत्रालय की सुविधा प्रदान करने की एक योजना "आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएमएस/ एनसीएचएमटी/आईसीआई/पीएसयू की सहायता" है जिसके तहत होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) की स्थापना

के लिए 16.50 करोड़ रुपए, खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) के लिए 7.50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकती है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा सृजित आईएचएम की स्थापना अथवा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) या राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) या फिर भारतीय पाक कला संस्थान (आईसीआई) के केन्द्र/शाखा की स्थापना हेतु सहायता की मात्रा इस सीमा के अधीन नहीं होगी।

नए आईएचएम/भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों और एनसीएचएमसीटी के साथ संस्थान की संबद्धता के अधीन है। सामान्य अनुदान 12.50 करोड़ रुपये तक है, जिसमें से 10.00 करोड़ रुपये निर्माण के लिए है और शेष संस्थान द्वारा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए है। छात्रावासों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 4.00 करोड़ रुपये भी दिए जा सकते हैं। केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त व्यय को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। एक खाद्य शिल्प संस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता 7.50 करोड़ रुपए तक सीमित है। छात्रावासों के निर्माण और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण जैसी संस्थागत अवसंरचना के उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटरों की खरीद और संस्थानों के आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक उन्नयन के लिए है। बजट अनुमान चरण में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 35.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है एवं नवंबर, 2025 तक लगभग 11.28 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

9.8 सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

पर्यटन मंत्रालय ने प्रत्येक स्तर पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" नामक योजना शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की विशाल पर्यटन क्षमता को पूर्ण रुप से लाभ उठाने के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं के हर स्तर पर जनशक्ति को प्रशिक्षित और अपग्रेड करना है, और स्थानीय आबादी को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। सीबीएसपी योजना के माध्यम से कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है ताकि वे अनौपचारिक से औपचारिक नौकरियों में जा सकें जिससे आय में वृद्धि हो सके अथवा काम करने की स्थिति में सुधार हो सके।

9.8.1 यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) द्वारा अनुमोदित संस्थान, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केंद्रीय प्रशिक्षण/आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में कार्यरत संस्थान जिनमें निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं।

9.8.2 पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल अंतराल के अध्ययन के लिए पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय एक मिश्रित संस्थागत आधार के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान कर रहा है जिसमें पर्यटन मंत्रालय प्रायोजित होटल प्रबंधन और खाद्य शिल्प संस्थान, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और राज्य पर्यटन विकास निगमों के अधीन संस्थान शामिल हैं। लेकिन प्रशिक्षित

जनशक्ति की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए विशिष्ट युवाओं के बीच रोजगार योग्य कौशल के निर्माण के लिए "हुनर से रोजगार तक" (एचएसआरटी) नामक एक विशेष पहल शुरू की। इस पहल के अंतर्निहित उद्देश्य मुख्य रूप से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौशल अंतर को कम करना और बढ़ते पर्यटन के आर्थिक लाभों के समान वितरण की दिशा में काम करना है। स्किलिंग इंडिया और पर्यटन संवर्धन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुँच और आउटपुट का विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत सिद्ध योग्यता वाले व्यावसायिक कौशल विकास एजेंसियों तथा एआईसीटीई/एनइसडीए/राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अनुमोदित आतिथ्य संस्थानों को पैनल में शामिल करके उन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई। यह पहल वर्ष 2015-16 से शुरू की गई थी और अब तक 135 से अधिक संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में देश में एचएसआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में सक्रिय हैं।

9.8.3 सीबीएसपी योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:-

क. हुनर से रोजगार तक:- यह कार्यक्रम वर्तमान में 160 घंटे से 700 घंटे के कुल ग्यारह लघु अवधि पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन ग्यारह पाठ्यक्रमों में से आठ अर्थात मल्टी कुजीन कुक, फूड एंड बेवरेज सर्विस, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस, लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर, किचन स्टीवर्ड, होम डिलीवरी बॉय और ट्रेडिशनल स्नैक एंड सेवरी मेकर आतिथ्य से संबंधित हैं और अन्य तीन पाठ्यक्रम अर्थात हथियार रहित सुरक्षा गार्ड, हेरिटेज गाइड और टूर गाइड गैर-आतिथ्य पाठ्यक्रम हैं तथा पूर्ण रुप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी कुल उपलब्धि 24153 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र देना था। वित्त वर्ष 2024-25 के 31 मार्च, 2025 तक कुल 89801 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र दिया गया है।

ख. कौशल परीक्षण और प्रमाणन:- खाद्य उत्पादन, खाद्य और पेय सेवा, बेकरी और हाउसकीपिंग जैसे चार आतिथ्य व्यवसायों में मौजूदा सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं का कौशल परीक्षण और प्रमाणन। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी कुल उपलब्धि 4792 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र देना था। वित्त वर्ष 2024-25 के 31 मार्च, 2025 तक कुल 20842 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र दिया गया है।

ग. उद्यमिता कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अंतर्गत (i) कुक-तंदूर, (ii) बर्मन, (iii) बेकर, (iv) होमस्टे (मल्टी-स्किल्ड केयरटेकर) और (v) हलवाई-इंडियन स्वीट्स के व्यवसायों में 150 घंटे के पांच पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी कुल उपलब्धि 1822 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र देना था। वित्त वर्ष 2024-25 के 31 मार्च, 2025 तक कुल 369 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीबीएसपी योजना के तहत कुल 89,801 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र दिया गया।

घ. अन्य कार्यक्रम:- इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन जागरूकता/संचेतना कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक कोर्स 2 से 6 दिनों की अवधि का होता है। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अंततः पर्यटकों के लिए एक बेहतर सेवा का वातावरण एवं अनुभव प्रदान करना और स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना है।

इसके एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने इन प्रतिष्ठित स्थलों पर और इनके आस-पास ढाबावालों, टैक्सी/रिक्शा चालकों, पुलिस कर्मचारियों, होटल स्टाफ और दुकानदारों आदि को लक्षित करते हुए पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। ग्यारह केन्द्रीय आईएचएम को इस कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ङ. पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी:- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की। इस पहल को संचालित करने के लिए कुल 7 पर्यटन स्थलों अर्थात ओरछा (मध्य प्रदेश), गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश), बोधगया (बिहार), आइजोल (मिजोरम), जोधपुर (राजस्थान), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और श्री विजयपुरम (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) की पहचान की गई ।

इस पहल के माध्यम से, पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य पर्यटकों के लिए गंतव्यों पर समग्र अनुभव को बढाना है, जहाँ वे 'पर्यटक-हितैषी' ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो अपने गंतव्य के दूत और कहानीकार के रुप में वहाँ के गौरव हैं। यह उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करके किया जा रहा है जो एक गंतव्य विशेष पर पर्यटकों से वार्तालाप करते हैं और उनसे जुड़े हुए रहते हैं।

'अतिथि देवो भव' अभियान के तहत, कैब चालकों, ऑटो चालकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, और बस स्टेशनों के स्टॉफ, होटल स्टॉफ, रेस्तरां स्टॉफ, होमस्टे मालिकों, टूर गाइड, पुलिस कर्मियों, स्ट्रीट वेंडर, दुकानदारों, छात्रों और कई अन्य लोगों को पर्यटन, आम स्वच्छता, सुरक्षा, स्थिरता के महत्व और पर्यटकों को सर्वोच्च स्तर के आतिथ्य एवं देखभाल प्रदान करने के महत्व पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की गई।

इस वर्ष 15 अगस्त को इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से, इस पहल के तहत लगभग 4382 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.9 अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम का संचालन कर रहा है- यह एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बेसिक, उन्नत (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। उम्मीदवार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में कहीं से भी, किसी भी समय और अपनी गति के अनुसार भाग ले सकते हैं। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विभिन्न डिजिटल उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को सफलटापूर्वक पूरा करने पर, उम्मीदवार एक पेशेवर रूप से प्रमाणित पर्यटक सुविधा प्रदाता होगा जो पर्यटकों को जानकारी प्रदान करके, देश के बारे में उनमें रुचि पैदा करके और अनुभवात्मक पर्यटन प्रदान करके उनकी सहयता करेगा। यह कार्यक्रम 01 जनवरी, 2020 से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 11 जनवरी, 2021 के दिशानिर्देशों में संशोधन के माध्यम से, मौजूदा क्षेत्रीय स्तर के गाइडों (आरएलजी) को अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) का नया नाम दिया गया है और उन्हें आईआईटीएफ/आईआईटीजी की इस नई प्रणाली के साथ जोड़ा गया है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर मौजूदा क्षेत्रीय स्तर के गाइडों (आरएलजी) का नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कर दिया जाएगा और उनके संचालन के क्षेत्र को एक निर्दिष्ट क्षेत्र से बढ़ा कर पूरे भारत में विस्तारित किया गया है। कुल 3200 आरएलजी में से लगभग 2600 ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उन्हें आईआईटीजी के नए पहचान पत्र (आईडी) जारी किए गए हैं, जो उन्हें देश के अन्य पर्यटन स्थलों और गंतव्यों के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों और विरासत स्थलों पर गाइड का कार्य करने की अनुमति देते हैं।

अब तक, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता बेसिक कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा नौ बार आयोजित की जा चुकी है, और आईआईटीएफ के तहत कुल 5311 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईआईटीजी विरासत परीक्षाएं दो बार आयोजित की गई हैं, जिसमें 95 उम्मीदवारों को आईआईटीजी के तहत प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, 2661 उम्मीदवारों ने रिफ्रेशर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत 2020-21 से आईआईटीएफसी पाठ्यक्रम आयोजित करने, पाठ्यक्रम सामग्री अपलोड करने, परीक्षाएं आयोजित करने, ई-मार्केट प्लेस का विकास करने आदि पर निम्नलिखित खर्च किए गए हैं:-

आईआईटीएफसी का भुगतान विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जारी भुगतान
1.	2020-21	₹ 3.18 करोड़
2.	2021-22	₹ 6.50 करोड़
3.	2022-23	₹ 8.76 करोड़
4.	2023-24	₹ 2.80 करोड़
5.	2024-25	₹ 3.50 करोड़
	कुल	**₹ 24.74 करोड़**

पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (जिसे पहले आरएलजी कहा जाता था) के लिए एक समान आईडी और बैज (शेप, साइज़ और कलर कोडिंग) के विचार को अपनाया है। आईआईटीएफसी और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड के लिए आईडी/बैज को उनके अनुभव संबंधी मानदंड के आधार पर 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	आईआईटीएफसी/आईआईटीजी का विवरण	कलर बैज/कैटेगरी	आईडी से जुड़ा स्टार
1	आईआईटीएफसी (बेसिक)	बेसिक-नीला	एक (*)
2	आईआईटीजी (5 वर्ष से कम का अनुभव)	सिल्वर	दो (**)
3	आईआईटीजी (5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम का अनुभव)	गोल्ड	तीन (***)
4	आईआईटीजी (10 वर्षों से अधिक लेकिन 20 वर्षों से कम का अनुभव)	डायमंड	चार (****)
5	आईआईटीजी (20 से अधिक वर्षों का अनुभव)	प्लैटिनम	पांच (*****)

क्र.सं.	आईआईटीएफसी/आईआईटीजी का विवरण	कलर बैज/कैटेगरी	आईडी से जुड़ा स्टार
1	आईआईटीएफसी (बेसिक)	बेसिक-नीला	एक (*)
2	आईआईटीजी (5 वर्ष से कम का अनुभव)	सिल्वर	दो (**)
3	आईआईटीजी (5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम का अनुभव)	गोल्ड	तीन (***)
4	आईआईटीजी (10 वर्षों से अधिक लेकिन 20 वर्षों से कम का अनुभव)	डायमंड	चार (****)
5	आईआईटीजी (20 से अधिक वर्षों का अनुभव)	प्लैटिनम	पांच (*****)

भारत पर्यटन कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक इसे जारी कर रहे हैं।

9.10 आईआईटीएफ/आईआईटीजी के लिए देश (ई-मार्केटप्लेस) प्लेटफॉर्म

रोजगार सृजन के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने 08 मार्च, 2022 को आईआईटीएफ/आईआईटीजी के लिए डिजिटल पर्यटन समाधान के एक भाग के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-मार्केटप्लेस) की अवधारणा शुरू की, ताकि पर्यटकों और प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/पर्यटक गाइडों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरैक्शन तंत्र प्रदान किया जा सके। इसे 12 अगस्त, 2022 से ऑनलाइन (बीटा संस्करण) बनाया गया है। आईआईटीएफसी और आईआईटीजी अपने प्रोफाइल, अनुभव को अपडेट करने में सक्षम होंगे।

पोर्टल पर सेवाएं, योग्यता, विशेषज्ञता का क्षेत्र, टैरिफ, तिथियों की उपलब्धता आदि प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें पर्यटक अपनी प्रोफ़ाइल बना सकेंगे, पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की खोज कर सकेंगे और बुकिंग कर सकेंगे। पर्यटक, अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान से, किसी भी गंतव्य के लिए सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की खोज कर सकते हैं और देश की अपनी आगामी यात्राओं के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इस वेब-आधारित समाधान (ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म) का उपयोग सुविधाप्रदाताओं/गाइडों की प्रोफाइल, बुकिंग, रेटिंग प्रबंधित करने, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया (सकारात्मक और नकारात्मक), ज्ञात भाषाओं और सामग्री के प्रबंधन के लिए किया जाना है।

समाधान मॉड्यूलर विकास और आवश्यकता के आधार पर भविष्य में अतिरिक्त कार्यात्मकताओं की तैनाती का भी समर्थन करेगा, जैसे: टीम लीडर, सुपरवाइजर, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, गुणवत्ता विश्लेषक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आदि को शामिल करना। यह वेब-आधारित ई-मार्केट प्लेस के लिए वैश्विक मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप होगा, जहां पर्यटक न केवल इस पोर्टल के माध्यम से अपनी नियुक्ति निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि अपने सेवाप्रदाता को भुगतान भी कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय के आईआईटीएफसी/आईआईटीजी कार्यक्रम के तहत ई-मार्केटप्लेस पोर्टल का समग्र अनुभव ओएलए, उबर आदि के प्लेटफार्मों के समान होगा, जो आईआईटीएफ/आईआईटीजी को व्यापार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा और ग्राहक और सेवाप्रदाता के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा। यह पर्यटक गाइडों और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार 'अतुल्य भारत' ब्रांड को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

****

ब्रिटिश रेजीडेंसी, उत्तर प्रदेश

10 प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

10.1 लैंगिक समानता

पर्यटन, एक सेवा उद्योग होने के कारण, महत्वपूर्ण महिला प्रतिनिधित्व का दावा करता है। इसके परिणामस्वरुप, मंत्रालय लिंग संवेदीकरण और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के आश्वासन को महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं के रूप में प्राथमिकता देता है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि महिला अधिकारी/कर्मचारी अपनी क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले सकें।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुदेशों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के कार्यान्वयन में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, इस मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए 2003 में तत्कालीन सचिव (पर्यटन) की मंजूरी से एक शिकायत समिति का गठन किया था। मौजूदा अध्यक्ष/सदस्यों के स्थानान्तरण आदि के पश्चात् शिकायत समिति की संरचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

10.2 कल्याणकारी उपाय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लिए संपर्क अधिकारी, जो मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देते हैं, वह उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं। यह प्रकोष्ठ मुख्य रूप से समय-समय पर आरक्षण नीति के संबंध में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सभी भर्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण आदेशों के अनुसार की जा रही हैं और तदनुसार आरक्षण रोस्टर बनाए जाते हैं। इस विषय पर संबंधित प्राधिकारियों को नियमित वार्षिक विवरणियां अग्रेषित की जाती हैं।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

श्री अनुज गोयल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) के दिनांक 16 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 34-16/2018-डीडी-III के निर्देश में, पर्यटन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने समूह 'क', 'ख' और 'ग' में विभिन्न स्तर के विभिन्न पदों को चिह्नित किया, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसरण में बेंचमार्क दिव्यांगता हेतु सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त थे। उक्त जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट (http://tourism.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

पर्यटन मंत्रालय के सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व।

मंत्रालय में एक आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और डीएस (प्रशासन) संपर्क अधिकारी हैं। मंत्रालय के क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों में, संबंधित क्षेत्रीय निदेशक संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रतिनिधित्व डेटा और आंकड़े।

पर्यटन मंत्रालय (मुख्य सचिवालय/मुख्यालय)

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	4	2	7	1	0	शून्य	शून्य
ग्रुप क के पद	36	4	2	7	1	0	0	0
ग्रुप ख के पद	52	10	2	9	2	1	0	5
ग्रुप ग के पद	44	7	3	11	3	4	2	3

उत्तरी क्षेत्र

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप क के पद	2	0	0	1	0	0	0	0
ग्रुप ख के पद	14	1	1	1	1	0	4	0
ग्रुप ग के पद	9	0	0	0	0	0	0	3 (2 अ.पि.व., 1 अ.जा.)

दक्षिणी क्षेत्र

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप क के पद		0	0	2	0	0	0	0
ग्रुप ख के पद	7	1	1	5	0	0	4	0
ग्रुप ग के पद	11	4	0	6	0	0	0	0

पश्चिमी और मध्य क्षेत्र

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप क के पद	1	0	0	1	0	0	0	0

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
ग्रुप ख के पद	26	4	1	4	1	2	1 (SC), 1 (OBC), 2 (EWS), 1 (PwD)	1 (SC), 1 (OBC)
ग्रुप ग के पद	14	4	2	1	2	0	0	OBC-1, EWS-1

पूर्वी क्षेत्र

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप क के पद	1	0	0	1	0	0	0	0
ग्रुप ख के पद	6	1	1	2	0	0	0	SC-0, ST-1, OBC-1, EWS-1, PwD-1 (HH)
ग्रुप ग के पद	14	4	0	4	0	0	0	SC-0, ST-0, OBC-4 EWS-0, PwD-0

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

	वर्तमान पदधारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	वर्ष 2025 में भरी गई कुल लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	दिनांक 01.01.2026 तक लंबित (बैकलॉग) रिक्तियाँ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन)	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप क के पद	1	0	0	1	0	0	0	0
ग्रुप ख के पद	7	1	0	4	0	0	1 (OBC)	0
ग्रुप ग के पद	1	0	1	0	0	0	0	1 (SC), 1 (OBC), 1 (EWS)

10.2.1 युवा पर्यटन क्लब पोर्टल- देश भर में युवा पर्यटन क्लबों के विवरण और कार्यकलापों की जानकारी एकत्र करने के लिए युवा पर्यटन क्लब पोर्टल https://ytc tourism.gov.in का संचालन किया गया है। सदस्य विशिष्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और इस पर अपनी विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। यह मंच न केवल सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यटन पहल को बढ़ावा देने में रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। भागीदारी के माध्यम से, सदस्य उत्तरदायी और स्थायी पर्यटन प्रथाओं के बारे में सीखते हुए टीम वर्क और नेतृत्व जैसे आवश्यक कौशल प्राप्त करते हैं।

कुल **9,568 युवा पर्यटन क्लब पंजीकृत हैं, जिनमें 18,015 सदस्य हैं और अब तक 1,961 आयोजन आयोजित किए गए हैं।**

10.2.2 प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ ग्राम ग्रामीण पर्यटन प्रतियोगिता

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम (बीटीवी) 2025 प्रतियोगिता का उद्देश्य उन गांवों को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है, जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए उत्कृष्ट पर्यटन पहलें प्रस्तुत करते हैं। यह दस्तावेज़ भाग लेने वाले गांवों, जिलों और राज्यों के लिए आवेदन प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड तथा प्रस्तुति संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इन निर्देशों का पालन करके आवेदक एक सुचारू प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं तथा अपनी चयन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। दिशा-निर्देशों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सर्वोत्तम प्रक्रियाएं, मूल्यांकन प्रक्रियाएं तथा डिजिटल फ़ाइल प्रबंधन से संबंधित विवरण भी शामिल हैं, ताकि एक प्रभावी और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम (बीटीवी) 2025 के लिए एक ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया विकसित की गई है।

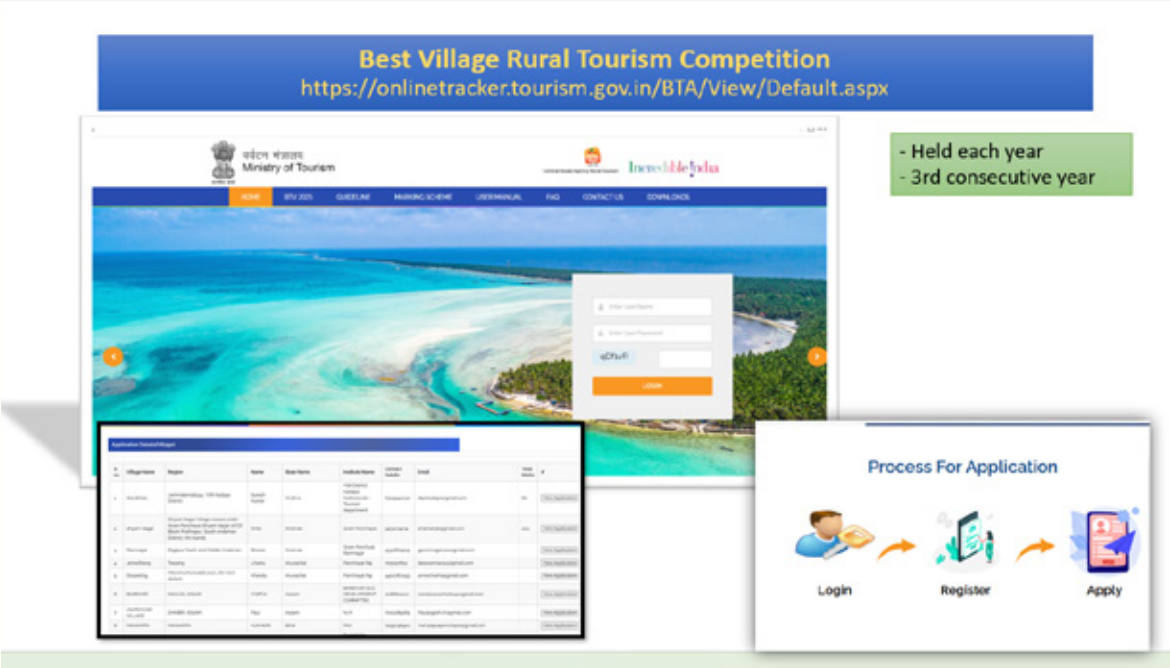

10.2.3. टूरिस्ट सेंटिमेंट ट्रैकर — यह एक अभिनव फीडबैक तंत्र है, जिसे कार्यनीतिक रूप से स्थापित किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से देशभर के पर्यटकों से अद्यतन फीडबैक एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगाए गए इन क्यूआर कोड्स को पर्यटक अपने स्मार्टफोन से आसानी से स्कैन कर सकते हैं और एक सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। यह सरल और सुगम प्रक्रिया पर्यटकों को केवल कुछ क्लिक में अपने अनुभव, सुझाव और समस्याएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्राप्त फीडबैक डेटा को स्वचालित रूप से संकलित एवं विश्लेषित किया जाता है, जिससे मंत्रालय को प्रमुख रुझानों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पर्यटकों की अपेक्षाओं और समस्याओं की समय पर पहचान कर मंत्रालय पर्यटन सेवाओं, सुविधाओं और अवसंरचना में समय पर डेटा-आधारित सुधार कर सकता है। **टूरिस्ट सेंटिमेंट ट्रैकर** प्रत्येक पर्यटक के लिए अधिक व्यक्तिगत और उच्च-गुणवत्तापूर्ण अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सके।

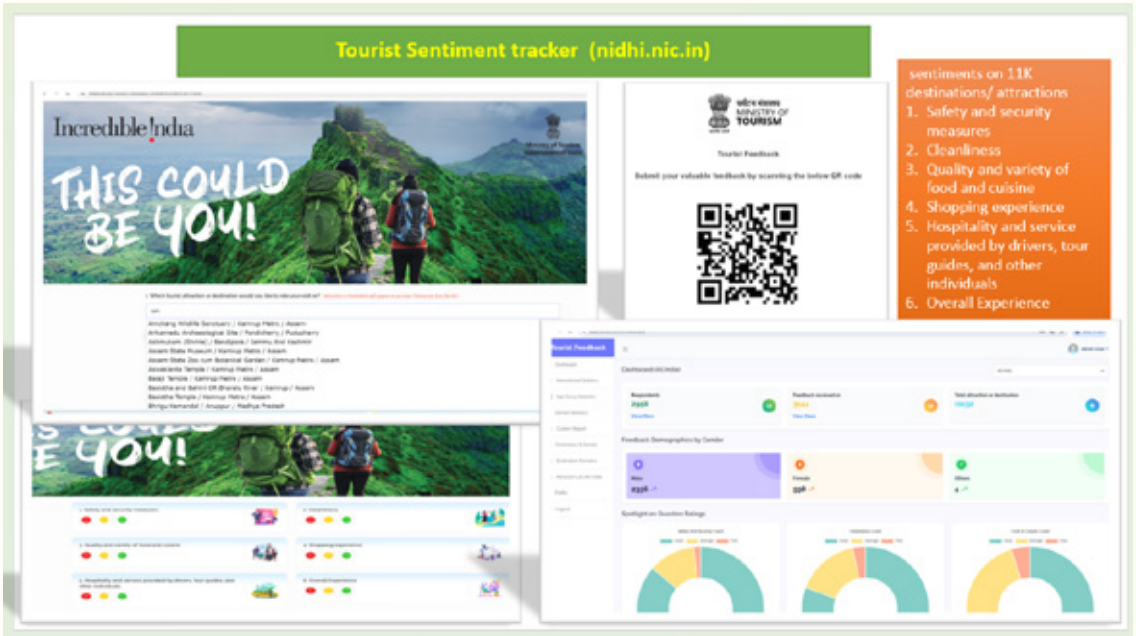

देशभर के 11,000 पर्यटन स्थलों/आकर्षणों पर पर्यटकों के अनुभवों को विभिन्न मानदंडों जैसे 1. सुरक्षा उपाय, 2. सफाई, 3. भोजन और व्यंजनों की गुणवत्ता और विविधता, 4. खरीदारी का अनुभव, 5. ड्राइवर, टूर गाइड और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई आतिथ्य सेवा तथा कुल अनुभव के आधार पर मापा गया है। टूरिस्ट सेंटिमेंट ट्रैकर https://nidhi.nic.in/Tracker/Notification पर उपलब्ध है। फीडबैक फॉर्म तक पहुँचने के लिए QR कोड https://nidhi.nic.in/Home/DownloadQR लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

10.2.4. देखो अपना देश अभियान

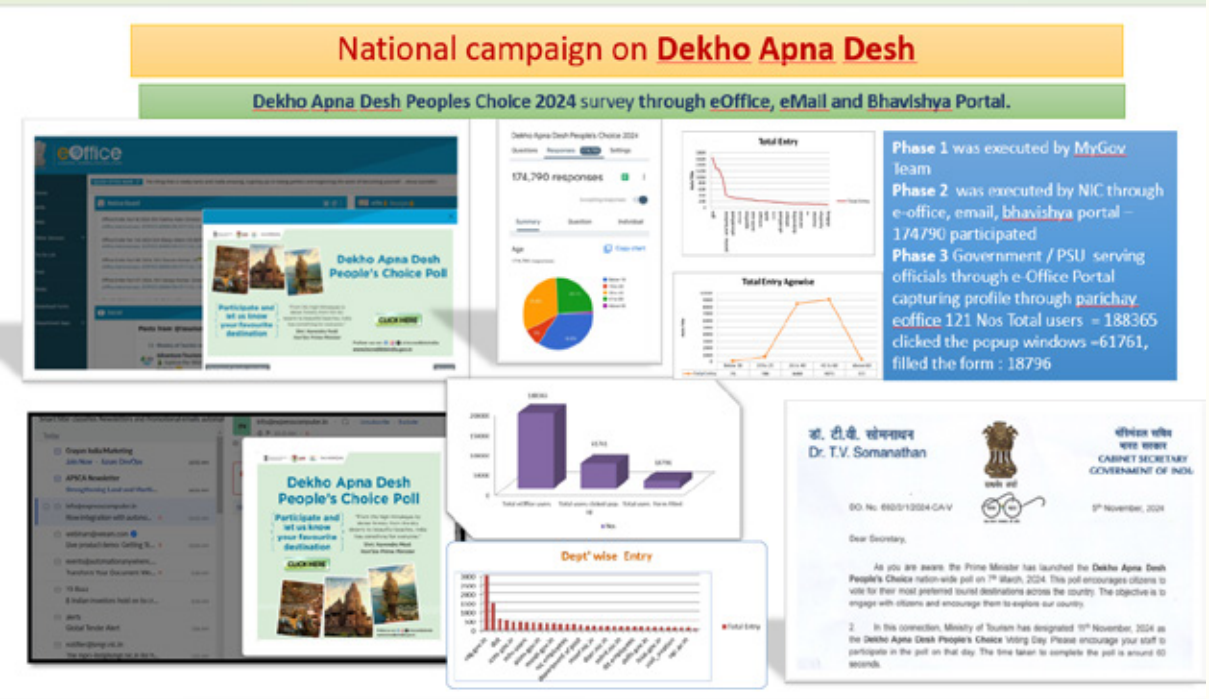

देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस के तहत राष्ट्रव्यापी मतदान आयोजित किया गया। चरण-1 में इसे MyGov टीम द्वारा एसएमएस और व्हाट्सएप अभियान के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। चरण-2 में इसे ई-ऑफिस, ईमेल और भविष्य पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें 1,74,790 लोगों ने भाग लिया। चरण-3 में 1,88,365 सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों ने ई-ऑफिस से जुड़े परिचय प्रमाणीकरण में भाग लिया।

10.2.5 उत्सव पोर्टल

https://utsav.gov.in भारत के विविध राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित होने वाले जीवंत कार्यक्रमों और महोत्सवों को प्रदर्शित करने वाला एक मंच है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाइव दर्शन की सुविधा भी शामिल है। यह पोर्टल सरकारी और कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और राष्ट्रीय महोत्सवों, धार्मिक उत्सवों, सम्मेलनों और संगीत कार्यक्रमों जैसे विभिन्न आयोजनों के सूचीबद्ध विवरण की सुविधा प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए और ऑनलाइन प्रकाशित करने से पहले राज्य, क्षेत्रीय निदेशक, और पर्यटन मंत्रालय के प्रशासक द्वारा गहनता से समीक्षा की जाती है। उत्सव पोर्टल न केवल इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हाइलाइट करता है, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और खेल के समकालीन उत्सवों को भी प्रदर्शित करता है।

10.2.6 जीईएम (GeM) के माध्यम से एआई के लिए जीपीयू सहित हाइपरस्केल गूगल क्लाउड की खरीद

गंतव्य और विकास पोर्टल को एआई-सक्षम बनाने के लिए GeM के माध्यम से जीपीयू सहित हाइपरस्केल गूगल क्लाउड स्पेस की खरीद की गई है।

10.2.7 भंडार प्रबंधन

मंत्रालय के नेटवर्क के भीतर भंडार प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) स्थापित की गई है। यह प्रणाली बिजनेस स्टॉक की निगरानी, नियंत्रण और अनुकूलन के लिए एक डिजिटल समाधान प्रदान करती है।

10.2.8 ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन्स

क. मंत्रालय में GOV.IN **सुरक्षित इंट्रानेट https://govintranet.gov.in/**को लागू किया गया है, जो सरकार की कार्यप्रणालियों को सुगम बनाने और आवश्यक एप्लीकेशन्स तक एकल साइन-ऑन की सुविधा प्रदान करने वाला वन-स्टॉप समाधान है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता ई-मेल, ई-ऑफिस और स्पेरो सहित अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स को एक्सिस कर सकते हैं। GOV.IN सुरक्षित इंट्रानेट (जीओवीइंट्रानेट) में

जी2ई एकल साइन-ऑन (एसएसओ) और सुरक्षित एक्सिस, वर्चुअल मीटिंग्स (जैसे भारतवीसी, गूगल मीट, वेबएक्स) आदि, फाइल साझा करने के लिए कोलेबफाइल्स, जीओवीड्राइव, आगंतुक प्रबंधन स्वागतम, टास्क मेनेजमेंट गोल ट्रेकर, एंगेजमेंट मेनेजमेंट, एआई मीटिंग असिस्टेंट, वर्चुअल मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन समराइज़ेशन, भाषिणी इंटीग्रेशन, अनुवाद, लिप्यंतरण तथा एग्जिक्युटिव डैशबोर्ड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

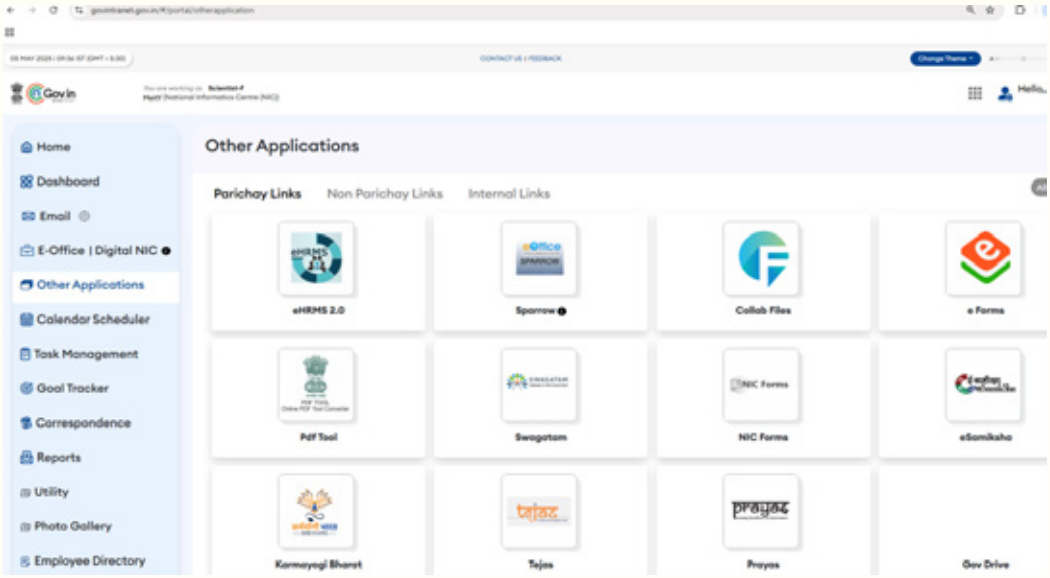

ख. ई-ऑफिस/स्पेरो

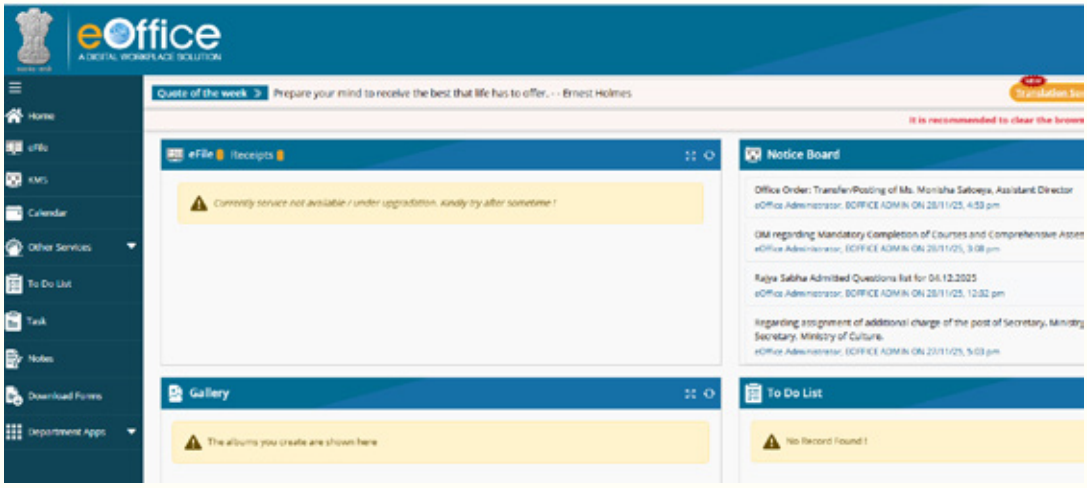

ई-ऑफिस पोर्टल किसी भी स्थान से कार्यालयी कार्य करने की सुविधा प्रदान करने वाला वर्चुअल कार्यालय का प्रवेश द्वार है और अधिकारियों को किसी भी स्थान से अपने कार्यालय से सुरक्षित रूप से जोड़ता है।

स्पेरो (स्मार्ट कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसे अधिकारियों/उपयोगकर्ताओं के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज और कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

10.3 सतर्कता

सतर्कता प्रभाग एवं उसके कार्यों का अवलोकन

विभिन्न सतर्कता संबंधी मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय में एक सतर्कता प्रभाग कार्यरत है। इस प्रभाग द्वारा किए

जाने वाले कार्यों में मुख्य रूप से मंत्रालय में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटान शामिल है। सतर्कता प्रभाग, सतर्कता मामलों में मंत्रालय और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने से संबंधित मामलों के साथ-साथ लंबित मामलों के निपटान एवं उनकी निगरानी से भी संबंधित कार्य करता है। सतर्कता नियमावली तथा सीवीसी द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार शिकायतों और मामलों की नियमित रिपोर्टिंग भी सीवीसी को की जाती है।

सतर्कता प्रभाग वार्षिक संपत्ति रिपोर्ट, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, सतर्कता स्वीकृति प्रदान करने आदि से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है।

निवारक सतर्कता उपाय

सतर्कता प्रभाग विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि संवेदनशील स्थलों पर तैनात अधिकारियों का नियमित स्थानांतरण और कार्यस्थल परिवर्तन, जीईएम (सरकारी ई-मार्किटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ई-ऑफिस प्रणाली का पालन आदि।

तीन माह के अभियान और सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

पर्यटन मंत्रालय ने 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक निवारक सतर्कता पर आधारित तीन महीने के अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन शामिल था। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय, इसके कार्यालय और संबद्ध संगठन ने सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। मंत्रालय और इसके स्वायत्त निकायों के अधिकारियों को मुख्य विषयों जैसे चार्जशीट तैयार करना, सीटीई जैसी गहन परीक्षा का संचालन, जांच प्रक्रियाएँ और रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

10.4 विभागीय लेखा संगठन

10.4.1. सचिव (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) एवं मंत्रालय के मुख्य वित्तीय नियंत्रक के माध्यम तथा सहायता से वह अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

10.4.2 मुख्य वित्तीय नियंत्रक लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं और प्रधान लेखा कार्यालय/वेतन एवं लेखा कार्यालय (पर्यटन) के माध्यम से मंत्रालय का पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में मंत्रालय के वित्तीय नियंत्रक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार है:

राजस्व खंड	2534.93 करोड़ रु.
पूंजी खंड	6.13 करोड़ रु.
कुल	**2541.06 करोड़ रु.**

पर्यटन मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, एक वेतन और लेखा कार्यालय और आंतरिक लेखा परीक्षा विंग शामिल हैं।

10.4.2.1 प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के लिए प्रधान लेखा कार्यालय एक ही है, जो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है:

क. सिविल लेखा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार और लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित तरीके से पर्यटन मंत्रालय के खातों का समेकन।

ख. मासिक और वार्षिक लेखा तैयार करना, केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण और वित्त लेखा के लिए सामग्री लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

ग. विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अंतर-विभागीय प्राधिकार जारी करने में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए लेखा महानियंत्रक कार्यालय से संपर्क रखना।

घ. वेतन और लेखा के लिए तकनीकी सलाह का प्रतिपादन।

10.4.2.2 बजट और लेखा

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2023 के का.ज्ञा. संख्या 23 (3)/ई.कोर्ड/2018 द्वारा जारी संशोधित चार्टर के अनुसार बजट और लेखा प्रभाग मुख्य वित्तीय नियंत्रक, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के तहत कार्य करता है और निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है।

1. अनुदान योजना/गैर-योजना घटकों के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित अनुमान तैयार करना।
2. बजट-पूर्व बैठक पर विभिन्न स्टेटमेंट तैयार करना, विस्तृत अनुदान मांग पर नोट तैयार करना, वित्त मंत्रालय की केन्द्रीय बजट सूचना प्रणाली का प्रचालन।
3. व्याख्यात्मक नोट्स/सेविंग नोट्स तैयार करना, एसबीई तैयार करना- बजट अनुमान का विवरण और डीडीजी के साथ इसका ऑनलाइन मानचित्रण।
4. अनुपूरक अनुदान मांग और विस्तृत अनुदान मांग तैयार करना।
5. विनियोजन लेखा तैयार करना और पुनर्विनियोजन आदेश, समर्पण आदेश जारी करना।
6. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों से संबंधित पैरा की निगरानी करना।
7. नीति आयोग तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के समन्वय से आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) की तैयारी।

10.4.2.3 वेतन और लेखा कार्यालय

वेतन और लेखा कार्यालय मंत्रालय का राजकोष है एवं निधियों को जारी करने, व्यय नियंत्रण, तथा अन्य प्राप्तियों और भुगतान कार्यों की निम्नानुसार निगरानी करता है:

i. मंत्रालय के गैर-चेक आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बिलों की पूर्व जांच।

ii. देश के विभिन्न भागों में स्थित 19 सीडीडीओ को चेक आहरित और संवितरण अधिकारियों को "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करके निधियों का प्राधिकार देना।

iii. सभी सीडीडीओ द्वारा किए गए सभी सशुल्क वाउचरों/भुगतानों की बाद में जांच।

iv. मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित सांविधिक निकायों और राज्य स्तरीय एजेंसियों को ऋण/सहायता अनुदान का भुगतान करना।

v. मासिक व्यय, प्राप्तियों और भुगतान के प्राधिकारों के आधार पर मासिक खाते का संकलन, जिसमें सीडीडीओ के मिलान किए गए खातों को विधिवत शामिल किया गया है।

vi. सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों का रख-रखाव और न्यासी बैंकों को नई पेंशन योजना के अंशदान का विप्रेषण, आवक और बाह्य दावों का निपटान, पेंशन का प्राधिकार/भुगतान, कम्युटेशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि।

10.4.2.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा, जो नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के लिए एक ही है, में चार सहायक लेखा अधिकारियों और चार लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों की स्वीकृत संख्या है जिसका नेतृत्व मुख्य वित्तीय नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन की भूमिका मुख्य रूप से यह निरीक्षण करना है कि व्यय नियंत्रण तंत्र निर्मित है और वित्तीय स्वामित्व से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक लेखा परीक्षा आवधिकता, बजट आवंटन और कार्यालय विशेष/एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना की प्रकृति और दायरे के आधार पर एक वार्षिक लेखा परीक्षा कैलेंडर तैयार करती है।

पर्यटन मंत्रालय में 49 लेखा परीक्षा योग्य इकाइयां हैं। इसमें 27 स्वायत्त निकाय, 19 सीडीडीओ (04 आरडीआईटी, 15 आईटी घरेलू) और 03 एनसीडीडीओ (पीएओ (पर्यटन), पर्यटन मंत्रालय (मुख्यालय) और आरडीआईटी (दिल्ली) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आईएचएम कोलकाता, आईएचएम मुंबई और हिमालयी सर्किट-मनाली (स्वदेश दर्शन) के विकास और नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (स्वदेश दर्शन) की योजना की लेखा परीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की गई।

आंतरिक लेखा परीक्षा के लंबित पैरा की स्थिति निम्नानुसार है:

इकाइयों की संख्या	अब तक लंबित पैरा
49	422

10.4.2.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय के लेखा संगठन ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म पर ई-बिल को पूरी तरह से लागू कर दिया है, जिससे कार्यान्वयन एजेंसी स्तर तक भुगतान और लेखा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की सुविधा प्राप्त हुई है।

10.4.3.1 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियों पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक ऑनलाइन भुगतान और लेखा मंच है।

पीएफएमएस निधि अंतरण के लिए एक केंद्रीकृत और पूरी तरह से प्रचालित आईटी अनुप्रयोग है जो "जस्ट इन टाईम रिलीज" और अंतिम लाभार्थियों तक निधियों के उपयोग की पूर्ण निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय में सभी स्तरों पर पीएफएमएस को कार्यान्वित किया गया है और सभी निधियां पीएफएमएस के माध्यम से जारी की जा रही हैं। सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल को रोल आउट करने के लिए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

10.4.3.2 ई-बिल

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रणाली विकसित की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46 वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम' पहल का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाने का प्रयास करता है जो वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करने योग्य है। इलेक्ट्रॉनिक बिल को हर स्तर पर डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है और भुगतान भी विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाता है। वेंडर/आपूर्तिकर्ता ऑनलाइन अपने बिलों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम है। बिलों को फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफआईएफओ) विधि में संसाधित किया जाता है। अधिकांश बिलों को अब ई-वे बिल के माध्यम से संसाधित किया जाता है।

10.4.3.3 ई-पीपीओ

ई-पीपीओ प्रणाली पेंशनभोगियों को भुगतान के लिए सीपीएओ से बैंकों के सीपीपीसी को ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित प्राधिकरण भेजने के लिए विकसित किया गया। वर्तमान में, सीपीएओ से 23 बैंकों (29 में से) को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित संशोधन प्राधिकरण भेजे जा रहे हैं। शेष 6 बैंक इस परियोजना के अंतर्गत शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। डिजी लॉकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ईपीओ) के एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है।

10.4.3.4 केंद्रीय नोडल एजेंसी

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी प्रक्रिया में संशोधन किया है। केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं, जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हों, ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) या केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। पर्यटन मंत्रालय में मंत्रालय द्वारा नामित दो सीएनए हैं: (i) "आईएचएम /एफसीआई /आईआईटीटीएम / एनआईडब्ल्यूएस को सहायता" और "केंद्रीय एजेंसियों की सहायता" नामक योजनाओं के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) और (ii) "विशिष्ट थीमों के आसपास पर्यटक परिपथों का

एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)" और "तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) नामक योजनाओं के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ।

10.4.3.5 एकल नोडल एजेंसी

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और दक्षता के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग को जारी करने और निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित एक एजेंसी है। पर्यटन मंत्रालय की "महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल" योजना इस मॉडल के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

10.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

लेखापरीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली (ई-एपीएमएस) महालेखा नियंत्रक रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2024 तक पर्यटन मंत्रालय के पास और सी एंड एजी के 6 लेखा परीक्षा पैरा और एक संपूर्ण रिपोर्ट लंबित है।

10.6 राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों पर कार्रवाई करने और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग हर संभव कार्रवाई करता है। इसके साथ-साथ राजभाषा प्रभाग मंत्रालय से संबंधित अनुवाद कार्य का भी निपटान करता है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन

राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। मंत्रालय का हिंदी में पत्राचार धीरे-धीरे बढ़ रहा है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फाइलों पर की जा रही हिंदी नोटिंग में भी लक्ष्यानुसार बढ़ोतरी हो रही है।

2. समितियां

i. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति:** मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.का.स.) का गठन किया गया है और इसकी तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय के अनुभागों द्वारा हिंदी में किए जा गए कार्य की समीक्षा की जाती है। अभी तक मंत्रालय में वर्ष 2025-26 की 3 तिमाहियों के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

ii. **संसदीय राजभाषा समिति:** वर्ष 2025-26 के दौरान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की जांच करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन

कार्यालयों का निरीक्षण किया है। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों की निरीक्षण बैठकों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं राजभाषा प्रभारी अधिकारी के रूप में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/प्रभारी अधिकारी तथा राजभाषा अनुभाग के अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण बैठकों में समिति को दिए गए आश्वासनों की समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूर्ति की जाती है।

3. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय:

i. **प्रोत्साहन योजना और नकद पुरस्कार:** मूल रूप से हिंदी में टिप्पण-आलेखन करने के लिए राजभाषा विभाग की वार्षिक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26 के लिए मंत्रालय में लागू की गई। इस योजना के तहत विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

ii. **हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा/माह:** पर्यटन मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर 2025 को हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। मंत्रालय के ई-ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर हिंदी दिवस से संबंधित माननीय गृह मंत्री की अपील तथा सचिव (पर्यटन) का संदेश जारी किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान चित्र अभिव्यक्ति, अनुवाद लेखन तथा हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने इनमें उत्साह से भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में हिंदी दिवस और पांचवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सहायक निदेशक (रा.भा.), पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया।

iii. **हिंदी कार्यशालाएं:** सरकारी कामकाज हिंदी में करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

iv. **अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण:** राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित मंत्रालय/विभाग द्वारा 25% अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के राजभाषाई निरीक्षण के लक्ष्यानुसार वर्ष 2025-26 में पर्यटन मंत्रालय के 11 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।

10.7 स्वच्छ भारत मिशन

''स्वच्छता'' को पर्यटन के एक स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि लंबी अवधि में स्वच्छ पर्यटन स्थल अधिक टिकाऊ होते हैं जो पर्यटन तथा निवेश आकर्षित करते हैं। इससे स्वास्थय भी अच्छा रहता है तथा स्थानीय निवासियों में गर्व की भावना और पर्यटकों में संतुष्टि की भावना पैदा होती है। स्वच्छ भारत मिशन एक "राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम" है और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छता से संबंधित कार्यकलापों और कार्यक्रमों को पर्यटन मंत्रालय के पीएमयू - एसबीएम प्रभाग द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, जो देश के भीतर पर्यटन के निरंतर विकास के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व पर बल देते हैं। इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेते हैं। कार्यान्वित कार्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:-

10.7.1 <u>स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)</u> - एसएपी के तहत देश भर में तीन प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यानी पर्यटक जागरूकता कार्यक्रम, छात्र जागरूकता कार्यक्रम और पर्यटन हितधारकों का जागरूकता कार्यक्रम। पर्यटन मंत्रालय भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), ग्वालियर, केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (सीआईएचएम), राज्य होटल प्रबंध संस्थान (एसआईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) और अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एआईएच एंड टीएम) के माध्यम से एसएपी के अंतर्गत उपर्युक्त श्रेणियों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने देशभर में पर्यटकों, छात्रों और पर्यटन हितधारकों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएपी 2025-26 के तहत लगभग 200 कार्यकलापों को मंजूरी दी है। यह अपेक्षा की जाती है कि हर जागरूकता संबंधी कार्यकलाप प्रत्येक स्थल पर 500 पर्यटकों, 100 छात्रों और 60 हितधारकों को कवर करे

10.7.2 <u>स्वच्छता पखवाड़ा (एसपी)</u> - देश भर में हर साल सितंबर के महीने में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की अवधि पंद्रह दिन (16-30 सितंबर) है। इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों (भारत पर्यटन कार्यालय), आईटीडीसी, शैक्षणिक संस्थानों (आईआईटीटीएम, सीआईएचएम, एसआईएचएम, एफसीआई) और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के पर्यटन विभागों ने देश में अपने-अपने स्थानों पर विभिन्न स्वच्छता कार्यकलाप शुरू किए थे।

इस अवधि के दौरान कुल 277 कार्यकलाप किए गए जिनमें लगभग 10,551 व्यक्तियों ने भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को मीडिया सेंटर, परिवहन भवन, नै दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।

10.7.3 स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) – एसएचएस कार्यकलापों का आयोजन प्रति वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाता है। एसएचएस-2025 का विषय **"स्वच्छोत्सव"** था। इस पहल के तहत पर्यटन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों (आईआईटीटीएम, केंद्रीय आईएचएम, राज्य आईएचएम, एफसीआई) और राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के पर्यटन विभागों ने स्वच्छता अभियान चलाए। इन एजेंसियों ने देश भर में विभिन्न स्वच्छता एवं जन-भागीदारी कार्यकलाप आयोजित किए। इस अवधि के दौरान, कुल **244 कार्यकलाप** किए गए, जिनमें लगभग **8,659 व्यक्तियों** की भागीदारी रही।

सफाई मित्रों को सम्मानित करने हेतु **19 सितंबर 2025** को परिवहन भवन स्थित मीडिया सेंटर में एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में सफाई मित्रों को स्वच्छता प्रहरी का डिग्निटी बैज, अंगवस्त्र तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा उत्सव के समापन के अवसर पर, पर्यटन मंत्रालय द्वारा **25 सितंबर 2025** को आईएचएम पूसा, नई दिल्ली में एक **भव्य कार्यक्रम** का आयोजन किया गया। इसमें महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि तथा **स्वच्छ भारत दिवस** के उत्सव के रूप में सचिव (पर्यटन) की उपस्थिति में एक व्यापक स्वच्छता अभियान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग **500 प्रतिभागियों** ने भाग लिया।

10.7.4 <u>स्वच्छता अभियान 2025</u> – माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निर्देशानुसार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 से **31 अक्टूबर 2025** तक **स्वच्छता अभियान** का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालयों एवं

संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए गए। स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय के एसबीएम प्रभाग द्वारा **17 अक्टूबर 2025** को परिवहन भवन, नई दिल्ली के परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया।

स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी) 2025–26 के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का चित्र

एफसीआई अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा 19 नवंबर 2025 को होटल रमाडा, अलीगढ़ में पर्यटन हितधारकों के लिए नुक्कड़ नाटक-आधारित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एफसीआई अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा 27 नवंबर 2025 को बॉयज़ पॉलिटेक्निक के सभागार, एएमयू अलीगढ़ में पर्यटन हितधारकों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक सेमिनार आयोजित किया गया।

एसआईएचएम दीमापुर, नागालैंड द्वारा स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी) 2025–26 के अंतर्गत 22 नवंबर 2025 को संस्थान परिसर में पर्यटन हितधारकों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक सेमिनार आयोजित किया गया।

स्वच्छता ही सेवा 2025 के छायाचित्र

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2025 को सचिव (पर्यटन) की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष स्वच्छता अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया। इस अवसर पर सफाई कर्मियों /सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने हेतु सचिव (पर्यटन) ने उन्हें सराहना स्वरूप पौधा भेंट कर सम्मानित किया।

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित करने हेतु 19 सितंबर 2025 को मीडिया सेंटर, परिवहन भवन में एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भारत पर्यटन गुवाहाटी, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) के सहयोग से विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर "पर्यटन और सतत परिवर्तन" नामक थीम के अंतर्गत गुवाहाटी स्थित ऐतिहासिक असम राज्य संग्रहालय में स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के छायाचित्र

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सचिव (पर्यटन) एवं वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (पर्यटन) द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

एसआईएचएम सिलवासा परिसर एवं उसके आसपास व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता अभियान

संस्थान के छात्रों और संकाय द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान संस्थान द्वारा पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के छायाचित्र

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2025 को मीडिया सेंटर, परिवहन भवन में **स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार समारोह 2025** का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता पखवाड़ा (16–30 सितंबर 2025) के दौरान स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप संचालित करने वाले संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। **अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक (पर्यटन), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (पर्यटन) एवं आर्थिक सलाहकार (पर्यटन)** द्वारा आईएचएम जयपुर, आईएचएम ग्वालियर, आईएचएम श्रीनगर, आईएचएम हाजीपुर और आईएचएम लखनऊ को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

स्वच्छता अभियान 2025 के छायाचित्र

माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निर्देशानुसार, पर्यटन मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के अंतर्गत, मंत्रालय के एसबीएम विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन और उसके आसपास स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान संचालित किया।

10.8 साइबर सुरक्षा

इस वर्ष, पर्यटन मंत्रालय ने "रेजिलिएंस फर्स्ट" दृष्टिकोण अपनाया है। यह कार्यनीति सामाजिक अभियांत्रिकी जैसे उन्नत खतरों से डिजिटल पर्यटन इकोसिस्टम की सुरक्षा के साथ-साथ महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।

1. कार्यढांचे के मुख्य स्तंभ

यह ढांचा संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार कार्यात्मक स्तंभों पर आधारित है:

- शासन और अनुपालन: यह डीपीडीपी अधिनियम 2023 के अनुरूप है और व्यक्तिगत पर्यटक डेटा को संभालने वाले विभागों के लिए "डेटा फिड्यूशियरी" संबंधी भूमिकाओं को सख्ती से लागू करता है।
    - सभी नए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए सीआईएसओ की निगरानी के तहत "सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन" को अनिवार्य करता है।
    - सीईआरटी-इन एम्पैनल्ड ऑडिटर्स द्वारा वर्ष में दो बार सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य है।

- घटना पर प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति:
    - रैनसमवेयर या डीडीओएस हमलों से त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) स्थापित करता है।
    - एनसीआईआईपीसी के समन्वय में त्रैमासिक साइबर मॉक ड्रिल आयोजित करता है।
- क्षमता निर्माण और जागरूकता:
    - कर्मचारियों और संबद्ध कार्यालयों के लिए "साइबर जागृत भारत" नामक जागरूकता अभियान संचालित करता है।

मंत्रालय का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के आधार स्तंभ के रूप में साइबर सुरक्षा को स्थापित करते हुए, वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय साइबर तत्परता सूचकांक में "परिपक्व (Mature)" रेटिंग प्राप्त करना है।

वर्ष 2025 के दौरान प्रमुख कार्यकलाप:

1. मंत्रालय के **आईसीटी अवसंरचना की व्यापक लेखापरीक्षा** एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया) के माध्यम से किया गया, जो नेटवर्क सहित सभी डिजिटल संसाधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक एसएंडटी स्वायत्त संस्था है और उनकी सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।
2. सीईआरटी-इन और एमईआईटीवाई के सहयोग से दिनांक 07 नवंबर, 2025 को साइबर हाइजीन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

10.9 भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)

10.9.1 प्रस्तावना

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1 अक्टूबर 1966 को निगमित आईटीडीसी देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगम यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। इस समय यह निगम परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थलों पर होटलों, रेस्टोरेंटों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, निगम पर्यटक प्रचार सामग्री के निर्माण, वितरण और बिक्री का कार्य भी करता है तथा पर्यटकों को ड्यूटी फ्री शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। निगम की इंजीनियरिंग से संबंधित परामर्श सेवाओं में भी उपस्थिति है और एसीईएस प्रभाग, साउंड एंड लाइट (एसईएल) शो लगाने के साथ-साथ केंद्र सरकार/विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अवसंरचना से संबंधित परियोजना कार्यों को संभालता है। अशोक ट्रैवल एंड टूर्स एक प्रभाग है जो विश्वसनीय किफायती सेवाओं के साथ टिकटिंग, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, टूर पैकेज और कार्गो संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है। निगम का अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है। अशोक इवेंट्स एक अग्रणी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी, कार्यशाला/सेमिनार तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हैंडल करती है।

इसके अलावा, आईटीडीसी ने पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के विकास में प्रतिबद्ध एवं प्रमुख भूमिका निभाई है और इसके माध्यम से यह क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। 2001 और 2002 में क्रमश: 19

होटलों और 1 अधूरी होटल परियोजना के विनिवेश के बाद आईटीडीसी ने अपनी शेष गतिविधियों को सुदृढ़ किया है और विविध सेवा उन्मुख कारोबारी गतिविधियां लेने के लिए अपने आप को पुनर्गठित किया है।

10.9.2 संगठनात्मक ढांचा:

कॉर्पोरेट स्तर पर वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में आईटीडीसी बोर्ड शामिल है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अध्यक्ष, (वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है)
- प्रबंध निदेशक
- दो कार्यात्मक निदेशक [यानी (1) निदेशक-वित्त और निदेशक-वाणिज्यिक एवं विपणन
- एक सरकार द्वारा नामित निदेशक और
- एक गैर सरकारी/स्वतंत्र निदेशक (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशको का पद रिक्त है)

निदेशक मंडल के अलावा, अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स, अशोक इवेंट्स, अशोक इंटरनेशनल ट्रेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स, अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, अशोक कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज और सोन-एट-लुमियर जैसे व्यावसायिक समूहों के प्रमुख हैं जिनकी सहायता कॉर्पोरेट विपणन और जनसंपर्क, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और लेखा, सतर्कता और सुरक्षा, प्रशासन, सचिवालय, राजभाषा आदि द्वारा की जाती है।

10.9.3 आईटीडीसी की सेवाओं का नेटवर्क

आईटीडीसी के वर्तमान नेटवर्क में अशोक ग्रुप के 4 होटल (जिनमें से 3 चालू हैं), 1 रेस्तरां, 4 संयुक्त उद्यम जिसमें से 1 होटल इकाई चालू है, 4 कैटरिंग आउटलेट, 3 यात्रा/परिवहन इकाईयां, बंदरगाहों पर 14 ड्यूटी फ्री दूकानें और एयरपोर्ट पर 1 ड्यूटी फ्री दूकान शामिल हैं।

10.9.4 सहायक कंपनियां

नीचे दिए गए विवरण में 05 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार चार सहायक कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में आईटीडीसी के 9.29 करोड़ रुपये के निवेश को दर्शाया गया है:

सहायक कंपनियां	आईटीडीसी का निवेश (रुपये में)
उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(इक्विटी शेयर) 1.19 करोड़ (वरीयता शेयर) 3.50 करोड़
रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.50 करोड़
पुदुचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.82 करोड़
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	1.28 करोड़
कुल	**9.29 करोड़**

10.9.5 पूंजी संरचना

इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

(आईएनडी एएस के अनुसार)	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अधिकृत पूंजी	150.00	150.00	150.00
प्रदत्त पूंजी	85.77	85.77	85.77
रिजर्व और अधिशेष	286.96	256.42	315.79
कुल मूल्य	372.49	341.95	401.33

10.9.6 शेयरधारिता का स्वरूप

आईटीडीसी एनएसई और बीएसई दोनों के साथ एक सूचीबद्ध है और तदनुसार बीएसई के अनुसार 05 दिसंबर, 2025 को इसका बाजार पूंजीकरण 4776.07 करोड़ रुपये और एनएसई के अनुसार 4789.79 करोड़ रुपये था। आज तक की स्थिति के अनुसार निगम की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 150.00 करोड़ रुपये और 85.77 करोड़ रुपये है।

शेयरधारिता का स्वरूप (05 दिसंबर, 2024 तक) निम्नानुसार है:

भारत सरकार:	87.03%
द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड:	7.87%
अन्य निकाय कॉर्पोरेट:	0.15%
योग्य संस्थागत खरीदार:	1.78%
सामान्य जन, कर्मचारी और अन्य:	3.17%

10.9.7 वित्तीय प्रदर्शन

पिछले पांच वर्षों के लिए निगम के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित प्रमुख आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
टर्नओवर	197.16	304.76	473.37	523.67	587.78
कर पूर्व लाभ	-24.04	7.95	82.08	104.23	100.84
कर पश्चात लाभ	-27.45	4.38	56.29	66.17	82.94

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक खातों को आईटीडीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया था और आईटीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29.00% लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है, जैसा कि 16 सितंबर, 2025 को आयोजित एजीएम में इसके शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

10.9.8 योजनागत स्कीमें

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी योजना के तहत आईटीडीसी को कोई अनुदान नहीं देता है। इसके आंतरिक संसाधनों आदि से, वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी परिव्यय का मूल बजट अनुमान 72.01 करोड़ रुपये है जिसमें केवल होटल संपत्तियों और अन्य डिवीजनों के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए 56.98 करोड़ रुपये शामिल हैं।

10.9.9 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत प्रदर्शन का मूल्यांकन डीपीई द्वारा किया गया और आईटीडीसी ने 100 में से 94.00 (उत्कृष्ट) अंक प्राप्त किए। वर्ष 2025-26 के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

10.9.10 आईटीडीसी तथा इसकी संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों की संपत्तियों के विनिवेश की स्थिति

भारत सरकार की चल रही विनिवेश नीति के अनुसार, संयुक्त उद्यम होटल की 3 संपत्तियों सहित 9 होटल संपत्तियां (अर्थात होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल; होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी; होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर; गुलमर्ग में अपूर्ण होटल परियोजना; होटल जनपथ, नई दिल्ली, होटल जयपुर अशोक, जयपुर, ललित महल पैलेस होटल, मैसूर; होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना एवं होटल दोनई पोलो अशोक, ईटानगर) अब तक संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं /सौंप दी गई हैं।

निम्नलिखित 3 होटल परिसंपत्तियों के विनिवेश हेतु वैकल्पिक तंत्र की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:

आनंदपुर साहिब की अपूर्ण परियोजना: वैकल्पिक तंत्र की स्वीकृति दिनांक 15 सितंबर, 2025 को डीआईपीएएम से प्राप्त हुई, जिसे पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 26 सितंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अंतिम समापन हेतु आईटीडीसी को सूचित किया गया।

होटल रांची अशोक, रांची: वैकल्पिक तंत्र की स्वीकृति दिनांक 30 जून, 2025 को डीआईपीएएम से प्राप्त हुई, जिसे पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अंतिम समापन हेतु आईटीडीसी को सूचित किया गया।

होटल जम्मू अशोक, जम्मू: वैकल्पिक तंत्र की स्वीकृति दिनांक 15 सितंबर, 2025 को डीआईपीएएम से प्राप्त हुई, जिसे पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 22 सितंबर, 2025 के माध्यम से अंतिम समापन हेतु आईटीडीसी को सूचित किया गया।

आईटीडीसी द्वारा निम्नलिखित परिसंपत्तियों के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है:

होटल नीलाचल अशोक, पुरी: राज्य सरकार को जेवी कंपनी में आईटीडीसी की 98% प्रदत्त इक्विटी पूंजी को खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है।

आईटीडीसी बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात, संपत्ति के मूल्य निर्धारण हेतु परामर्शदाता/मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए आईएमजी एजेंडा पर्यटन मंत्रालय में प्राप्त हुआ है तथा आईएमजी बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है।

होटल पांडिचेरी अशोक, पुदुचेरी: जेवी कंपनी में आईटीडीसी की 51% इक्विटी को राज्य सरकार को बेचने का निर्णय लिया गया है। होटल पांडिचेरी अशोक के मूल्य निर्धारण हेतु तकनीकी सलाहकार/मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए आईएमजी बैठक बुलाने संबंधी आईटीडीसी का प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

होटल अशोक, नई दिल्ली: हाल ही में नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालय और डीआईपीएएम के साथ आयोजित बैठक में होटल अशोक के परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर चर्चा की गई। यह विचार-विमर्श किया गया कि आगे की प्रक्रिया हेतु आईएमजी की स्वीकृति से एक अंतरराष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता (आईपीसी) की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में आईएमजी बैठक बुलाने हेतु मसौदा आईएमजी एजेंडा पर्यटन मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर: राज्य सरकार को आपसी सहमति से तय मूल्यांकन पर मौजूदा होटल कलिंगा अशोक को अपने अधिग्रहण में लेने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है तथा राज्य सरकार की और से उत्तर प्रतीक्षित है।

10.9.11 अशोक होटल समूह

द अशोक:

नई दिल्ली के डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के हृदय में भव्य रूप से स्थित होटल अशोक, वर्ष 1956 में स्थापना के बाद से ही आईटीडीसी की प्रमुख आतिथ्य सेवाओं की गरिमा और विरासत का प्रतीक रहा है। सुव्यवस्थित एवं हरियाली से घिरे इस होटल में कालातीत भव्यता और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है, जो गणमान्य व्यक्तियों, व्यावसायिक अग्रणीयों तथा अवकाश यात्रियों सभी को समान रूप से आकर्षित करता है।

550 सुसज्जित कक्षों, जिनमें 160 भव्य सुइट्स तथा एक आलीशान प्रेसिडेंशियल सुइट शामिल हैं, के साथ होटल अशोक उत्कृष्ट सौंदर्यबोध एवं उच्चस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक अद्वितीय आवास अनुभव प्रदान करता है। आवास के अतिरिक्त, यह होटल प्रतिष्ठित सम्मेलनों, उच्च-स्तरीय आयोजनों तथा भव्य समारोहों के लिए भारत के प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। इसके विशाल बैंक्वेट परिसर एवं प्रतिष्ठित कन्वेंशन हॉल निरंतर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को आकर्षित करते रहे हैं, जिससे होटल अशोक देश के आतिथ्य क्षेत्र में एक अग्रणी स्थल के रूप में स्थापित हुआ है, जैसा कि नीचे हाइलाइट किया गया है।

आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन किया गया। #एकपेड़मांकेनाम पहल में आईटीडीसी के अग्रणीयों से लेकर माली एवं उनके बच्चों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मातृत्व के सम्मान में पौधारोपण किया। संयुक्त राष्ट्र की थीम "बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन" के अनुरूप, इस आयोजन ने स्थायी पर्यटन एवं पर्यावरण-अनुकूल आतिथ्य के प्रति आईटीडीसी की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन 21 जून 2025 को होटल अशोक में किया गया। आईटीडीसी द्वारा एससीओपीई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में डीपीई, वित्त मंत्रालय तथा 25 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा एक प्रभावशाली एवं ऊर्जावर्धक योग सत्र का संचालन किया गया।

वर्ष भर होटल अशोक ने अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मत्स्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान फॉर डेमोक्रेसीज़ (प्राइड), बौद्ध कॉन्क्लेव 2025, एमआईएलएमईडीआईसीओएन 2025, तथा भारत पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन और भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन जैसे उद्योग निकायों के सम्मेलन शामिल हैं।

आईसीजीईबी, मोंटेनेग्रो दूतावास सहित अनेक वैश्विक संगठनों एवं राजनयिक मिशनों तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी उच्चस्तरीय बैठकों के लिए होटल अशोक को चुना। इसके अतिरिक्त, होटल ने वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, ईएसआईसी, एनएचएआई, भारतीय गुणवत्ता परिषद, सेल तथा अनेक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के महत्वपूर्ण आयोजनों की भी मेजबानी की।

चिकित्सीय सम्मेलनों की मेजबानी में अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए, होटल अशोक दिल्ली ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, सर गंगाराम अस्पताल, सीएसआईसीओएन 2025 तथा एमआईसीआरओसीओएन 2025 जैसे प्रमुख आयोजनों का स्थल रहा।

आवासीय मेज़बान के रूप में, होटल ने पद्म पुरस्कार के विजेताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं, पैरा-ओलंपिक दलों तथा प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया।

रेस्तरां में आयोजित विभिन्न कार्यकलाप/खाद्य महोत्सव निम्नानुसार हैं:

कॉफी शॉप में मैंगो खाद्य महोत्सव (16 जुलाई से 23 जुलाई 2025)

कॉफी शॉप में मॉनसून मेनिया खाद्य महोत्सव (25 अगस्त से 31 अगस्त 2025)

अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस के अवसर पर केक शॉप में विशेष पिकनिक हैम्पर्स

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉफी शॉप, द अवध, फ्रंटियर तथा केक शॉप में विशेष छूट

केक शॉप में विशेष राखी एवं तीज हैम्पर्स

फ्रंटियर रेस्तरां में खैबर-की-पेशकश फूड प्रमोशन (23 नवंबर से 4 दिसंबर 2025)

विदेशों में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सवों में सहभागिता:

शेफ प्रजित पी. कुमार एवं श्री नरेश ने अगस्त 2025 में ताजिकिस्तान में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में होटल अशोक का प्रतिनिधित्व किया।

होटल सम्राट एवं होटल अशोक से शेफ विकाश कुमार आनंद तथा श्री महबूब आलम ने अक्टूबर 2025 में कजाखस्तान में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में भाग लिया।

संसद भवन कैटरिंग यूनिट से शेफ चंदन कुमार एवं श्री अर्जुन कुमार लाल ने नवंबर 2025 में ट्यूनीशिया में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में भाग लिया ।

पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ:

श्री अमित गोठवाल, सीनियर सूस शेफ, ने फूड कनोसर्स इंडिया अवॉर्ड्स (जुलाई 2025) में एक्जीक्यूटिव शेफ ऑफ द ईयर 2024–25 का पुरस्कार प्राप्त किया।

श्री नवीन माथुर, शेफ डे पार्टी, ने सितंबर 2025 में आयोजित इनक्रेडिबल शेफ्स चैलेंज में लाइव पास्ता श्रेणी में रजत पदक प्राप्त किया।

सुश्री फिरदौस, छात्र प्रशिक्षु, ने सितंबर 2025 में आयोजित इनक्रेडिबल शेफ्स चैलेंज में केक डेकोरेशन श्रेणी में रजत पदक प्राप्त किया।

सुश्री सृष्टि, छात्र प्रशिक्षु, ने सितंबर 2025 में आयोजित इनक्रेडिबल शेफ्स चैलेंज में केक डेकोरेशन श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया।

श्री दमन प्रकाश, हलवाई, को 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित इंडियन कलिनरी फोरम एनुअल शेफ अवॉर्ड्स में मास्टर शेफ अवॉर्ड–इंडियन स्वीट्स प्रदान किया गया।

सुश्री हरप्रीत कौर, छात्र प्रशिक्षु, ने 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित इंडियन कलिनरी फोरम एनुअल शेफ अवॉर्ड्स में महिला स्टूडेंट शेफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया।

होटल अशोक ने अपनी आईएसओ प्रमाणन लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की तथा 7 अगस्त 2025 को आईएसओ 22000:2018 प्रमाणन प्राप्त किया, जो वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा के अधीन तीन वर्षों के लिए वैध है।

एनेक्स भवन की तृतीय तल पर स्थित 49 अतिथि कक्ष, जिन्हें पूर्व में आईआरएफसी द्वारा कार्यालय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा था, का वर्तमान में नवीनीकरण किया जा रहा है ताकि उन्हें पुनः अतिथियों के उपयोग के योग्य बनाया जा सके। होटल अशोक में ऐश्वर्या लॉन्स का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण कर उसे एक आकर्षक नए बैंक्वेट स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिसके लिए बुकिंग प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, होटल के टैक्सी स्टैंड क्षेत्र को एक अन्य बैंक्वेट स्थल में परिवर्तित किया जा रहा है।

<u>होटल सम्राट</u>:

होटल सम्राट जो दिल्ली के प्रतिष्ठित लैंडमार्क द अशोक के साथ सुंदर परिदृश्य वाले बाग के बीच स्थित है, फूलों से भरे आलिंद और खुले-आसमान के नीचे स्थित आंगन के चारों ओर निर्मित एक सुंदर संरचना है। इसके 255 सुव्यवस्थित और डीलक्स कमरों में डबल और साथ ही क्वीन साइज के बेड हैं, जहां से मेहमानों की मांगों को पूरा करते हुए चारों ओर उद्यान के फव्वारे और पानी के चैनल दिखाई देते हैं।

विशिष्ट समारोहों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में, यह होटल नियमित रूप से कौटिल्य हॉल, चाणक्य हॉल और पूल साइड लॉन सहित अपने बहुमुखी समारोह स्थलों पर सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और शादियों की मेजबानी करता है। इस वर्ष, होटल सम्राट ने अपने परिष्कृत नए एफ एंड बी आउटलेट "एट्रियम" का अनावरण किया, साथ ही मेहमानों

का अनुभव और दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अभिनव पाक संबंधी पेशकशों की एक श्रृंखला भी पेश की। होटल ने अगस्त में आयोजित अमृत उद्यान के उद्घाटन के एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक विशेष फूड स्टॉल भी स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया।

संपूर्ण वर्ष के दौरान, इस परिसंपत्ति ने यूपीएससी समूह, आईपीएस अकादमी समूह और रूसी दूतावास जैसे प्रमुख संस्थाओं/समूहों की मेजबानी की, साथ ही राष्ट्रपति भवन एवं पर्यटन मंत्रालय के सम्मेलन के दौरान कार्यक्रमों के लिए निर्बाध सहयोग भी किया। अपनी पाक-कला संबंधी उत्कृष्टता के लिए विख्यात, इस होटल ने विभिन्न व्यंजनों के स्वादिष्ट पैक्ड भोजन की आपूर्ति की और अशोक इवेंट्स और संस्कृति मंत्रालय को 3,000, 6,000 और 11,000 पैक्ड हाई-टी बॉक्स सफलतापूर्वक वितरित किए।

होटल सम्राट ने गलियारों, लॉबी और प्रवेश द्वार पोर्च के साथ-ही 48 अतिथि कमरों के नवीनीकरण को पूरा किया, जबकि आईएसओ के अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए चल रहे रसोई उन्नयन सहित अतिरिक्त 20 कमरों का नवीनीकरण जारी है।

होटल ने 12 सरकारी संगठनों के साथ वार्षिक दर अनुबंध भी किया, मेहमानों की प्राथमिताओं के अनुरूप रूम सेवा, बैंक्वेट और थाली की टैरिफ को संशोधित किया, ऑनलाइन चैनलों पर अपनीउपस्थिति को सुदृढ किया, और कमरे में भोजन के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए व्यंजनों और मॉकटेल की एक श्रृंखला पेश की।

अपने वैश्विक पहचान को बढाते हुए, होटल सम्राट ने गौरवपूर्ण रूप से कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित भारतीय खाद्य महोत्सव में भाग लिया, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पाक विरासत का प्रदर्शन किया गया।

होटल कलिंग अशोक:

1980 से प्रचालनरत, होटल कलिंग अशोक आईटीडीसी का एक प्रसिद्ध होटल है जो 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। भारत के सांस्कृतिक केंद्र, भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित यह होटल यात्रियों के लिए एक प्रमुख विकल्प है, जो आराम, सुविधा और सांस्कृतिक निकटता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है। प्रमुख परिवहन केंद्रों- सड़क, रेल और हवाई मार्ग के निकट इसके रणनीतिक स्थान होने के साथ, यह अवकाश पर आने वाले और व्यावसायिक आगंतुकों दोनों के लिए एक आदर्श बेस है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों से घिरा यह होटल घूमने और विश्राम के लिए एक आदर्श केंद्र है।

होटल कलिंग अशोक अपने विशाल और सोच-समझकर बनाए गए अवसंरचना के लिए जाना जाता है। इसकी विशाल लॉबी और पर्याप्त पार्किंग, जो कि भुवनेश्वर के केंद्र में एक दुर्लभ लक्ज़री है, व्यक्तिगत यात्रियों और बड़े समूहों दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। यह होटल अपनी प्रीमियम बैंक्वेट सुविधाओं के कारण सामाजिक और कॉर्पोरेट आयोजनों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। दो विशाल लॉन यानी कपिलाश और आंगन, जो क्रमशः (28,550 वर्ग फुट) और (44,350 वर्ग फुट) के हैं और क्रमशः 250 और 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले दो बैंक्वेट हॉल अर्थात कोणार्क और उत्सव हैं, जो सभी आकार के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करते हैं।

इस होटल में 32 कक्ष और 04 लग्सरीयुक्त सुइट्स हैं, जो अतिथियों को आरामदायक स्टे प्रदान करते हैं। एक रेस्तरां-सह-बार यानी फूलबनी में, जिसकी क्षमता 60 अतिथि की है, भोजन करना एक बहतरीन अनुभव देता है और स्वादिष्ट व्यंजनों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है। यह होटल बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के लिए भी एक पसंदीदा स्थान है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है।

इसके जारी नवीनीकरण कार्य का उद्देश्य होटल अपनी की अवसंरचना को उन्नत करना और अतिथि सेवाओं को बढ़ाना है। अपनी स्थिरता और लागत अनुकूलन प्रयासों के भाग के रूप में, होटल ऊर्जा की खपत को कम करने, दीर्घकालिक दक्षता में सुधार करने और पर्यावरण अनुकूल प्रचालन को बढ़ावा देने के लिए एक सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर रहा है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आईआईए) के सहयोग से एक डिजाइन संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें इस परिसंपत्ति के सौंदर्य संबंधी अपील को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस पहल का उद्देश्य लागत प्रभावी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करते हुए स्थानीय उड़िया कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प के तत्वों को शामिल करना है। प्रतिभागियों को रचनात्मक डिजाइनों का प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो ओडिशा की विरासत के साथ सामंजस्य स्थापित करने, स्थानीय शिल्प कौशल का उपयोग, स्थिरता में वृद्धि, अतिथि अनुभव में वृद्धि और होटल के आगामी विस्तार और परिचालन की आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं।

आईआईए के साथ यह साझेदारी होटल के आधुनिकीकरण, स्थिरता एवं विरासत संरक्षण के दृष्टिकोण के अनुरूप सबसे अभिनव, व्यावहारिक और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध डिजाइन को पहचान देने में मदद करेगी।

चक्रवात और कोविड-19 जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इस होटल ने अपनी सेवा और धैर्य के लिए भुवनेश्वर के लोगों से बहुत सम्मान पाया है। होटल कलिंग अशोक विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नवरात्रि, और दिवाली को मुख्य उत्सवों के रूप में मनाता है।

हैदराबाद हाउस:

हैदराबाद हाउस ने भारत की स्वतंत्रता के बाद से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और अन्य हस्तियों की मेज़बानी की है। तितली के आकार की यह इमारत शहर में महाराजाओं के लिए सभी शाही आवासों में सबसे प्रभावशाली थी। केंद्रीय गुंबद, चतुर्भुजाकार उद्यान, गोलाकार फ़ोयर और सीढ़ी, मेहराब और ओबिलिस्क के साथ, हैदराबाद हाउस मुख्य रूप से यूरोपीय वास्तुकला वाली आकृतियों को मुगल रूपांकनों के साथ जोड़ता है। भारत पर्यटन विकास निगम 1974 से हैदराबाद हाउस (जो विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है) में खानपान और रखरखाव सेवाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन एवं संचालन करता है।

हैदराबाद हाउस भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय विदेश मंत्री और माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक, हैदराबाद हाउस राजकीय भोज, विदेशी कार्यालय परामर्श,

द्विपक्षीय बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों का स्थल है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से, इस प्रतिष्ठान को विश्व के नेताओं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है।

इन विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, हैदराबाद हाउस राज्य मंत्री, विदेश सचिव, प्रोटोकॉल प्रमुख और विदेश मंत्रालय के अन्य सचिवों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की भी मेजबानी करता है। यहां से जेएनबी, साउथ ब्लॉक और मंत्रियों के आवासों जैसे अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और साउथ ब्लॉक में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इस वर्ष, आईटीडीसी ने विश्व के नेताओं के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की व्यवस्था की है, जिनमें न्यूजीलैंड के माननीय प्रधानमंत्री, चिली के माननीय राष्ट्रपति, अंगोला के माननीय राष्ट्रपति, पैराग्वे के माननीय राष्ट्रपति, फिलीपींस के माननीय राष्ट्रपति, फिजी के माननीय प्रधानमंत्री, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री, मंगोलिया के माननीय राष्ट्रपति और रूस के माननीय राष्ट्रपति के साथ-साथ हैदराबाद हाउस और प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध अन्य प्रतिष्ठित स्थलों पर आने वाले प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं।

विज्ञान भवन:

आईटीडीसी 1979 से विज्ञान भवन में एक प्रतिष्ठित वीवीआईपी खानपान इकाई का प्रबंधन कर रहा है। जो कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अधिकांश ऐसे कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उप राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। विज्ञान भवन में आईटीडीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की उत्कृष्टता, आथित्य और निर्बाध समन्वय के लिए हमेशा सराहना और प्रशंसा की गई है।

चालू वर्ष के दौरान, विज्ञान भवन की खानपान इकाई ने कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों और उच्च-स्तरीय बैठकों को सफलतापूर्वक हैंडल किया है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। इन सम्मेलनों का आयोजन विभिन्न प्रतिष्ठित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा किया गया, जिनमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज संघ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (गृह मंत्रालय), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, आयकर विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और कई अन्य सम्मानित संगठन शामिल हैं।

इन प्रमुख संस्थानों द्वारा जताया गया निरंतर विश्वास विज्ञान भवन में बेहतर गुणवत्ता वाली वीवीआईपी खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटीडीसी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

10.9.12 अशोक इवेंट्स

अशोक इवेंट्स अर्थात आईटीडीसी की कार्यनीतिक कारोबार इकाई एक अग्रणी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हैंडल करती है। अशोक इवेंट्स की मुख्य दक्षता विभिन्न सेवाओं के लिए पेशेवर सम्मेलन आयोजक के रूप में वन स्टॉप समाधान उपलब्ध कराने की है। इस प्रभाग ने इवेंट मैनेजमेंट में बेहतरीन तरीके से अपना स्थान बनाया है और इसकी उत्कृष्ट विशेषज्ञता के कारण सरकारी मंत्रालय, विभाग, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण इसके प्रमुख ग्राहकों की सूची में शामिल हैं। अशोक इवेंट्स सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पुरस्कार समारोहों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय की निर्दिष्ट एजेंसी है।

2025-26 (30 नवबंर, 2025 तक) के दौरान अशोक इवेंट्स डिवीजन द्वारा आयोजित किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "17वां सिविल सेवा दिवस" का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे।
- नीति आयोग द्वारा 24 मई, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक" का आयोजन किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थे।
- आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय **"संविधान हत्या दिवस 2025"** 25 जून 2025 को त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि, भारत के माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार के अन्य केंद्रीय मंत्री थे।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "आचार्य श्री विद्यानंद जी की 100वीं जयंती" के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री थे।
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 नवंबर, 2025 को आईजी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थे।
- **महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग** द्वारा 19 से 23 नवंबर, 2025 तक मुंबई के आजाद मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

- संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ज्ञानभारतम मिशन का आयोजन किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थें।
- 23 से 27 जुलाई, 2025 तक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अरियालुर जिले में ''राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती तथा दक्षिण पूर्व एशिया में उनके समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूर्ण होने और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत" के उपलक्ष्य में कार्य़क्रम का आयोजन किया गया है। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थे।
- वस्त्र मंत्रालय और ईपीसीएच द्वारा 07 अगस्त, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस" का आयोजन किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 7 से 8 जुलाई, 2025 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन सचिवों की बैठक आयोजित की गई।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "हर घर तिरंगा: बाइक रैली" का आयोजन किया गया और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "हर घर तिरंगा: कॉन्सर्ट" का आयोजन किया गया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 22 अगस्त, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय बैठक 2025: विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना" नामक कार्यक्रम तथा 23 अगस्त, 2025 को "द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025" नामक आयोजित किया गया।
- राजस्थान पुलिस द्वारा 13 से 21 अक्टूबर, 2025 तक जयपुर, राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 14-15 अक्टूबर, 2025 को होटल मैरियट, उदयपुर, राजस्थान में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- गृह विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 1 से 9 जुलाई, 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 1 से 6 नवंबर, 2025 तक छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में "नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया।
- गुजरात के केवड़िया में 1 से 15 नवंबर, 2025 तक "राष्ट्रीय एकता दिवस" के दौरान पर्यटन मंत्रालय पैविलियन।

- "राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य" में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 07 नवंबर, 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थे।
- उच्च न्यायालय द्वारा "वाणिज्यिक न्यायालयों के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय मंच की छठी पूर्ण बैठक" 08 नवंबर, 2025 और 09 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 08 नवंबर, 2025 और 09 नवंबर, 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 - सतत शहरी विकास और अभिसरण - विकसित भारत के शहरी भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार करना" नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एसईसीआई, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर, 2025 और 12 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2025 पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 13 से 16 नवंबर, 2025 तक सिक्किम के गंगटोक के पंगथांग में "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट-2025" का आयोजन किया गया।
- महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा 19 से 23 नवंबर, 2025 तक मुंबई के आजाद मैदान में "नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया।
- एनआईटी, दिल्ली द्वारा 19 नवंबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का 5वां दीक्षांत समारोह" आयोजित किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत की माननीया राष्ट्रपति** थीं।
- संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 22 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में "भारतीय कला महोत्सव - 2025" का आयोजन किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत की माननीया राष्ट्रपति** थीं।
- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 26 नवंबर, 2025 और 27 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "शताब्दी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।
- नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 28 से 30 नवंबर तक आईआईएम रायपुर में डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें **मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री** थे।

10.9.13 अशोक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (एआईटी)

आईटीडीसी का अशोक इंटरनेशनल ट्रेड (एआईटी) प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ड्यूटी फ्री शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। आईटीडीसी प्रमुख समुद्री बंदरगाहों के साथ साथ नए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अपने ड्यूटी फ्री व्यवसाय को समेकित करने का प्रयास कर रहा है। आईटीडीसी के ड्यूटी फ्री आउटलेट भारत के तटीय शहरों के आसपास क्रूज पर्यटन सृजित करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप हैं।

वर्तमान में, इस प्रभाग की 15 ड्यूटी फ्री दुकानें हैं, जिनमें से कामराजर, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, कांडला, मैंगलोर, विशाखापत्तनम, गोवा, पारादीप, काकीनाडा, कृष्णापटनम, कोचीन, वीओ चिदंबरनार और जेएनपीटी के समुद्री बंदरगाह पर 14 ड्यूटी फ्री दुकानें हैं और एएआई के विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ड्यूटी फ्री दुकान है, जिसे प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया था।

इस प्रभाग ने दिनांक 18 जुलाई, 2024 से विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय आगमन और प्रस्थान दोनों पर ड्यूटी फ्री दुकान का प्रचालन शुरू किया गया। ये ड्यूटी फ्री आउटलेट अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधा के रूप में काम करते हैं अंतरराष्ट्रीय और क्रूज यात्री की संख्या को बढ़ाने संबंधी भारत सरकार के विजन को भी मजबूत करते हैं।

एआईटीडी ने अच्छी बिक्री और लाभप्रदता कायम रखी है और यह बंदरगाहों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और यात्रा संबंधी रिटेल वाले स्थानों पर उत्पन्न होने वाले नए व्यावसायिक अवसरों का भी लाभ हासिल करना जारी रखेगा और स्थायी ड्यूटी फ्री दुकानों के छूट संबंधी अधिकारों के लिए बोली लगाएगा।

10.9.14 अशोक ट्रैवल एंड टूर (एटीटी)

आईटीडीसी का यात्रा प्रभाग अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (एटीटी), सरकारी मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, सीपीएसई, रक्षा बलों, अर्धसैनिक संगठनों और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विश्वसनीय यात्रा सहभागीदार के रूप में काम कर रहा है। एटीटी ने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में निरंतर विश्वसनीय, किफायती और अनुपालन यात्रा समाधान प्रदान किए हैं।

डिजिटल परिवर्तन - आईटीडीसी बुकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप

डिजिटल सशक्तिकरण के सरकार के विजन के अनुरूप, एटीटी एक **अत्याधुनिक यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन** - www.itdcbookings.com लॉन्च करने जा रहा है।

यह प्लेटफ़ॉर्म सभी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए शीघ्र टर्नअराउंड, पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए एक सरल वनस्टॉप समाधान प्रदान करेगा।

आईटीडीसी बुकिंग की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल होंगे: -

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन हवाई टिकटिंग
- सुरक्षित, वास्तविक समय के लेनदेन सहित एकीकृत भुगतान गेटवे
- सभी उपकरणों पर 24/7 एक्सेस (मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप)
- त्वरित बुकिंग पुष्टिकरण तथा स्वयं-सेवा यात्रा कार्यक्रम प्रबंधन
- 99% अपटाइम सहित सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स

विविध सेवा पोर्टफोलियो

- हवाई टिकटिंग के अलावा, एटीटी अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए निम्नलिखित को शामिल कर रहा है:-
- स्थल मार्ग का यात्रा समाधान: कैब, कोच, कारवां (अखिल भारतीय)
- रेल बुकिंग (जल्द ही शुरू की जाएगी)

परिचालन उत्कृष्टता

एटीटी ने अखिल भारतीय सेवाओं को सीधे और अपने पैनल में शामिल जीएसए के माध्यम सेजारी रखा है। प्रभाग ने मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की बड़े पैमाने पर यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें हवाई टिकटों से लेकर अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने संबंधी एंड-टू-एंड समाधान सुनिश्चित किए जाते हैं।

कार्यनीतिक महत्व

एटीटी का आधुनिकीकरण एक समग्र यात्रा एवं आतिथ्य समाधान प्रदाता के रूप में आईटीडीसी की स्थिति को सुदृढ करता है। डिजिटल नवाचार के साथ विरासत वाले विश्वास को जोड़कर, एटीटी सार्वजनिक क्षेत्र के यात्रा प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और सेवा उत्कृष्टता के सरकार के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है।

10.9.15 कॉर्पोरेट विपणन और जनसंपर्क प्रभाग

कॉर्पोरेट विपणन और जनसंपर्क प्रभाग ने आईटीडीसी की संस्थागत छवि को मजबूत करने की दिशा में अपने केंद्रित प्रयासों को जारी रखा है, इस अवधि के दौरान, इस प्रभाग ने #wholeofCPSE पहल के तहत स्कोप के सहयोग से प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागीदारी के साथ एमडीएनवाईआई के प्रशिक्षकों द्वारा एक विशेष सत्र और #एक पेड़ मां के नाम अभियान के विषय पर आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह शामिल थे, जिसमें बागवानों एवं उनके बच्चों ने आईटीडीसी की इकाइयों में पौधे लगाए। सभी प्लेटफार्मों पर लक्षित

सोशल मीडिया प्रचारों के माध्यम से डिजिटल आउटरीच को काफी आगे बढ़ाया गया, जिससे संपर्क बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग स्वरूपों का लाभ लिया गया। प्रमुख पहलों में #KitchenFlash (आईटीडीसी शेफ द्वारा टिप्स एंड हैक्स), #VoicesofAITM, आईटीडीसी के 60 वर्ष एवं अशोक के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मारक लोगो और "हर घर तिरंगा" अभियान का विस्तार शामिल है। एमआईसीई, वेडिंग की दृश्यता बढ़ाने तथा आईटीडीसी के होटलों एवं रेस्तरां को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जारी #ITDCIndiaLegacy अभियान ने प्रभावशाली डेटा स्टोरीटेलिंग के माध्यम से आईटीडीसी के संस्थागत विकास को प्रदर्शित किया।

आईटीडीसी के वाणिज्यिक कार्यक्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रभाग ने, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर और मुख्यधारा की मीडिया आउटरीच को एकीकृत करते हुए एक व्यापक विपणन कार्यनीति को अपनाया है। खाद्य और जीवनशैली संबंधी इंफ्लुएसरों के साथ सहयोग से यूवा डिजिटल दर्शकों के बीच अनुभव साझा करने, प्रामाणिक समीक्षाओं और व्यापक दृश्यता को बढावा मिला। डीडी मॉर्निंग शो में 'नवरात्र थाली' के लिए डीडी नेशनल द्वारा एक विशेष फीचर के माध्यम से मीडिया कवरेज को सुदृढ किया गया, साथ ही प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रचार किया गया। एमआईसीई पेशकश, डेस्टिनेशन वेडिंग और आतिथ्य सेवाओं के लिए कार्यनीतिक प्रचार ने ब्रांड की स्थिति को और मजबूत किया और व्यवसाय सृजन में योगदान दिया। सामूहिक रूप से, इन प्रयासों ने ब्रांड रिकॉल को मजबूत किया और आईटीडीसी के सेवा पोर्टफोलियो की बाजार में उपस्थिति को बढ़ाया।

जनसंपर्क प्रयासों का उद्देश्य कार्यनीतिक संचार और व्यापक दृश्यता पहलों के माध्यम से आईटीडीसी की ब्रांड प्रतिष्ठा को सुदृढ करना था। मौसमी और प्रासंगिक सामग्री जैसे त्योहारों के व्यंजन, राष्ट्रीय दिवस समारोह एवं रचनात्मक लेख नियमित रूप से प्रिंट किए गए और डिजिटल पोर्टलों और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रसारित किए गए, जिससे विभिन्न लक्षित दर्शकों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित हुई। इस प्रभाग ने राष्ट्रीय उद्योग मंचों और हितधारक प्लेटफार्मों पर आईटीडीसी की उपस्थिति को निरंतर बढ़ाया। कुल मिलाकर, समन्वित जनसंपर्क और विपणन संबंधी पहलों ने नियमित रूप से एवं सकारात्मक ब्रांड सुदृढीकरण में योगदान दिया, जिससे पर्यटन मंत्रालय के तहत आईटीडीसी के व्यापक विजन और मिशन को सहयोग मिला।

10.9.16 अशोक परामर्श और अभियांत्रिकी सेवाएं

अभियांत्रिकी और एस्टेट प्रभाग आईटीडीसी के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक है। इस प्रभाग में अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों का एक पूल है जो पूरे भारत में प्रतिष्ठित पर्यटन और सांस्कृतिक अवसंरचना परियोजनाओं की अवधारणा, योजना निर्माण तथा वितरण के लिए अग्रिम रूप से कार्य कर रहे हैं। इस टीम ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के दूरदराज क्षेत्रों में कार्य किया है। इस प्रभाग के पास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं भारत में पर्यटन और अन्य अवसंरचना विकास परियोजनाओं के निष्पादन में पांच दशकों से अधिक का अनुभव है।

यह प्रभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजनाओं की तैयारी।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के तहत पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं।

आईटीडीसी होटल इकाइयों (अशोक होटल, सम्राट होटल और होटल कलिंग अशोक) और अन्य सभी आईटीडीसी परिसंपत्तियों का नवीनीकरण और मरम्मत संबंधी रखरखाव के कार्य।

पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न राज्यों में एएसआई संरक्षित स्मारकों के प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) सहित साउंड एंड लाइट शो/मल्टीमीडिया शो का कार्यान्वयन।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में डीपीआर तैयार करना और परामर्श सेवाएं, बहुआयामी शो, विषयगत/वास्तुशिल्प संबंधी प्रकाश व्यवस्था और प्रदीप्तीकरण करना।

पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न राज्यों में प्रमुख स्मारकों के अग्रभाग की प्रकाश व्यवस्था/ प्रदीप्तीकरण का कार्यान्वयन।

वर्तमान में, यह प्रभाग सीएफए योजना के तहत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रतिष्ठित एसईएल शो और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नवल सागर झील, बूंदी (राजस्थान) में म्यूजिकल फाउंटेन एंड वाटर स्क्रीन मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन शो का आयोजन कर रहा है। यह प्रभाग लेह पैलेस और कारगिल (लद्दाख), सरखेज रोजा (अहमदाबाद), उदयगिरी खंडगिरि गुफाएं (भुवनेश्वर) और पुराना किला (नई दिल्ली) में मल्टीमीडिया परियोजनाओं सहित प्रमुख एसईएल शो को भी हैंडल कर रहा है।

हाल ही में, इस प्रभाग ने संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को रोशन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें मध्य प्रदेश में खजुराहो, महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं, कर्नाटक में हम्पी और गुजरात में धोलावीरा शामिल हैं।

10.9.17 पर्यावरण प्रबंधन पहल

आईटीडीसी ने एसटीपी/ईटीपी, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा, जैविक अपशिष्ट परिवर्तक और अन्य ऊर्जा संरक्षण उपायों सहित विभिन्न पर्यावरण के अनुकूल पहलों को लागू किया है। अशोक और सम्राट होटल्स में एक एमएलडी एसटीपी है, जबकि भुवनेश्वर में होटल कलिंगा अशोक में 30 केएलडी एसटीपी/ईटीपी है। जैविक कचरे को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नई दिल्ली के अशोक और सम्राट होटलों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में होटल सम्राट को फरवरी 2024 से यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा एलईईडी गोल्ड प्रमाण पत्र दिया गया है।

10.9.18 अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान

वर्ष के दौरान, आईटीडीसी के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचटीएम) ने कार्यक्रमों के एक संरचित कैलेंडर के माध्यम से संगठनात्मक दक्षताओं को सुदृढ करना जारी रखा। प्रमुख पहलों में खाद्य और पेय सेवा, खाद्य उत्पादन, फ्रंट ऑफिस और आईटीडीसी कर्मचारियों के लिए हाउसकीपिंग के साथ-ही मॉकटेल प्रदर्शन, आरटीआई कार्यशाला, ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और आईजीओटी कर्मयोगी जैसे विशेष मॉड्यूल शामिल थे। एआईएच एंड टीएम ने नए नियुक्त सहायक प्रबंधकों, एसीएस और काउंटर सहायकों के लिए इन्डक्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए एवं इकाइयों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसके अलावा, प्रभाग ने एंटी रैगिंग सप्ताह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, पर्यटन हितधारकों के जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता कार्य योजना सहित महत्वपूर्ण संस्थाग कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान की, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जैसे बाहरी संगठनों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण भी प्रदान किया। ए.आई.एच.टी.एम. राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा और जेएनयू, नई दिल्ली के साथ बी.एससी (आथित्य एवं होटल प्रशासन) और एनआईओएस के साथ फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी में भी डिप्लोमा चलाता है।

यह प्रभाग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत आरडीएटी के साथ संबद्ध आईटीडीसी के होटल प्रभाग के सहयोग से संरचित शिक्षुता कार्यक्रमों को भी निष्पादित करता है, जिससे कौशल विकास एवं नौकरी के साथ सीखने में सहयोग किया जाता है। इन पहलों के माध्यम से, एआईएचटीएम ने आईटीडीसी में सेवा उत्कृष्टता बढ़ाने और कुशल मानव की संख्या को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है।

10.9.19 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल सीएसआर उत्तर दायित्व 132.19 लाख रुपये का था और वर्ष के दौरान कुल व्यय 133.00 लाख रुपये का रहा। बोर्ड की मंजूरी के बाद, सीएसआर निधि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया गया।

आईटीडीसी हर समय सामाजिक, आर्थिक और स्थायी तरीके से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगा जो पर्यावरणीय स्थिरता की ओर उन्मुख जाती हैं। आईटीडीसी उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा जो उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद हैं।

10.9.20 मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष 2024-25 (01 दिसंबर, 2025 तक) के लिए आईटीडीसी की कुल जनशक्ति की संख्या 422 है जिसमें 159 एक्जीक्यूटिव और 263 गैर-एक्जीक्यूटिव शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 101, अनुसूचित जनजाति के 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 54 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, कुल जनशक्ति की संख्या में से 62 महिला कर्मचारी हैं। आईटीडीसी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनी हुई है।

10.9.21 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

वर्ष के दौरान आईटी प्रभाग द्वारा किए गए प्रमुख पहल निम्न प्रकार हैं:

- एटीटी एयर टिकटिंग के लिए नया यात्रा पोर्टल अंतिम चरण में है।
- एनआईसी ई-मेल सेवा को नए ईमेल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- अलग-अलग वेटेज के साथ मौजूदा एचआरएमएस में कई मूल्यांकन शुरू किए गए हैं।
- ड्यूटी फ्री शॉप प्रबंधन के लिए नए सॉफ्टवेयर के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- एटीटी ट्रैवल पोर्टल के लिए एआई आधारित चैटबॉट की पेशकश का अध्ययन किया जा रहा है।
- अशोक और सम्राट के लिए नवीनतम तकनीक के साथ वाई-फाई सेवाएं प्रक्रियाधीन हैं।
- मूल्यांकन के लिए ई-स्पैरो की पेशकश की प्रक्रिया जारी है।
- नए केंद्रीकृत पीएफ और पेरोल मॉड्यूल की पेशकश की प्रक्रिया जारी है।

*****

सत्यमेव जयते

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

Incredible India

@tourismgoi @tourismgoi ministryoftourismgoi tourism.gov.in